श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : महोदय, मैं इस विषय के साथ associate करता हूं।

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला (गुजरात) : उपसभापति जी, मैं भी अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री वी.पी. सिंह बदनौर : सर, मैं भी इस विषय के साथ associate करता हूं।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी (गुजरात) : उपसभापति महोदय, मैं भी इस विषय के साथ associate करती हूं।

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will start further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. As per the list, the next speaker is Mr. Baishnab Parida. But, I have a special request from Shri Brajesh Pathak, whose name comes only in the end. He has to leave early to attend some important engagement. Hon. Members, with your permission, I would allow him to speak now. Mr. Brajesh Pathak, please speak.

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य रेणुका चौधरी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रसताव पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक ऐसी राजनैतिक, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन सरकार के पूरे साल-भर के कार्यों के लेखा-जोखा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है। लगभग सभी मुद्दों पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सरकार के बढ़ते हुए कदमों का जिक्र किया है, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना करते समय सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश के अंदर समान शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, तब तक देश उस गति से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा, जिस गति की आज जरूरत है। पूरे देश के पैमाने पर विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है। कक्षा ज़ीरो से लेकर कक्षा बाहर तक - चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो - अलग-अलग पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर, इंटरमिडिएट पास करके आते हैं और बड़े लोगों के बच्चे, शहरों के बच्चे Montessori पद्धति के स्कूलों में, अंग्रेजी पद्धति के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, प्राइमरी स्कूलों में, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, व्यवस्था

यह है कि उनमें सीधे कक्षा-एक में प्रवेश मिलता है। दूसरी ओर Montessori और अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में प्रेप या लोअर केजी, अपर केजी के बाद कक्षा-एक में प्रवेश मिलता है। प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से हिन्दी माध्यम की शिक्षा देने के बाद छठी कक्षा में अंग्रेज़ी के अक्षर सिखाने का काम किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज़ी पद्धति में कक्षा ज़ीरों से ही अंग्रेज़ी के अक्षर सिखाकर उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। सर, देश में और विश्व में विज्ञान कितनी ही प्रगति कर ले, लेकिन हम यह तय नहीं कर सकते कि फलां बच्चा किस घर में पैदा होगा। बच्चा किस घर में जाएगा, यह दायित्व तो आज तक कोई तय नहीं कर सका, लेकिन देश में चुनी हुई सरकार का यह कर्त्तव्य है, यह दायित्व है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही लिखा है, सभी को समान अवसर देने होंगे। सर, बच्चे का लालन-पालन कैसे हो, उसके रहने और खाने के प्रबंध में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन हमें उनके लिए कक्षा ज़ीरो से लेकर कक्षा बाहर तक समान शिक्षा नीति इस देश में लागू करनी होगी, तभी हम इस देश को प्रगति के रास्ते पर ला सकते हैं। इसके लिए हमारी केन्द्र की सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल प्रस्तुत किया और सौभाग्य से वह बिल पास भी हुआ। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिल को पास कर दिया और उसे राज्यों पर छोड़ दिया, पूरा पैसा न देकर उसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी आपने तय की है। राज्यों पर छोड़ने के कारण अभी तक यह बिल धरातल पर लागू नहीं हो सका है। हमारा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जब भी माननीय मंत्री जी जवाब दें, जब अभिभाषण का जवाब दें तो इस बात का उल्लेख जरूर करें कि राज्यों की हिस्सेदारी का जो सवाल छोड़ा गया है, उसके बजाय पूरा पैसा देकर हम बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध क्यों नहीं कर सकते, जबकि शिक्षा हमारे मूल अधिकारों में आता है? एक शेर के माध्यम से किसी विद्वान ने कहा है:

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो कतरा-ए-खूं निकला।

महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें एक समेकित स्वास्थ्य योजना बनानी होगी। आज इस देश के अंदर भुखमरी से मरने वालों की संख्या उतनी नहीं है, जितनी उचित समय पर अच्छी चिकित्सा न मिलने पर मौतें होती हैं। इसलिए सभी को उचित समय पर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था मिले, इस बात का भी प्रयास हमें करना होगा।

महोदय, इस देश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर नए कानून बनाए गए, नयी योजनाएं बनायी गयीं। एसईजेड का भी डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया, जमीनें अधिकृत की गयीं। महोदय, व्यापारियों और उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए तो योजनाएं बनीं - इस देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां बनीं, वे गरीबों के बजाय, आम आदमियों के बजाय उद्योगपतियों के लिए, जो इस देश के केवल दस प्रतिशत लोग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बनीं।

[श्री ब्रजेश पाठक]

सर, जिस ढंग से आज तक व्यापारियों को, उद्योगपतियों को सहूलियतें दी गईं, उस ढंग से किसानों के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनी। मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सभी सरकारें सिंगन विंडो सिस्टम बनाती हैं, वहां पर उनकी custom, excise, sales tax, income tax, बिजली और पानी के कनेक्शन से संबंधित कामों को एक काउंटर पर, एक जगह अधिकारियों को बैठाकर हल किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए विशेष रूप से आज तक कोई इंतजाम इस तरह के नहीं किए गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि किसानों के लिए भी हमें विशेष रूप से कुछ इंतजाम करने चाहिए, जिससे उनको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

सर, आये दिन हम इस बात को सुनते हैं कि खाद पर सब्सिडी कम की जा रही है, बिजली का रेट बढ़ रहा है और किसानों को बिजली समय पर नहीं मिलती है। किसान जो खाद्यान्न उत्पादित करता है, उसका मूल्य तय करने का अधिकार किसान को न होकर राज्य या केन्द्र की सरकार को होता है। जबकि, दूसरी तरफ जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो उद्योगपति हैं, वे कोई सामान बनाते हैं, तो उसका लागत मूल्य निकालकर, लाभ बढ़ाकर उसको बाजार मूल्य पर बेचने का अधिकार उनका स्वयं का है और किसानों के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए एक राष्ट्रीय मूल्य नीति बने, जिससे कि उन लोगों पर कंट्रोल हो सके जो जीवनोपयोगी वस्तुओं के अचानक दाम बढ़ाकर आम लोगों का शोषण करते हैं और दूसरी तरफ किसानों के लिए ऐसे इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं और किसानों को सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अंत में जब किसान अपने उत्पादित खाद्यान्न का उचित मूल्य नहीं पाता है, तो वह आत्म-हत्या करने पर मजबूर हो जाता है।

सर, शहरी गरीबों के बारे में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। शहरी गरीब वे लोग हैं, जो दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े-बड़े शहरों में या छोटे-छोटे शहरों में रहते हैं। वे बड़े-बड़े लोगों की बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े-बड़े लोगों के घर सुसज्जित करते हैं, वे सड़कें बनाते हैं और लेबर के रूप में झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। आज एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि हमारे पास आवास की कमी नहीं है और वह पर्याप्त मात्रा में गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। सर, मुझे आंकड़े देखकर महसूस होता है कि यह माननीय मंत्री जी का सही भाषण नहीं है। आज जो हालत है, उसमें शहरी गरीबों को कोई व्यवस्था ठीक से उपलब्ध नहीं है। आये दिन लोकल नगरपालिकाएं, एमसीडी, एनडीएमसी गरीबों की झोपड़ियों को उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। सर, मैं आपके माध्यम से इसके लिए अपनी बहन कुमारी मायावती जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में, जो आबादी के हिसाब से देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर सभी शहरों में, जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में गरीबों को दो कमरे का मकान बनाकर नि:शुल्क देने का काम किया है, यह कार्य मान्यवर कांशीराम शहरी योजना के माध्यम से किया

गया। इस योजना को अगर पूरे देश में लागू किया जाए, तो वास्तव में झुग्गी-झौपड़ी मुक्त देश बना सकते हैं।

सर, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं पिछली दफा लोक सभा का सदस्य था, तो स्लम फ्री हिन्दुस्तान की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की थी, लेकिन आज तक यह योजना कागज से धरातल पर नहीं उतरी है। यह योजना केवल कागज पर ही रह गई है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि मान्यवर कांशीराम शहरी योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैलाकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मकान बनाकर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गरीबों को मकान दे सकते हैं और स्लम फ्री इंडिया का जो नारा है, उसको सफल बना सकते हैं।

सर, सबसे बड़ा मसला इस देश के अंदर वामपंथी उग्रवाद का है, नक्सलाइट मूवमेंट का है, बाहरी तत्वों द्वारा हमारे देश को चुनौती मिलने का है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में वामपंथी उग्रवाद का जिक्र किया, बाहरी तत्वों द्वारा, विदेशी ताकतों द्वारा हमारे देश को अस्थिर किए जाने की बात का भी जिक्र किया। सर, इस देश के अंदर उन लोगों के बारे में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया, जो उन्मादी तत्व हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर, इस देश के भोलेभाले लोगों पर, प्रदेश के भोलेभाले लोगों पर हमला करते हैं। वे ग्रेनेड और ए.के. 47 जैसे बड़े-बड़े हथियार लेकर कत्लेआम करते हैं। सर, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ऐसा सबके सामने होता है, उनको सम्मानित करके हम संसद और विधान सभा में भेजने का काम करते हैं।

कई पार्टियां उनको सम्मानित करके संसद में भेजती हैं तथा राज्यों में सरकारें बनती हैं। महोदय, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इस देश में जिनको कई प्रदेशों की पुलिस, पैरा मिल्ट्री फोर्सेज़ खोजती थीं, उन लोगों को भी संसद में भेजकर संविधान की गरिमा को धब्बा लगाया गया है। सर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना की थी, यह सब देखकर आज वे क्या सोच रहे होंगे। यह सोच कर हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है कि संसद के सामने, आप लोगों के सामने बाबा साहेब के संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भाषण में कोई जिक्र नहीं है।

सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब-जब इस देश में चुनाव का महाकुंभ होता है, चुनाव में चुनी जाने वाली पार्टियां लोक लुभावन वायदे करती हैं। जिस प्रकार बाजीगर ढोल, नगाड़े बजाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने जादू का प्रभाव डालते हैं, ठीक उसी प्रकार चुनाव में पार्टियां ऐसे वायदे करती हैं, जिनसे जनता उनके बहकावे में आ जाती है, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, लेपटॉप हो, फ्री बिजली-पानी हो या कोई अन्य चीज देने की घोषणा हो। जब उन पार्टियों की सरकारें बन जाती हैं तो वे जनता के साथ किए गए सभी वायदे भूल जाती हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हुए एक वर्ष

[श्री ब्रजेश पाठक]

बीत गया है। वहां की सरकार ने अपने घोषण-पत्र में वे सब बातें लिखी थीं, जो ऊपर कही गई हैं। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा होता है तो वह सभी कुछ देने का वायदा करता है। यदि उसे डूबने से बचा लिया जाए तो वह सर्वस्व दान कर देगा। ऐसी सरकारें जनता के इम्तिहान में पूरी तरह से फेल होती हैं। उत्तर प्रदेश में आज खूनी तांडव खेला जा रहा है। वहां पांच हजार से अधिक हत्याएं हो चुकी हों, ढाई हजार से अधिक बलात्कार हो चुके हैं, हजारों की संख्या में डकैतियां हो रही हैं और आम आदमी का सिर शर्म से झुक जाता है। एक आम आदमी जब अखबार पढ़ता है तो उसको उत्तर प्रदेश में रहने लायक माहौल नहीं दिखता है और वह पलायन करने पर मजबूर हो जाता है।

महोदय, हाल ही में कुंडा के प्रतापगढ़ जिले में एक घटना घटी है। वहां के एक नौजवान पुलिस उपाधीक्षक की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करके उसकी लाश को घसीटा गया, उसकी वर्दी फाड़ी गई और जो भी उसके साथ हुआ महोदय, वह आप से छुपा नहीं है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने इस घटना पर राज्य सरकार से जबाव मांगा है, किन्तु संविधान की धारा 356 का उपयोग करके ऐसी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर केन्द्र सरकार मौन है। इस पर अपने जबाव में माननीय मंत्री जी को कुछ न कुछ अवश्य कहना चाहिए।

सर, मैं एक शेर के माध्यम से ऐसी सरकार के बारे में कहना चाहूंगा:

सितमगर तुझसे उम्मीदें करम होंगी जिन्हें होंगी।
हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है।।

सर, यह सब इसलिए हो रहा है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं और उनमें जो लोग हैं, उनका संवैधानिक व्यवस्था में कुछ लेना-देना नहीं है। जिनको पुलिस ने एनकाउंटर में मारा गिराया, महोदय, जो 25-25 वर्षों से अपराध के क्षेत्र में डंका बजा रहे थे, जिनको कई प्रदेशों की पुलिस खोज रही थी, उनकी ही महिमा मंडित करके विधान सभा तथा संसद में भेजने का काम किया गया। इस पर भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है।

सर, अंत में मैं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के अपराधियों द्वारा मारे गए पुलिस उपाधीक्षक स्व. जिया-उल-हक जी को श्रद्धांजलि करता हूं और सदन में उपस्थित सभी साथियों से तथा आप से अनुरोध करता हूं कि जिआ-उल-हक जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ, अपने स्थान पर खड़े होकर, दो मिनट का मौन रखने का कष्ट करें।

सर, मैं आप से यह भी अनुरोध करूंगा कि जिया-उल-हक जी के परिवार को एक संवेदनापत्र, अपने माध्यम से भेजकर उस आत्मा की शांति के लिए अपील करें, जिसने इस कष्ट को भोगा

है। इससे हमें भी आत्मिक शांति मिलेगी कि आपने हमारी बात सुनी। सर, इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक कवि ने कहा है कि

"हो चुकी पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से, एक नई गंगा निकलनी चाहिए।"

जय भीम, जय भारत।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, the hon. President's Address does not mention about the great problems our country or our society is facing, that is, corruption, black money, price rise and slow economic growth. They are affecting the entire nation. At the same time, the democratic system which has been adopted by our nation is gradually declining and negative signs are emerging every day. That is why, I am not in a position to support the hon. President's Address which was ceremonially placed before the Joint Session of both the Houses. Sir, the President's Address which reflects the present Government's so-called achievements and future plans does not tally with the grassroot-level reality. The UPA has completed nine years. During this period, they announced policies and implemented them. After nine years, the growth rate has come down. It has come down from 8.4 per cent to 5 per cent. This is in the economic sphere. There is every apprehension that it will decline to even lower levels in the coming years. Sir, throughout the country, there is despair and frustration and it is becoming more rampant and more strong among the farmers, workers, youths and women. Sir, agriculture is the largest job creating sector in our country. About 67 per cent of our population is engaged in it. But, agriculture is not progressing at the pace as it is required to be. Number of farmers' deaths is increasing. In the name of loan waivers, thousands of crores of rupees are being misused and misappropriated, which has been exposed by the CAG Report. Agriculture is not in a position to generate new employment opportunities. Lack of storage facilities and increasing prices of fertilizers are creating problems for the farmers. Mass migration from agriculture sector is taking place every year. In 2005, agriculture absorbed 258 million people. But in 2010, the number was reduced to 244 million people. These 14 million jobs have not been added to the manufacturing sector. Sir, about 14 million people have migrated from the agriculture sector. But there is no scope in the industry or in the manufacturing sector to absorb them. Job opportunities in India are, actually, declining alarmingly. India has lost five million jobs in this five year period, that is, from 2005 to 2010. According

[Shri Baishnab Parida]

to the Planning Commission's Report, Indian manufacturing sector, that is, micro, small and medium enterprises have been reducing in number. From 2004-2005 to 2009-10, employment in manufacturing sector declined from 55 million to 50 million.

There is about 9 per cent employment lost. It happened due to the automation technology that we have adopted and which has lowered the demand for labour. This country needs to develop infrastructure like China to attract industry. There is a lot of opportunity for creating jobs in the manufacturing sector in our country. The Planning Commission figures reveal that in other emerging economies like China, Brazil and South Africa, the manufacturing sector has grown much faster than their GDP. China has been successful in transferring 150 million people from agriculture to manufacturing sector. It should be a lesson for us. The industrial sector is also not expanding due to the contradictory policy of the Central Government. The Ministry of Industry is giving sanctions for opening factories in different parts of the country. But due to a lot of complications in the Ministry of Environment and Forests, industries are not coming in time, and the same thing happened in the case of Posco in Odisha which is to be the biggest FDI investment in India. For the last six-seven years, things are just lagging unimplemented there and new problems are coming up daily.

There is no indication to create new jobs for the youths of our country. In the Presidential Address, it is said that the Government is very much concerned with the interests of the youths. But, actually, every year, we are creating millions of jobless youths, unemployed youths, and, at the same time, we are not creating any employment opportunities for them. As a result, they are getting frustrated and some sort of cynicism is developing in them, and they are becoming anti-social.

Then, Sir, there is a vast poverty in our country. To eradicate poverty, the Government has started a lot of social welfare programmes. But we are not giving much importance to develop the skill of the poor, the landless labourers, the youth of the villages in a productive way. We are giving some doles to them in the name of preventing starvation deaths. Sir, though it is very essential to prevent starvation deaths and nobody should remain starved in our country, yet, at the same time, we must create new opportunities, we must develop their skills to utilize their labour power to make them self-sufficient. That will help the country. But by giving doles, we can't remove poverty in our country. It will perpetuate poverty.

1.00 P.M.

Then, Sir, I come to the issue of corruption. Every day, a tsunami of scams is coming in the newspapers. Few years back, the Bofors scam had shook the entire country and its system. But the number of Bofors-like scams is growing every day and it has become a menace for the country. Sir, there is a need to check corruption. When I talk about corruption, I am not talking about the corruption prevalent in high places only, but I am also talking about the corruption that has spread from Delhi to local level Panchayat offices, the Collector, Tehsil, Block Office, etc. Starting from Secretariat level, it has spreaded to the village level. There is corruption everywhere. Unless you give the PC, percentage of commission, unless you give bribe, you can't get a caste certificate; a bed in the hospital; you can't get an Indira Abas or — a BPL Card. Sir, corruption has become a menace and it must be curbed. It is killing the spirit and the very morality of our society. That must be stopped. Sir, our democratic system is gradually declining now everyday.

Even political parties are losing their credibility in the eyes of the public. It is not only the ruling party but the entire polity of this country that is losing its credibility. Corruption and the way we are running this Government are harming the credibility of the entire political system.

Sir, we had introduced the Panchayat system in order to decentralize power, but now you would see that every village is divided and there are hundreds of cases of fighting, firing, etc. In a Panchayat, even a Sarpanch or a *Zilla Parishad* member spends lakhs of rupees to get himself elected. Contractors and corrupt businessmen provide funds to get him elected. Corruption has entered even into Panchayat system. So, now, instead of decentralizing political power, we have decentralized corruption; the corrupt system has travelled from Delhi, Bhubaneswar to my village. The village was peaceful, but now corruption has entered there. Mr. Mani Shankar Aiyar, who was the architect of the Panchayati Raj system, is not here. I would request my friends to be very serious about this issue, otherwise, the whole system would collapse. Once Hitler had said, "there is rampant corruption and frustration. I am here to save you." So, somebody like Hitler might appear on the scene or some fundamentalist or anti-democratic forces would say, "This system is now rotten; we only can change it."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't eulogize Hitler.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, we are in a situation where cynicism is growing among the youth and the people at large. This cynicism is the most dangerous enemy of the democratic political system and we must be very careful about it. I would conclude by saying that the country is facing enormous problems. It is not only the ruling party but all political parties who must be very careful in dealing with these dangerous situations.

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, when would we have the lunch-hour?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We would have a 45-minute lunch break after the next speaker.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: But, Sir, the sense of the House must be taken on that. The Chair cannot decide it on his own.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There was an understanding reached in the leaders' meeting. Of course, the House is supreme. You could change any decision. I have no problem with that. I am only the servant of the House. …*(Interruptions)*… I fully agree with you. I have only mentioned the informal decision taken at the leaders' meeting. But the House is supreme. You may change it and advise me on it. Now, Mr. D.P. Tripathi. …*(Interruptions)*… Mr. Tripathi, kindly excuse me. Dr. Barun Mukherji wishes to take the flight at 2.00 p.m. and he had requested me to give him a chance earlier. I hope, you would agree.

SHRI D.P. TRIPATHI (Maharashtra): That is all right, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Barun Mukherji. You may take only seven minutes.

DR. BARUN MUKHERJI (West Bengal): Sir, while congratulating the President of India for his Address at the Joint Session of Parliament, I cannot ignore my disappointment and its omission of some of the major issues confronting the common people in the country. I am sorry to note that the most enlightened speech of the President has under-estimated the grave issue of unemployment and price rise currently prevailing in the country. The number of eligible unemployed youths is increasing every year. If the State doesn't come forward, who else can offer them the opportunity to earn their livelihood? We may feel proud of MGNREGA Scheme offering employment to 'around 5 crore households', but in true sense

this is not 'full employment'; nor is it proper utilization of the money spent for it. The proper scope for employment generation may come through expansion of manufacturing sector which is unfortunately in a very bad shape at present. The contribution of manufacturing to the GDP during 2012-13 is only 15.2 per cent. The President has only expressed his Government's pious wish that it 'remains committed to increasing the share of manufacturing to 25 per cent of GDP and creating 100 million jobs within a decade'. But a decade is too long a period for the millions of unemployed youths and moreover no details as to how to achieve these are given in the President's Address.

The other most difficult situation for the 'aam admi' is continuing rise in prices of all essential commodities. The President's Address doesn't offer any hope in this respect. It has only admitted that inflation 'is still a problem'. It is a matter of serious concern as the Address indicates that 'the Indian economy is currently experiencing slower growth. Real GDP grew by 5.4 per cent in the first half of the current fiscal year', which is 'significantly lower than the average of around 8 per cent in the last decade'. To explain this slow down, the Government is highlighting 'a combination of global and domestic factors'. But the question remains who should be responsible for the 'domestic factors', particularly when the UPA is in power for about the last one decade. To mitigate the hardship of the poor, the Government is not prepared to introduce and strengthen the universal Public Distribution System, as is demanded everywhere.

Perhaps the Government has other plans to initiate growth. The President's Address gives a serious hint: "The 12th Plan recognizes that growth-outcomes will depend upon the extent to which we are able to take some difficult decisions'. It is not elaborated what these 'difficult decisions' mean. But the possibility of introduction of some high degree of reforms cannot be ruled out. So far as the interest of the poor and the common people are concerned, we have experienced the ill-effects of cut in subsidy, very frequent rise in prices of oil products, encouraging forward trading and others. We wonder whether the Government can ensure that the reforms are panacea of all evils.

In view of the critical food inflation, people are eagerly awaiting the enactment of the National Food Security Act which can offer 35 kgs. of foodgrains at the rate of Rs. 2 per kg. per family per month.

[Dr. Barun Mukherji]

Thanks to the President that he has apprised us about our comfortable foodgrains position. He said, "The total stock of foodgrains with the public sector agencies was 662 lakh tons on 1st February, 2013, including 307 lakh tons of wheat and over 353 lakh tons of rice." Moreover, he said, "India became the largest exporter of rice in 2012-13." In such a situation, we can reasonably expect the Food Security Bill to be enacted in this session itself. Thank you very much.

SHRI D.P. TRIPATHI: Thank you very much, Sir. The Motion of Thanks on Presidential Address, excellently proposed by Shrimati Renuka Chowdhury, is also a 'Motion of Congratulations' because this is the first Presidential Address of our President to the joint sitting of Parliament. While the Presidential Address was going on, my memories went back to the first Presidential Address by legendary Dr. Rajendra Prasad to the Members of Parliament on 31st January, 1950, where he talks about the high enterprise of service of our motherland and the millions of people of India, and ends by saying, "I pray that wisdom and tolerance may guide your deliberations". Where Dr. Rajendra Prasad ends his Address, it is there that this Presidential Address begins. In the very first paragraph, the President says that he hopes that this session will be productive and useful. Now, this is one point. I am beginning with the first paragraph of Presidential Address because I am a new Member in this House. I have not yet completed one year in the Parliament. I fail to understand as to why Parliament is disrupted. If you oppose the Government, I understand that. This is the job of the opposition to oppose and correct the Government whenever it is wrong. That strengthens democracy; but why disrupt the Parliament? This is something which I have failed to understand. That is why, the first paragraph of the Presidential Address is extremely important.

Now, I take you back to the first Address by Dr. Rajendra Prasad because it is not merely a trendsetter but it is very comprehensive also. He talks about the commitments of his Government and explains all those policies of his Government. Like that, this Presidential Address is comprehensive. It also explains the commitments of the UPA Government and its achievements. Therefore, I also welcome criticism of those achievements as a democrat. But, that criticism shows the work done by the UPA Government. I agree with my friend, Mr. Derek O'Brien, who said that UPA, which according to me is 'Unique Political Alliance', has become APA. I agree

with him that UPA has become APA, but he has got the meaning of APA wrong. The meaning of APA is that UPA is 'All People's Alliance' because it is 'Unique Political Alliance'.

The approach that the principal opposition party, according to me, should now have is what Shri Atal Bihari Vajpayee had said in his first reply to the Presidential Address on 31st March, 1998. I quote his words, "We have never adopted non-cooperative attitude in constructive endeavours." Therefore, I would appeal to the opposition to follow Shri Atal Bihari Vajpayee and support the constructive endeavours to take India forward, take India to the triumphant march of development which has been initiated and is being implemented by the Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh.

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha): Tripathi ji, you have been very sweet to quote Shri Atal Bihari Vajpayee but I hope you will tell the Ruling Party also to follow the path of Shri Atal Bihari Vajpayee. If both sides follow the path shown by Shri Atal Bihari Vajpayee, this country will regain the momentum that it had during the NDA-regime. Thank you, Sir, for quoting Shri Atal Bihari Vajpayee.

SHRI D.P. TRIPATHI: I am quoting the positive attitude that should be taken about the achievements and activities of the Government of the day in the broad national interest. This is what I mean.

While analyzing the President's Address, now I come to the speech and intervention of hon. Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, made on 10th March, 2005. That speech is very significant because his Government was going to complete almost one year at that point of time, and, as humility not merely characterizes that speech but it characterizes the very personality of Dr. Manmohan Singh that while going through this, I was reminded of a line from a Sanskrit shaloka 'विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्' Learning gives you humility and humility brings competence.

In that language of humility, he enumerates the priority sectors of his Government while replying to the debate on the Motion of Thanks on the President's Address in 2005. The first priority is education, the second is health, the third is employment, the fourth is agriculture, the fifth is urban renewal and so on and so forth. Why I mention that speech is because in the...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: Sixth is corruption!

SHRI D.P. TRIPATHI: Please. I don't interrupt anybody. Therefore, I would like you to be kind to me. So, all these priorities are relevant for this Presidential Address because this is a comprehensive Presidential Address where from agriculture, industry, economic growth to national security, foreign policy, Defence, internal security, all aspects have been covered, and, it shows the continuity and consistency in the policies of the UPA Government. That is why I mentioned Dr. Manmohan Singh's speech. I will come back to Shri Atal Bihari Vajpayee's speech and Dr. Manmohan Singh's speech later.

But let me take up certain points raised by the hon. Leader of the Opposition and my distinguished friend. Actually, criticism and controversy show the enterprise of the Government. The distinguished American writer, artist and philosopher, Elbert Hubbard, said, and, I quote: "To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing." President John F. Kennedy said, and, my Leftist friends should not mind that I am quoting only Americans, don't worry, I can come to Antonio Gramsci a bit later. President John F. Kennedy said, "My experience in the Government is that when things are non-controversial and beautifully coordinated, there is not much going on." So, therefore, we welcome criticism and when we work, we will definitely be criticized.

I welcome the brilliant speech made by the hon. Leader of the Opposition, wherein he talks about various aspects and likens P. Chidambaram — 'P.C'. to P.C. Sarkar. Coming to his speech and the points raised by him, there were a lot of statistics in his speech and he talked about the jugglery of figures and statistics, and so on and so forth. He mentioned the words, 'fiscal indiscipline'. We talk about fiscal discipline, but he said, who created this 'fiscal indiscipline'? It is the UPA which created this 'fiscal indiscipline, according to the hon. Leader of the Opposition. And, therefore, there are no economic achievements and he gave a lot of statistics.

The distinguished writer Arthur Koesler has said that statistics never bleeds. Therefore, the politicians, bureaucrats, journalists and academicians have a tendency of throwing statistics on everybody. So, I am not going to throw much of statistics, but since the Leader of the Opposition talked about the jugglery of figures and no achievement in nine years, I would give only one statistics which is indicative of the economic progress made by India in these nine years. He talked about the great legacy left by the NDA, that great legacy, and strong economy which was booming, according to him. What was the situation in 2002-03? The *per capita* income in India was 24,164 rupees. And after all the socalled fiscal indiscipline,

economic mismanagement, jugglery of figures and statistics, according to the hon. Leader of the Opposition, what is the *per capita* income in the year 2011-12 – 42,851 rupees. So, from that great legacy ...*(Interruptions)*... No, no, it is 42,851 rupees. Please check your statistics. I give my statistics and details after checking and re-checking them. All right? So, this is 42,851 rupees. Therefore, while listening to his brilliant speech, I was reminded of what I said in 2004 after the election results. A foreign television correspondent was asking these political leaders. My BJP friends were also there. They asked me: What will be your one-line comment on the election results and formation of the new Government, UPA Government, in 2004? I said, "Now that NDA is out of power, I feel good because India is shining now". This was my comment on the election results which threw NDA out of power in 2004. Therefore, this much about the excellent speech of the Leader of the Opposition and this shows the real strength and power of the United Progressive Alliance Government in taking India to economic heights. Mrs. Renuka Chowdhury and all other speakers mentioned about many things in the Presidential Address. I do not wish to be repetitive; I wish to raise only new points. All those previous speakers have made my task easier. So, I would raise only new points. Though the President begins his Address with aspirational India, and Mrs. Renuka Chowdhury talks about it, no speaker, unfortunately, has looked at third paragraph of the Presidential Address where he talks about the gathering anxieties of economic slow down, jobsecurity and timely delivery of entitlements and, above all, the persistent social and economic inequality. This is the third paragraph. The Presidential Address not merely talks about the aspirational India, it talks about the anxious India also.

Now, coming to the basic points of development, I would not go into various sectors; but before I go to other aspects of the Presidential Address, I must mention para 34 of the Presidential Address where the President says that my Government has created a separate department for disability affairs. Now, this is something which has not been mentioned by any speaker. I am fully confident that all Members of this august House will laud the effort of the Government of creating this separate department for disability affairs because the most neglected and deprived section of our society are those who suffer from disabilities because they are not merely victims of constant cruelty, humiliation and lack of opportunities, they face severe problems. Because of want of time, I do not wish to go into all these aspects. No speaker has mentioned that achievement of the Government in para 34.

[Shri D.P. Tripathi]

According to most conservative estimates, 2.5 per cent of our population are the disabled people. According to independent researchers, the number of those who are disabled, who suffer all agonies, tears and unimaginable tribulations in life...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: 'Disabled' word is not used these days. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: I am saying what is written there. ...*(Interruptions)*... I agree with you. ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: Then, don't use 'disabled'. ...*(Interruptions)*... We use 'differently abled'. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, 'differently abled'. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: I agree with you entirely. ...*(Interruptions)*... But, what is written there in the Presidential Address is that. ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: That is why you should condemn that. ...*(Interruptions)*... That word should not have been used. ...*(Interruptions)*... If you have commented on that paragraph, then you should be saying that this particular word should not have been used at all. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: Okay. ...*(Interruptions)*... It's all right. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Tripathiji, please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री डी.पी. त्रिपाठी : तो मैं अभी इतना ही कहूंगा।

सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ और मसलों को उठाते हुए मेरी विपक्ष से अपील होगी, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष से कि उन्होंने जो अपने भाषण में प्रगति की गति की बात की है, वह प्रगति की गति बिना सरकार के प्रयासों के नहीं आ सकती। तो हमें प्रयास जरूर करने दीजिए और उन प्रयासों में आपका समर्थन भी जरूरी है। देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उस प्रगति की गति के लिए, मैं उर्दू के एक शेर के माध्यम से...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have two more minutes. ...*(Interruptions)*... Take two more minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री डी.पी. त्रिपाठी : उर्दू का एक शेर कह कर मैं अपनी यह बात को खत्म करना चाहता

हूं। शेर आपको मामूली लगेगा, लेकिन उसका मतलब गैर-मामूली है। इसी देश में हमारे प्रयासों से विकास होगा, यह हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। वह शेर यह है कि -

वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दो,
मुझे यकीं है कि पानी यहां से निकलेगा।

That is how India will prosper. Now, I have three minutes, as I am told. I am a disciplined person. I always abide by the discipline and dignity. Therefore, I would just mention this. Prof. Ram Gopal Yadav, in his professorial speech, talked about agriculture. It is no wonder that there are nine paragraphs in this Presidential Address on agriculture. No one has talked about the achievements of the Indian agriculture. Growth in the Eleventh Plan is 3.7 per cent instead of 2.4 per cent in the Tenth Plan. There was record foodgrains production of 260 million tonnes last year and this year, in spite of erratic and deficient rain, it is projected that we will have production of 250 million tonnes. There is all-time high production in the horticulture sector of 251 million tonnes. With 128 million tonnes of milk production, India continues to be the largest producer of milk in the world. I understand the anxieties of the hon. Members about food processing and we entirely agree with them. Now, very briefly, I will come to a bit about foreign policy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Take one minute more.

SHRI D.P. TRIPATHI: Sir, let me conclude then. I come to the last paragraph in the Presidential Address where the Address begins with aspirational India and ends with inspirational India. It talks about why India is considered tall. It is because of its liberal and plural democracy. And he appeals to all of us to support the endeavours to march forward as a proud nation. That is the great strength of India. The Presidential Address talks about inspirational India. Since we all love our motherland, let us take it to the great height of development and progress. I will end my speech with a few lines from the distinguished poet, Ezra Pound, who says,

"What thou lovest well remains,
the rest is dross What thou lov'st well shall not be reft from thee
What thou lov'st well is thy true heritage"

Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, if the House agrees, we will have a lunch break upto 2.15 p.m. The House is adjourned to meet at 2.15 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled at fifteen minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the President's Address.

On behalf of the All India Anna DMK, I rise to place our views on the Address by the President of India to Parliament. I have two Addresses here, one presented by the former President, Shrimati Pratibha Patil, last year on 12th March, 2012; and the other by the present President, Shri Pranab Mukherjee, this year, on the 21st February, 2013. I am tempted to conclude that we need to have Action Taken Reports by the Government on the President Addresses also. After all, the President never speaks out his mind. But he reads out a text approved by the Union Cabinet.

After a long and protracted political battle by the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, the final order of the Cauvery Water Dispute Tribunal, dated 5th February, 2007 was notified in the Gazette of India on the 19th February, 2013. The people of Tamil Nadu, particularly the farmers, are extremely happy that ultimately justice had been done to them, even though very belatedly. In fact, the Cauvery water delta farmers are organising a grand felicitation function in honour of Dr. Puratchi Thalaivi in Thanjavur on 9th March, 2013. The Tribunal has mandated the establishment of the Cauvery Water Management Board; and the Cauvery Water Regulation Committee with a clear cut composition, role and functions.

The Chief Minister of Tamil Nadu has written to the hon. Prime Minister on 22nd February, 2013 to ensure that the Ministry of Water Resources constitutes the Cauvery Water Management Board and the Cauvery Water Regulation Committee so as to give effect to the final order of the Tribunal. I urge upon the UPA Government to act on this immediately and not wait till the Karnataka Assembly Elections are over.

In para 109, the President's Address says that two units of the Kudankulam Nuclear Power Plant will be commissioned this year. A few days ago, the Minister of State in the Prime Minister's Office, Shri V. Narayanasamy has refixed — he always does — the revised date and deadline as 15th March, 2013 for commissioning the plant. But, yesterday, he told in the Lok Sabha that the Kudankulam plant will

be commissioned in April, 2013. In view of the widespread power shortage, the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, in her letter dated 25th December, 2012, to the Prime Minister has requested that the entire power of 2,000 MW generated from the Kudankulam plant is allotted to the State of Tamil Nadu. There has been a precedent for this, with the entire 1,000 MW of power generated at Simhadri power plant in Andhra Pradesh was allotted to Andhra.

But our Prime Minister has not, as usual, bothered to respond to her request. Now that the Kudankulam plant is likely to be functional in the next few weeks, I reiterate the request of our Chief Minister that the entire 2,000 MW be allotted to Tamil Nadu at least this year.

Para 5 of the President's Address mentions about the Direct Benefits Transfer system using Aadhaar Number. This is being claimed as a game-changer. This shows how little the UPA Government understands ground level realities. The DBT will not work for certain schemes, like PDS and fertilizer subsidy, where ensuring availability of foodgrains and fertilizers is much more crucial to preserve food security than transferring cash. I would like to quote Puratchi Thalaivi who said, "In a federal structure like ours where the States are in direct and close contact with the people, the choice of designing and implementing popular welfare schemes is at best left to the States." That is why we are strongly opposed to Para 12 of the President's Address where the Government is committed to enacting the National Food Security Bill. Tamil Nadu is implementing the Universal Public Distribution System (UPDS) successfully and is able to address the issue of food security without any exception. We have serious reservations on the Food Security Bill as it will deprive the State's entitlement of foodgrain allotment. We will strongly oppose the Food Security Bill when it is taken up in the Parliament.

The External Affairs Minister had told the House last week that welfare, safety and security of our fishermen have always received the highest priority of the Government and assured us that the UPA Government was engaged with Sri Lanka to ensure that fishermen on both sides could continue to pursue their livelihood in a safe, secure and sustainable manner. But as recently as Sunday morning, 16 fishermen from Thoothukudi district had been apprehended by the Sri Lankan Navy when they were fishing in the Gulf of Mannar, which they have been doing for the past several decades. This has become very frequent and this is happening at regular intervals. While the Sri Lankan Navy has been proactive and aggressive, I do not know what

[Dr. V. Maitreyan]

our Indian Coast Guard is doing. They neither do crucial coastal surveillance nor do they guard our fishermen. The Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Prime Minister to intervene and secure the immediate release of the Tamil Nadu fishermen. I urge the Government to act with firmness. As I say this, yesterday another fisherman who was fishing in Kodiakarai, Nagapattinam district was shot at by the Sri Lankan Navy.

On behalf of my party supremo and Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma and on behalf of the seven crore Tamilians of our country, I strongly protest against the non-inclusion of war crimes and genocide of Tamils in Sri Lankan in the President's Address. In fact the Tamil Nadu Legislative Assembly passed a unanimous resolution condemning the genocide of Tamils in Sri Lanka, demanding an independent international inquiry and urging economic embargo on Sri Lanka till the Tamils are treated with respect and dignity. But the UPA Government has maintained a deafening silence on it and the President's Address has totally ignored it.

The President's Address in Para 98 mentions about the progress made in our engagement with Sri Lanka including in our efforts to resettle and rehabilitate the internally displaced persons there and to ensure a life of peace, dignity and equality for the Tamil people. On the contrary the ground reality is totally different with the Sri Lankan Government enforcing cultural genocide in the North and the East. There is an enhanced presence of military and sinhala settlements and the Sri Lankan Government has been systematically destroying the archaeological and historical traces of Tamil identity in the North and the East. The Sri Lankan Government pursues it agenda of cultural genocide of the Tamils in the name of development of the North and the East. But blinded to this obvious reality, the UPA Government has hiked assistance to Sri Lanka by Rs. 210 crores in the current Budget.

As against Rs. 190 crores for 2011-12 and Rs. 290 crores for 2012-13, the UPA Government has allocated Rs.500 crores for the year 2013-14. Thus, in the three years 2011-14, the Government of India has allotted nearly Rs. 1,000 crores, and this grant, instead of helping the affected Tamils, is being misused by the Sri Lankan Government for Sinhala resettlements in the North-East. The Prime Minister assured the delegation of Congress MPs on 22nd February that there would be no

compromise on more powers for Sri Lankan Tamils *vis-a-vis* the 13th Amendment. Responding to the Calling Attention Motion moved by me last week in this House, the External Affairs Minister Mr. Salman Khursheed almost parroted the same about power devolution. But as recently as 2nd March, the Sri Lankan President Mr. Rajapakshe in an exclusive interview to 'The Hindu' ruled out autonomy to the North-East, the Tamil Home Land, saying that the North would have powers which are "not more, not less" than those enjoyed by the eight other provinces.

Except the UPA Government, none will expect anything different from the Sri Lankan President. That is why the Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi, has insisted that the UPA Government should move a resolution in the United Nations Human Rights Council in Geneva condemning the genocide in Sri Lanka, and to demand an independent international investigation and also urge for economic embargo against Sri Lanka.

We hear from newspapers that next week the U.S. is moving a Resolution against Sri Lanka in UNHRC, Geneva. I strongly urge upon the UPA Government not to bail out Sri Lanka as it did last year by toning down the last year's Resolution, but to take the lead in moving our own Resolution condemning genocide in Sri Lanka. I also urge upon the UPA Government that it should not participate in the CHOGM Summit to be held in Sri Lanka in November this year. Any step taken by the UPA Government to either directly or indirectly help Sri Lanka will be a gross betrayal of the Tamils and the people of Tamil Nadu will not forgive you for that.

Sir, nowadays we are witnessing a great Indian *tamasha*. The UPA Government, of which the DMK is a part, has much to answer for the genocide committed in Sri Lanka, because the Sri Lankan President constantly maintained that he was fighting India's war only, and New Delhi never denied it. The DMK, which was ruling Tamil Nadu when the genocide of Tamils was committed in 2009, is now shedding crocodile tears by meeting foreign dignitaries, organizing TESO conferences and calling for Tamil Nadu Bandh, etc. All these can, at best, be a DMK show and nothing more than that, and the Tamils, the world over, understand this drama very well. But worse, I read in newspapers yesterday and today that the Congress (I) Party is also participating in the TESO Conference to be held in New Delhi today evening, and it is deputing its senior General Secretary and a Union Minister along with three more Members of Parliament. This is the greatest Indian *tamasha* of this year. People,

[Dr. V. Maitreyan]

who are supposed to act and act with firmness and decisively, are indulging in dramatics and theatrics. I only wish to reiterate what I said last week. The sinners can never become saints and Tamils will never accept it. They will never allow it and they will never approve it. Instead I demand that the Congress (I) and the DMK should tender a public apology to the Tamils world over for their acts of commission and omission in the genocide of Eelam Tamils. Thank you.

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion for Thanks to the President's Address.

The President's Address is very important not only individually but also as an Address to both the Houses of Parliament. And he takes the approval of the Cabinet before delivering his speech to both the Houses of Parliament. After this, naturally, the whole country looks forward to the hon. President for the *dasha disha*. Unfortunately, after listening to his speech, I come to know that except the ongoing schemes of the present Government, he has not mentioned about the *dasha disha* of this country.

But, he has rightly mentioned, in the beginning itself, that younger generation, women and children are eagerly waiting for timely delivery of their entitlements and about their persisting social and economic inequality. This one sentence blows out the Government's objective of achieving inclusive growth. Sir, I found one peculiar thing with this Government. When there is fall in growth, it says global recession. But, when there is growth, it says that it all happened because of their policies and programmes.

Secondly, hon. President proudly says that Cash Transfer Scheme is a "Trend-Setter" and the Finance Minister says, it is a "Game-Changer." Sir, if you study deep into it, it is neither a "Trend-Setter nor a "Game-Changer", but it will turn out to be a "Scam-Setter" as more than Rs. 3.2 lakh crores are involved in distribution for poor from this year. Let me substantiate this point. Sir, the Government started this Scheme in some 23 districts and one of them is Alwar in Rajasthan. The Collector of this district is reported to have said that there is a massive leakage in Kotkasim block of this district. So, the Congress slogan "आपका पैसा आपके हाथ।" rhymes well with another Congress slogan, "आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ।", but with above result in Alwar, the slogan needs to be changed as "आपका पैसा दलाल

के हाथ।" So, I only suggest the Government to go ahead with this scheme carefully and meticulously; only then can you make it a success.

Sir, the less I talk about corruption and scams in the UPA Government, the better it is. There is no direction shown in the Address to root out corruption from the country. The latest Augusta Westland scam shows to what extent corruption penetrated into the country. It is really a dangerous signal if corruption creeps into Defence, because it is the Army, the Air force and the Navy which are protecting our country. Sir, a posting is rapidly gaining popularity on the social networking sites. It says, "Yesterday, the turnover of General Motors was greater than the Union Budget of India. But, today, the size of scams in UPA is greater than the turnover of General Motors!" If you just take into account the major scams such as 2G, Coalgate, Commonwealth Game, Mining, DIAL, etc., it comes to more than Rs. 6.5 lakh crores. Now, we are seeing, for the first time, that people, led by non-political organisations, coming on the streets voluntarily and participating in the anti-corruption movement. On the one hand, I feel very happy because, through these movements, the democracy is becoming more vibrant and, on the other, I am more concerned since it shows the weakness of the Government. So, it is the duty of the Government of-the-day and the institutions of this country to protect this country from corruption.

Sir, I now come to reforms. I do agree that reforms are required in every sphere, but they have to be with humane face. There have to be reforms in the socio-economic spheres of this country, there have to be reforms in administration, judiciary, etc., but all these have to culminate in achieving the objective of inclusive growth. We have to use the information technology and other modes for achieving innovative methods and processes so as to take the fruits of growth to the last man in the queue. Otherwise, whatever exercise you do, it will be a futile one.

Sir, with a deep sense of pain, I wish to submit that hon. President, it appears, deliberately omitted to mention the issue of Telangana in his Address. A separate State is the five decades' aspiration of 4 crore Telangana people. In 2004 President's Address, there was a mention about Telangana.

Nearly 700 people died for the cause of Telangana. I demand the Union Government to immediately bring the Bill on Telangana. We all support it.

I now come to power sector. We had set a target of 78,500 MW in the Eleventh Plan, but could achieve only 54,900 MW. But, if you look at the installed capacity,

[Shri Devender Goud T.]

it is about 2 lakh MW at the end of the Eleventh Plan. Even in the Twelfth Plan, we have set a target of 89,000 MW. It is good to have an ambitious target, but if you lack in will to achieve this, it will just remain on paper. We all know that power situation is not good in the country. It is going from bad to worse in my State as well. In 1998, when TDP was in power, it brought Andhra Pradesh Electricity Reforms Act and divided Andhra Pradesh Electricity Board into TRANSCO and GENCO for effective and efficient generation and transmission of power. The objective behind this is to meet the 10 per cent annual increase in demand and ultimately make my State as "Energy Hub" of the country. As of 1989-90, there was 2,000 MW deficit in Andhra Pradesh. The TDP Government, by 2003-04, increased the capacity to 10,695 MW. Even though in the last 4 years of TDP rule witnessed severe drought, it was able to generate 981 MW through hydropower, but Congress Government could generate only 243 MW. Congress assured that it would give 12 lakh agriculture connections, but so far it has given just 7.5 lakh connections. Average power consumption by agriculture sector during TDP regime was 62 per cent and in Congress regime it has fallen to 47 per cent. This clearly shows that Congress Government in Andhra Pradesh neglected the farming sector. The Congress, since it came to power, has increased power charges three times which comes to Rs. 6,870 crores. In the form of FSF, it has increased charges to the tune of Rs. 7,771 crores and from April, 2013, it is going to increase charges to garner Rs. 13,705 crores. If one calculates, one would know the burden the Andhra Pradesh Government is putting on the common man.

Secondly, DISCOMs owe more than Rs. 30,000 crores. If this situation goes on, TRANSCO, GENCO and DISCOMs become bankrupt and Power Emergency has to be declared in Andhra Pradesh. So, I would urge the Union Government to come to the rescue of Andhra Pradesh and help the people of Andhra Pradesh by allocating more power from the Southern Grid and also provide sufficient gas to projects in Andhra Pradesh to come out of the crisis. Otherwise, all this leads to once *Swarnandhapradesh* to *Andherpradesh.*

I now come to terrorism. Sir, so long as we play vote bank politics, it is next to impossible to deal with such unscrupulous elements which are brining terror into the country. Almost every State is affected with one form or the other of anti-national

activities such as terrorism or extremism or secessionist activities or naxalim. And, Sir, Hyderabad has become *adda* for terrorists. They are carrying out their activities at their will. Now, a two-day Red Alert has been declared in Hyderabad. In these two days, police is carrying out checks and searches in every nook and corner of the city. And, the people are worried about another possible bomb blast in Hyderabad. While replying to the debate, I hope, the hon. Prime Minister would assure the people of Hyderabad not only about their safety but also the safety of the city.

The next point is, why is the Government not coming out with NCTC and NATGRID? I request the Government to discuss this issue with States, sort our differences and convince the States explaining the need and importance of these. It is only then we can deal with terrorism. Otherwise, whenever there is any incident, there would be a knee-jerk reaction, visit by VIPs to the spot, announce some compensation and there ends the issue. So, I only urge to take some concrete steps so as to address this menace which is affecting not only our economic independence but also social, cultural and challenging our sovereignty.

Sir, I now come to the plight of women in the country. A society that is unable to respect, protect and nurture its women and children not only loses its moral right of existence but it ultimately collapse.

Let us see to it that such a situation does not come to this great country. We must adopt a three-tier approach in order to protect them: The first one is, prosecution and strict legal action would act as an important deterrent. The second one, and a very important one, is that law enforcers must be trained to deal softly and sensitively with women and children who have been harassed, assaulted and raped. The third is, punishment should be exemplary, quick and widely covered in the media. Finally, a nation-wide vigorous campaign is needed which would involve film personalities, sportspersons, eminent citizens from the society and religious heads, to enable India to protect its core values and traditions which respect women and children. I propose that for, at least, ten minutes of prime-time on every television channel, this campaign should be telecast continuously for, at least, one year. I am sure, this would bring about a tangible change in the perception towards women in our society.

Sir, I would conclude my observations with one or two more points. In the President's Address, farmers' loan waiver is not mentioned. We are really disappointed with that. People talk a lot about the agricultural sector in the country but they

[Shri Devender Goud T.]

have not yet attended to them. Seventy per cent of our population, the farmers, are dependent on land. They are all looking towards the Government of India for a waiver of their loans. Price-rise is another important problem which has not been mentioned in the hon. President's Address. The President has skipped the issues of price-rise and unemployment. Though he mentioned the youth, unemployment was not mentioned. We are disappointed with this.

Thank you, Sir.

SHRI H.K. DUA (Nominated): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President's Address.

Sir, when we were young, at school, we talked about 'Tryst with Destiny', nation building, a new Constitution, independence of the Judiciary and responsibilities and the challenging role of the Bureaucracy or the Executive, in a free India. It was good to be around during those decades of nation building which was thought of by the visionaries who brought freedom to India. After many ups and downs — I don't want to go into the history of the entire post-Independence India — in the 1990s, we started thinking big again. And I think, all parties at that time were coming to the conclusion that India has the potential of emerging as a major economic, political and nuclear power of the 21st century. The people talked of the Asian Century, the people also talked of China emerging as a major power and India becoming a major power in the future. The world also started taking us seriously. We could, and we are still, able to look straight into the eyes of the world. We don't have to go round with a begging bowl looking for PL-480 grain. We can take care of our food problem ourselves. We can even export foodgrains, but here, if there is a difficulty, we can withstand a drought or two without any difficulty. Our industrial base is very, very strong. We are one of the ten largest economies of the world. We have the third largest army in the world. And, as shown recently by the Indian Air Force in the vasts fields of Jaisalmer, we have the sixth most powerful Air Force in the world. Our space scientists are daily doing us proud and going deeper and deeper into the space, and in a few years' time, an Indian would be on the Moon.

Yet, my worry is, the country these days is steeped in a mood of cynicism

despite all those achievements. There are gaps here and there. There is recent economic slowdown in most of the world and here also. But, this mood of cynicism, which is widespread, is not only in cities and small towns but also has gone deeper down everywhere, evident when you are talking in a drawing room or when having food in a restaurant or a *dhaba.* There is a mood of cynicism. The talk is on which way the country is going and on what is going to happen to the country, despite the achievements. Maybe, we aspire for more;maybe, the expectations have gone higher and higher, and we are not able to meet. Maybe, there are untackled problems so massive with the size of the nation of 1.2 billion people. They are indeeed overbearing. However with this mood of cynicism, you can't be creative. If you have to build a nation as an emerging major power-economic, political and nuclear-with a billion people in the 21st Century, you cannot remain steeped in the mood of cynicism. The President of India, who just reflects the collective wisdom of the Cabinet in his address is talking of gathering anxieties. He has listed some of the anxieties about jobs, about unmet aspirations of 'the aspirational India', of how to improve the delivery system, how to take the gains of economic growth to the people, to fight inequalities, as he was talking towards the end of the Address. But, my anxiety is a little different, a little wider, which I thought would deserve the attention of every political leader whether in the Government or in the Opposition, or the opinion leaders outside as well as of the nation itself.

The countrymen are getting worried about the fate of the Constitution, which our visionary founding fathers gave us. It is coming under a serious strain and it should worry everybody sitting here, particularly Parliament which is supposed to represent the will of the people. The Constitution of India has come under a serious strain. Parliamentary democracy has come under a serious strain. One is not sure what form it is going to take. The quality of Parliamentary democracy, as it is in the country today, as it is viewed by the people these days, is definitely worrying. That worry is some times admitted by the political leadership of various parties; some times, it is talked about in undertones. But, we are not able to understand what our responsibility is to save democracy from further decline. The malaise is not necessarily reflected in what are 'street protests' which are gathering in State after State. They are at times worrisome. The headlines can be scary. But, I think, we can withstand those. This is because of the atmosphere of intolerance developing in the country. A small incident becomes a riot. A big riot becomes a crisis. Then,

[Shri H.K. Dua]

most of the nation's energy gets wasted. Social tensions are developing in different parts of the country; the State Governments are not able to handle them; the Centre is distant itself, having other problems at hand; and, the people do not know how the situation has to be tackled.

So, this kind of an atmosphere cannot be creative for building a powerful new India, with a powerful economy, as a political power, as a nuclear power. I think, we need to pool our heads together.

The Centre-State relations are also under strain. There are many issues on which there should be no serious problem in tackling terrorism, for instance. Terrorism has to be tackled and major role has to be of the Central Government but the States are questioning this.

Law and order is a State subject. Everybody respects that. You can't control the law and order situation from Delhi. The simple formula should have been that the States should have control over law and order and the Centre should have a supplementary role in case of a contingency. In tackling terrorism, the lead role should be of the Central Government, and the supplementary support has to be provided by the States. Together they have to fight terrorism. But the fact is, the Centre, over the years, and it is worrying, Mr. Deputy Chairman, Sir, has become weak. And, I think, the leaders of the States and the leaders of the Centre need to work it out and ensure that the Centre should not become weak. You cannot become a major power with a weak Centre. It is just not possible. If the Centre is weak, the States also will be weak. And, if the States are weak, the Centre cannot be strong either. So, we have to work it out. What the country needs, at the moment, is a consensus among political parties. Without that consensus, there cannot be a workable democracy which will draw the respect from the people. Parliament is no longer enjoying the kind of respect it should have among the people — thanks to our behaviour. The Judiciary, crowded as it is, with three crore cases pending — no one knows whether the case will come up in his life-time and justice will be delivered come to public notice about. There are other faults also that have appeared in the Judiciary. As regards Executive, you go from State to State, from village to village, from town to town, the bureaucracy is often found callous, distant and unresponsive to the people's demands. If the major institutions are not respected

by the people, then, the Constitution is bound to come under strain. I think the time has come when a remedy will be found, not by the Government alone, not by the Opposition alone, not by blocking Parliament here, which Shri D.P. Tripathi has talked about, it will be found by an informed consensus on some vital issues, which is very, very important and has become urgent. There are some issues on which there should be no difference. Terrorism is one. It is a major threat. Any time a terrorist can choose any spot for a surprise attack. The fundamental weapon of terrorist groups is 'surprise', and any State and the Central Government can be taken by surprise anywhere. ...*(Interruptions)*... I won't take long, Sir. I know there is paucity of time, but I would like to make one or two points. Terrorism is one issue; security of the country is the other issue; nuclear question is another issue; Foreign Policy is another issue. Also, everybody will agree that without internal coherence, India cannot emerge as a major power or a major economic power, or tackle its enormous problems.

Sir, I will just touch Foreign Policy since there is no time to elaborate it further.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, there are two more speakers from the 'Nominated Category'.

SHRI H.K. DUA: I will just take two minutes more. We are being respected more by the world now. But in South Asia, I think, we have to be careful. Test of a good Foreign Policy is always in the neighbourhood. Pakistan continues to be a worrying phenomenon for us. There is uncertainty about Pakistan; elections or no elections, Pakistan is going through an uncertain phase. You look at the Pakistani Papers, or, at the World Press. Whichever Government is in power will not be able to control *jehadi* power in Pakistan. We don't know about the Army's role, whether it is anti-*jehadi* or it is supporting some *jehadi* groups in Pakistan — a Pakistan, where *jehadis* are there, and where nuclear weapons are also there, *jehadism* plus nuclear weapons are a dangerously combustible material lying just next door to us. If something happens in Pakistan, if the nuclear weapons fall in the hands of the *jehadis*, the world has to worry, but we will be the first country to worry most. I think we should, get into consultation with other world powers, about it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI H.K. DUA: Sir, the President's Address mentions other countries — Bangladesh, Nepal, etc., but Maldives has not been mentioned. I am not taking Maldives particularly because of the recent developments, but because it is in the middle of the Indian Ocean, and we cannot ignore the interests which China and Pakistan are taking in Maldives. Whether it is Waheed's rule or Nasheed's rule, that is for its people to decide, but India has its strategic interests in the Indian Ocean. And, I think we should take care of that. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Birendra Prasad Baishya. He is not here. Okay, Mr. D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I rise to present the views of my Party, the Communist Party of India, on the President's Address. Sir, when the President was delivering his Address, the working people of this country were on a general strike at the call given by 11 central trade unions irrespective of their political affiliations. We were, of course, outside the Parliament, extending our support to the working people of this country. Sir, when I look at this President's Address, I find the Congress-led UPA-II Government is pleading helplessness and hopelessness. Sir, when the President delivered the Address last year, on the same Address, on the same floor of the House, I said that it is nothing but a compilation of broken promises and promises to be broken. Now we have a President's Address which pleads helplessness and hopelessness. Sir, in the last year's President's Address, the Congress-led UPA-II Government has promised five things. I quote, "My Government will work on five important challenges that our country faces today: to strive for livelihood security for the vast majority of our population and continue to work for removal of poverty, hunger and illiteracy from our land; to achieve economic security through rapid and broad based development and creation of productive jobs for our people; to ensure energy security for our rapid growth; to realize our developmental goals without jeopardising our ecological and environmental security; and, to guarantee our internal, external security within the framework of a just, plural, secular and inclusive democracy." Sir, I ask the Government whether they can do some introspection. Have you moved anywhere forward to face these challenges? The present...*(Interruptions)*... You moved a long way from the people and were not facing the challenges. That is another thing. Sir, the present Address talks about the present state of economy in a big way and there the President concedes that both global and domestic factors have affected our growth. Sir, I would like to

3.00 P.M.

recall what our Prime Minister has said sometime back, "The financial crisis originated in the USA in 2008. India, to a great extent, remained unaffected by the crisis. That is due to the strength of the public sector enterprises and public sector banks." It has been acknowledged by none less than the Prime Minister of our country while giving away the MoU Excellence Awards to the public sector enterprises. But the Twelfth Five Year Plan widens the scope for private sector. This is where this Government needs to introspect as to what went wrong. Are our fundamentals strong? Earlier the previous Finance Ministers used to claim that the fundamentals of our economy continue to be strong. Now no Finance Minister, no Prime Minister speaks about the fundamentals of the Indian economy. This Government has completely changed the paradigm of development depending upon FDI for every thing — FDI in multi-brand retail trade, FDI in banking, FDI in insurance, FDI in stock market. The Government wants to build an economy depending upon FDI. How far it is reasonable and realistic, how far it will strengthen our economic sovereignty, this is for the Government to answer to the people of this country. The Government will have to explain.

Sir, weakening public sector in the name of disinvestment, in the name of liquidating Government equities, is the surest way of undermining our economic strength. That's what the Congress-led UPA-II Government does. On the other hand, the Government goes on slashing the subsidies given to the people. I sincerely believe that the time has come when we will have to define and re-define subsidies. Subsidy is not something like a merciful action taken by the Government in the interest of the poor people. You have been denying their due share in the wealth. And, somewhere down the line, you have to compensate. That's what you are trying to do. It is a very defective understanding that those subsidies have become the greatest ordeal in path of the growth. This understanding should go. On the other hand, you are compelling the people to pay more and more on everything. Fuel charges are increased every now and then. Prices are going up. The Government stands hopeless to control inflation and everything is left to the market forces. If everything can be left to the market forces, what for do we have an elected Government? What is the role of this Government? What are the steps that this Government is taking to control the prices to contain inflation, to plan for productive employment? The Government goes on promising that it will create 100 million jobs in a decade's

[Shri D. Raja]

time. How many times have we been hearing this? But there is galloping unemployment in the country. It is Prime Minister who has said, "What is being built in India is nothing but crony capitalism". This 'crony capitalism' is responsible for the corruptions in the country. And, your Government is neck-deep in corruption. I don't want to list the scams, the corruption charges. The whole world knows that. The whole country knows that. How do such scams take place in India? It is because you have determined to go ahead with your neo-liberal policies in building 'crony capitalism', not understanding the difficulties, sufferings and hardships of the working people, toiling people of this country.

The Twelfth Five Year Plan talks about faster growth. It talks about sustainable growth. It talks about inclusive growth. All three are mentioned in the Twelfth Five Year Plan. But, look at the Economic Survey. The Economic Survey places India at 129th place, as far as the Human Development Index is concerned. Even today India is under 34th place. Again, the Economic Survey admits that people who belong to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes are suffering from financial exclusion. The Economic Survey mentions this. Where is the faster growth? Where is your inclusive growth? These are the issues on which the Government will have to think over.

The Government talks about the *Gram Nayayalayas*. The Government talks about the fast-track courts for dealing with violence against women. What about the fast-track courts to deal with the increasing atrocities being committed against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? Where are the judicial reforms? Where has the constitution of a National Judicial Commission gone? What about the police reforms? What about the electoral reforms? You are talking about only one reform, that is, the economic reform. What do you mean by economic reforms? Let us depend upon the FDI! Let us support and encourage the corporate sector! Let us serve the interests of the multi-national corporations! That is your understanding of the economic reforms. And, you are obsessed with one single reform, that is, the neo-liberal economic reform. You are not taking about the judicial reforms, the police reforms, the electoral reforms.

Sir, now, let me come to the independent Foreign Policy. I have gone through the President's Address.

There is no mention about Palestine. I do not know whether the Congress-led UPA-II Government has given up its friendship with traditional allies. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Let me finish, Sir. The Government talks about energy security, but, it has not been talking about the Iran-Pakistan-India gas pipeline. I would like to know whether you have given up the whole idea. What is your friendship with Iran? Nobody knows. The President's Address does not speak about our friendship with these countries. Sir, that is where I find that the Government has been drifting. It is not following an independent Foreign Policy. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: The only friendly country is Sri Lanka.

SHRI D. RAJA: As my friend, Dr. Maitreyan said, on Sri Lanka, after the war, the Sri Lankan Government admitted that it would carry out four things. One is demilitarisation; second is, development; third is, democratisation; and the fourth is, devolution. Now, I am asking the Government: Can you say any one of these has been implemented by the Sri Lankan Government? ...*(Time-bell rings)*...

Where is the devolution of powers to Tamils in Sri Lanka? Sir, here, I must say, now time has come that the Congress-led UPA-II Government should be honest and truthful. This Government should acknowledge that the horrendous war crimes and human rights violations which took place in Sri Lanka took place with the help of India, with the help of this same Government.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): No, no.

SHRI D. RAJA: Yes, that is part of history. You can deny history. But that is part of history. The Government gave all the support.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no. Sir, it should be expunged.

SHRI D. RAJA: You may say no. It is your view. I hold my view. Now I am asking. In Geneva, there is a meeting of the United Nations Human Rights Commission. What is the stand of India? ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, your time is over.

SHRI D. RAJA: Are you going to leave everything to America? No, what is the point in organising a special conference between the Congress and the DMK? Sir, Parliament will have to take a stand. India as a nation will have to take a stand. How can India remain as a sepctator? What is the role of India in Geneva? I am asking the Government. Are you going to be a spectator? Or, are you going to play a role? You allow the Americans to prepare the text of the Resolution and go by what the Americans say or Sri Lankans say. You have no say on the Resolution. ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, your time is over. Please conclude.

SHRI D. RAJA: So, the Government will have to take a stand. The Government will have to vote against Sri Lanka and the Government will have to demand an impartial investigation into war crimes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude.

SHRI D. RAJA: I am coming to the end, Sir. On the Nuclear Policy, the Government should take into consideration the huge concerns of public safety. People have fear after Fukushima. Here, the Government talks about Kudankulam, but what about Jaitapur? What about the Government's agreement with the French company whose technology is an untested technology? Why do you go for a cluster of nuclear reactors in Jaitapur? Is it reasonable? That is what the Government will have to think.

Finally, Sir, I must point out to the Government that this Government will have to review its policies, Economic Policy in particular. The Government will have to go for course correction. If the Government does not do it, the Government will have to face the political consequences. People are looking for an alternative, Sir. Some people may feel that they can wipe out Left from this State or that State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Nobody is thinking like that. We want Left and Right.

SHRI D. RAJA: Some people can think that they ...*(Interruptions)*.. But people are looking for an alternative. That is what Tripura shows. Sir, now, while we pay the homage to Chavez who died yesterday, let us understand he was an amazing person who fought for his own national interest, fought for his own poor and toiling people who could change the face of Latin America, standing firmly against the US imperialist power, which was really holding a threat to Chavez and his Government.

Let us draw some lessons from what is happening in Latin America. How do they protect the interests of their people? Sir, with these words, I express my strong regret. The President's Address doesn't inspire the people, doesn't motivate the people and doesn't give any kind of hope for the future of this nation. That is where the President's Address fails to address the concerns of the people. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Members, I have to request for your cooperation. See, we have to finish this discussion today because the hon. Prime Minister will be replying tomorrow. Now, in the 'Others' category, there are 13 names, and only 2 have spoken. For them, the total time is 'one hour, twenty-seven minutes'. So, if everybody takes ten minutes, even then it is difficult to finish. The Congress has 'two hours and six minutes'. There are six speakers. But I would request Congress Members to restrict themselves between ten to twelve minutes. Likewise, I would request the BJP Members also to restrict themselves. They have 'one hour and sixteen minutes' and four speakers. So, each Member is having more than fifteen minutes. I am only requesting for your cooperation. If that is done, we can finish it today. Therefore, in 'Others' category, we have only seven-eight minutes or a maximum of ten minutes. Mr. Raja is my good friend. So, he took fourteen minutes. He took the freedom. I am requesting everybody not to take that freedom. Now, Shri Bharatkumar Raut. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: So, we all are your good friends!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All are good friends. But don't take that freedom!

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Thank you, Sir, for having given me this opportunity.

Sir, I assure you that I will not take even a minute more than what is required. ...*(Interruptions)*... I was waiting for the hon. President's maiden speech to the joint sitting with a great expectation. This is because I hold him in very high esteem. He is the one President who has, perhaps, the longest tenure as a Minister, as a Parliamentarian, and he has a long history behind him.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) in the Chair.

But, Sir, I mention with regret that when I read the speech, when I heard him, I thought, is it really the President's speech! The President keeps repeating in his

[Dr. Bharatkumar Raut]

speech 'my Government'. I am not sure, if he were not the President, he would have mentioned, the content of the speech as 'my Government'. Anyway, that is, perhaps, our constitutional requirement. I have had my reservations on every point, but most of the reservations have already been expressed. So, I shall restrict myself to only a few points.

Sir, everybody is talking about rural poor, rural housing. Yes, their plight is huge. The atrocities meted out to them are huge. I come from Mumbai, the metropolis of the city. We call it Urbs Prima. Sir, who is concerned about the plight of the poor in the urban area? Who is concerned about the urban poor? I don't think we are, because, nobody is bothered about them. Everybody is talking about housing for the rural poor, everything for the rural poor. Here, in a city like Mumbai — perhaps, in Delhi, Kolkata and Chennai also — there are huge slums. Half of the Mumbai, half of the city, lives in slums. Who is working on improving their living? There is no mention here about any such welfare activity. Is that the duty of only the Municipal Corporation of Mumbai? Is that the duty of only the State Government? Or, should the Centre also get involved in it? It is because the problems of Mumbai lie not in Mumbai but somewhere else, in other States. Therefore, there are more Hindi-speaking people living in Mumbai than any other city in the North India, except, perhaps, Delhi and Allahabad.

Sir, who would address this situation? There is no mention of that in this Address. That has really put me off.

Sir, talking about Mumbai, it has historically been known as the industrial hub of the country, for ages. Now it has changed its complexion from an industrial city to a commercial hub. There is a vast difference between an industrial city and a commercial hub. The commercialization began with mills closing down, various chemical industries closing down, engineering units closing down and now, the last thing that I heard really hurt me, Larson and Toubro, one of the giants of engineering, are winding up their industry in Mumbai and shifting to Gujarat. I have nothing against Gujarat; I am not talking about Gujarat. But the point is, what is coming up in the place of the vast land used by L&T for their industry? I could understand

it if any other industry is coming up, but here, what is coming up is housing complexes. This is happening because land is selling at prices higher than gold in Mumbai. Therefore, the Centre must take cognizance of this today; tomorrow would be too late. Do we want to change the city entirely? Then, what would happen to the sons of the soil who have been living there for generations? What would be their fate? What would be the fate of their future generations? We are not bothered about them! All right, you bring in commercial complexes; but who will come and work there? If they come from out of Mumbai or out of the State, they would be adding to the burden of the city. The infrastructure in Mumbai is very limited. If we keep on adding extra burden to the city, it will burst tomorrow, if it has not burst today. Therefore, Sir, it is the duty of the Centre, as the guardian of the nation, to intervene immediately. You cannot become a silent spectator or keep playing political games and making accusations politically. This is not correct.

Sir, another point is, many atrocities are being perpetrated on the Marathi-speaking people in the disputed region of Belgaum at the Maharashtra-Karnataka border. I am not saying that BJP is right or the Congress is right; I am not getting into that. But if Marathispeaking people in the border areas — they are also living in India; they are not residing outside India — are being *lathi-charged* and fired at, then it is for the Central Government to intervene and provide them justice.

Sir, there are many issues that I would have loved to speak about, but I know time is running out. I would like to raise only one important national issue. In the first speech after UPA-II came to power, the then hon. President had given a balance-sheet of what the Government would do in 100 days. I am not getting into the days' business. The Right to Education Act was passed and with great fanfare, the hon. President had dedicated it to the nation, saying that no child between seven and 14 years of age will be deprived of his or her opportunity or right to get educated. Sir, three years have passed. If this was the target to be achieved, how many schools should have been opened by now? It is the responsibility and duty, moral and legal, of the Government to come up and tell the House as to how many new schools have been opened, how many school buildings have been constructed, how many new teachers have been appointed, etc. But nothing has happened. बस बोल दिया। वोट ले लिए, बोल दिया। What is this? How can you keep fooling the people day after day, year after year, decade after decade?

[Dr. Bharatkumar Raut]

Sir, this is not correct. On the same line, the Right to Education has gone haywire. Now, we are talking about food security. It is another issue that is going to fool the people. Our Agriculture Minister had the courage to say that it is a difficult thing. Why are we giving false promises to the people? Giving just false promises may, perhaps, yield votes for you in one or two elections. What about the next election? What are you going to achieve by doing this? Instead, you must come out and say that this is the thing which you can do and this is the thing which you cannot do; we are into the era of corruption from within and, therefore, we cannot do this. Sir, this type of courage I was waiting, hoping for and was eager to hear from the hon. President in his Presidential Speech. But that has not happened. Therefore, I am totally disgruntled at the speech, and I don't want to oppose it also because there is nothing to oppose also. If there is nothing to support, there is nothing to oppose also. I only express my displeasure about the Speech.

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संदर्भ में कई महानुभावों ने इस सदन में अपनी धारणाओं को, अपनी चिंताओं को, अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि जो शब्द महामहिम राष्ट्रपति जी के मुख से प्रस्फुटित हुए हैं, उनके पीछे का लेखन और चिंतन, भारत सरकार का है। महामहिम ने अपने भाषण में नौजवानों और महिलाओं का उल्लेख किया है। जब इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई, तब आंकड़ों के माध्यम से भारत के वर्तमान की चिंता और भविष्य की कल्पना को देश के सामने उजागर किया गया। आज कुछ आंकड़े मैं भी अपने शब्दों में समेटकर लाई हूं। In a nation where 60 per cent of the population is below the age of 35, when we speak about realization of the dreams and the aspirations of our youth, we need to understand that those aspirations and dreams can be fulfilled only when the Government of India effectively contributes to our economy, our polity and our society. Sir, today, when we speak about the State of our economy, how does the Indian youth perceive the Indian economy? Today, the Indian youth sees that this nation has lost 5 million jobs in the past five years; today the Indian youth sees that 34 per cent of the Indian labour force is either unemployed or under-employed; today the nation's youth sees that in our country, when we speak about the BPO sector, it is unfortunate that in the global BPO sector India's share has dipped by 10 per cent. And when the Indian youth looks for answers, he finds that by December 2012, as the Government of

India has stated, in six sectors in our economy which include electricity and roads, 80 per cent projects are stalled. आज श्री डी.पी. त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में एक वाक्य कहा था "that statistics don't please everybody." मैं उनकी इस बात का समर्थन करती हूं। जब त्रिपाठी जी differently-abled के बारे में बोल रहे थे, तब मैं सोच रही थी कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत में हम आज तक differently-abled के बारे में, पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक accurate Census data प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हम कुपोषण की बात करते हैं, malnutrition की बात करते हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि National Health Survey No. 3 यानी 2005 के आंकड़ों के आधार पर हम 2013 में malnutrition की बात करते हैं। Sir, an up-dated youth in this country is sought to be served by a Government on the basis of out-dated data.

रेणुका जी आज सदन में नहीं हैं। कल उन्होंने इस सदन में कहा कि वे किसान हैं, इसलिए आज अगर वे सदन में होतीं, तो मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करती कि हमारे देश में आज भी दो-तिहाई नौजवान गांवों में रहते हैं। जो नौजवान गांवों में रहते हैं, वे भारत की सरकार से पूछते हैं कि साढ़े छः दशक बाद भी आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम हर गांव तक agricultural literacy क्यों नहीं पहुंचा पाए हैं? आज गांवों के वे नौजवान पूछते हैं कि क्यों वे agriculture की ओर आकर्षित हों, जब agricultural sector में we have lost 14 million jobs? क्यों वे agriculture की ओर आकर्षित हों, when they see that 41 per cent of small farmers are in debt, कर्ज़े में डूबे हुए हैं? I am sure if Renuka*ji* was here today, she would support me in saying that you can never plough a field by turning it over in your mind. If we seriously seek to attract the Indian youth towards agriculture, what do we need to do? We need soil testing labs in every village; we need agricultural scientists in every district; and, we need more investment in agricultural R&D. अगर आप पिछले नौ सालों के आंकड़े देखें, तो पाएंगे that public sector R&D spending in agriculture in comparison to agricultural GDP has been a mere 0.5 per cent. जब देश में NSSO के आंकड़े यह कहते हैं कि 40 प्रतिशत किसान अब खेती नहीं करना चाहते और जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण को पढ़ती हूं, तो surprisingly उसमें एक phrase पाती हूं and I quote, "There is reason for cheer on the agricultural front". If seems, in jubilation, the Government of India forgot about the State of Maharashtra.

महोदय, महाराष्ट्र में 6000 गांव सूखे की चपेट में हैं, जिनमें से 75 गांवों ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को 11 रुपए का मनीऑर्डर भेजा है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि भले ही उनका गांव सूखे की चपेट में है, लेकिन वे अभी भी जिंदा हैं। वहां जालना में 45 days में एक दिन पीने का पानी आता है। भिवंडी और ठाणे में पानी के टैंकर से पीने का पानी लेते-लेते दौड़-भाग में छः बच्चे मर जाते हैं और यहां भारत सरकार शब्दों का

[श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी]

जाल बुनकर अपनी पीठ थपथपाती है और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में महाराष्ट्र के सूखे को भूल जाती है।

महोदय, इस सरकार में भूलने की आदत कई लोगों को पहले से ही है। मुझे अभी भी याद है, जब मीडिया के बंधुओं ने Agusta Westland के स्कैम के बारे में भारत के गृह मंत्री से उनकी टिप्पणी मांगी, तो भारत के गृह मंत्री ने कहा कि लोग बोफोर्स भूल गए थे, यह भी भूल जाएंगे और घोटालों की बात छोड़िए, अगर आज मैं पूर्वोत्तर के किसी नौजवान से मिलती हूं, तो पूर्वोत्तर का नौजवान हमसे कहता है कि भारत की सरकार तो हमें कब का भुला चुकी, वरना क्या यह संभव था कि साढ़े छ: दशक की आज़ादी के बाद भी मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन पांच राज्यों की राजधानियों को आज भी रेल के माध्यम से हम पूरे देश से जोड़ नहीं पाए हैं?

महोदय, भूलने की आदत इस सरकार में लोगों को इतनी है कि जब बंगलादेशियों ने असम में हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण किया, हिन्दुस्तानियों को उनके घरों से बाहर खींचकर उनके घरों को जला दिया, 3 लाख 60 हज़ार हिन्दुस्तानी जब कोकराझार और धुबरी में कैम्पों में रहने पर मजबूर हो गए, तब भारत सरकार दो दिन तक आर्मी भोजना भूल गई।

महोदय, आलम तो यह है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सरपंचों का भी उल्लेख नहीं है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सरपंचों ने लोकतंत्र पर विश्वास दिखाया। यहां पर अगर किसी को याद रहा, तो एक परिवार के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पण करना याद रहा। स्वभाविक है कि जिस राजनीतिक पार्टी में परिवार के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर ही राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता हो, उस पार्टी में स्वाभाविक है कि आप परिवार को प्रणाम करें, लेकिन बड़ी विनम्रता से आज इस सदन में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जिस नौजवान का सरहद पर सिर काटा गया, उस नौजवान के परिवार ने आज तक न सदन में, न सड़क पर, इस राष्ट्र पर अपना एहसान जताया है। जिस बेटे के शव को पाकिस्तान आर्मी ने mutilate किया, उस सौरव कालिया के पिता ने आज तक इस राष्ट्र पर एहसान नहीं जताया है। अगर उम्मीद की है, तो सिर्फ इतनी कि उन्हें न्याय मिलेगा और भारत की सरकार ने ऐसे परिवार को क्या दिया? भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो गई और जब गेंद पर तालियां पड़ीं, तो तालियों की गड़गड़ाहट में हमारी यह सरकार भूल गई कि शहीदों के परिवार आज भी इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।

महोदय, जब बात इंसाफ की होती है तब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पढ़ती हूं, "Protection of *Women* against *Sexual Harassment* at *Workplace Bill"* के बारे में। इस सदन में जब इस बिल पर चर्चा हुई थी, तब मैंने सरकार से आग्रह किया था कि शायद आज़ाद हिन्दुस्तान में पहली बार एक ऐसा कानून आ रहा है, जिसमें अगर महिला को sexually

harass किया जाता है तो कानून में प्रावधान है कि accused के साथ आप settlement कर सकते हैं। क्या यह deterrent factor है, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं? कल रेणुका जी ने यहां पर बात की थी कि महिला को राजनीति में किस प्रकार से आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने की जरूरत है। आज मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि आप 33 परसेंट आरक्षण का बिल लोक सभा में लाइए - आप आगाज़ तो कीजिए, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे।

कल आदरणीय लीडर ऑफ ओपोज़िशन, श्री अरुण जेटली जी ने इस सदन से कहा कि let us immediately pass legislation which ensures the dignity and security of women in our nation. मुझे यकीन है कि हम सब अरुण जी की इस बात से सहमत हैं। जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई तो हम सब एक स्वर में बोले। सरकार के मंत्री भी बोले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है, लेकिन यह सरकार भारत की जनता को यह बताना भूल गयी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए जो budgetary allocation होता है, जो आर्थिक प्रबंधन होता है, उसको इसी सरकार ने अप्रैल, 2011 में बंद कर दिया था। जब दिल्ली की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो दिल्ली की मुख्य मंत्री जंतर-मंतर पर जाकर मोमबत्ती जलाकर आयीं। टीवी डिबेट्स में उन्होंने अपनी संवेदना को, अपनी व्यथा को व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने देश की जनता को यह नहीं बताया कि धूलीचंद नाम का एक रेपिस्ट है, जो उम्रकैद की सज़ा काट रहा है। उस रेपिस्ट को parole न मिले, ऐसा सुझाव दिल्ली पुलिस ने दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के सुझाव को ठुकराते हुए दिल्ली की मुख्य मंत्री ने एल.जी. से ऐसे रेपिस्ट के parole की गुहार लगायी। यह बताना वे भूल जाते हैं। महोदय, जब मैं ये बातें याद दिलाती हूं तो कुछ लोग मुझे हिदायत देते हैं कि स्मृति, इतिहास के पन्नों को पलटना छोड़ दो और आगे देखो। आगे बढ़ो और जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें संग लेकर चलो। हमने यह प्रयास भी किया। गुजरात सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने हमारे प्रयास में हमारा साथ नहीं दिया। हमने गुजरात सरकार की ओर से भारत सरकार से कहा that we are a power-surplus State, we want to help those States who have deficiency in generating or providing power to its citizens. हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप Inter-regional Power Transmission Corridors को सशक्त करिए ताकि कोई constraint न रहे और हम दक्षिण भारत में जितने प्रदेश हैं, चाहे वह केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, अगर वहां पर जरूरत हो तो हम अपना surplus power वहां पहुंचा सकें। महोदय, फरवरी, 2011 में गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा। फरवरी, 2013 में पॉवर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गुजरात के मंत्री ने इस निवेदन को दुबारा दोहराया, लेकिन आज तक भारत सरकार से जबाव नहीं आया। फिर भी गुजरात के मुख्य मंत्री ने कहा कि

"*माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है?*"

आज मैं भारत सरकार से कहती हूं कि भले ही आप भ्रष्टाचार और महंगाई का अंधकार पूरे देश में फैलाएं लेकिन हम भाजपा शासित प्रदेशों में प्रगति का दीप जलाएंगे और भारत मां

[श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी]

को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, रेणुका चौधरी जी के प्रस्ताव का समर्थन न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 21 फरवरी को संसद के समक्ष जो अभिभाषण प्रस्तुत किया और उस पर श्रीमती रेणुका चौधरी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया, मैं उसका समर्थन करती हूं। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रपति महोदय के प्रति विशेष अनुगृहित हैं कि उन्होंने अपना विद्वतापूर्ण एवं तथ्ययुक्त अभिभाषण यहां पर प्रस्तुत किया, जिसमें हमारे राष्ट्र की नीति, कार्यक्रम, उपलब्धियों और चुनौतियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरे राष्ट्र के लिए एक अवसर होता है जिसमें सिंहावलोकन होता है कि राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हों। यह वह अवसर होता है कि हम सब इस बात का चिंतन करें कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, जिनका हमें सामना करना है।

मैं राष्ट्रपति महोदय के उस वाक्य का उल्लेख करना चाहती हूं जिसमें उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है, एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होगी।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए हैं जो हमारे विकास का सूचकांक है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि कृषि के क्षेत्र में हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले ज्यादा विकास दर हासिल की है। पिछले दो वर्षों में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन लगभग 260 मिलियन टन हुआ है। यह उपलब्धि हमें देश के अन्नदाता किसानों की मेहनत और सरकार की सहायक नीतियों के बूते पर हासिल हुई है। यूपीए सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसान की उपज का सही मूल्यांकन हो, उसकी लागत की सही मायने में उसको कीमत मिले और उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की चीज़ें अच्छी क्वालिटी की, कम दाम पर, सस्ते दाम पर मिलें। इसके साथ-साथ लाखों लोगों को इससे रोजगार मिले, इस मकसद के लिए सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश करने का फैसला लिया है। देश में फसल की पैदावार को संरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, बड़े गोदाम, भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। देश में कोल्ड चेन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रशीतन श्रृंखला विकास केन्द्र की भी स्थापना की गई है। इसके साथ ही साथ "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" प्रारंभ किया गया है। सरकार ने "सार्वजनिक निजी भागीदारी" के अंतर्गत गोदामों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत अगले दो वर्षों में देश में लगभग 181 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन होगा। इसी के साथ ही हमारे लिए गर्व की बात है कि 2011-12 में 128 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ

है। इससे भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनने जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-1 का अनुमोदन किया है जिससे वर्ष 2016-17 तक 150 मिलियन टन दूध की मांग पूरी की जा सकेगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 12वीं पंचवर्षीय योजना में परती क्षेत्रों के विकास के लिए भी योजना बनाई गई है। इसमें मेरा शासन से यह निवेदन है कि परती क्षेत्रों में जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके पास मात्र दो-ढाई बीघा जमीन होती है और वे वर्षा के ऊपर निर्भर रहते हैं, अगर ईश्वर ने चाहा और वर्षा ठीक हुई, तो फसल ठीक हो जाती है, अन्यथा वे आपदा से परेशान होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि परती क्षेत्रों में विकास की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। वहां पर watershed प्रबंधन की आवश्यकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, अगर त्वरित सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध होंगे, तो उन गरीब किसानों को, जो छोटी जाति के किसान हैं, उनको इससे लाभ मिल सकेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि 2012-13 में "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि" के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार की जा रही है, उसके लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे गांव के कमजोर तबकों को, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को साफ पानी मिल सकेगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि इस तरह की योजनाओं में गांव को एक यूनिट मानकर, उस बसावट को पूरा कर लिया जाता है। इनमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग एक गांव के एक तरफ रहते हैं, पूरे गांव की गंदगी उनके यहां से होकर जाती है। आज भी हम उनके लिए इतना प्रावधान तो कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में आज उनको स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। वे लोग खेतों में जाकर वही गंदा पानी पीते हैं। गांव की जितनी भी गंदगी उनके कुओं के अंदर जाती है, वही गंदा पानी वे पीते हैं। मेरा आप से यही निवेदन है कि उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यह जो "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि" रखी है, इसके अंतर्गत हम उनको ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकें।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, खेती की चाल, चेहरा और चरित्र बदल रहा है। आज हमारा किसान परम्परागत खेती से हटकर, नई टेक्निक से खेती कर रहा है। मेरा आप से यह निवेदन है कि सरकार किसानों के समर्थन में काफी योजनाएं ला रही है, जैसे "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" है, "दलहन योजना" है, "राष्ट्रीय कृषि योजना" है, "मैकामेनेजमेंट कृषि यंत्रीकरण योजना", "आइसोपाम योजना", "एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम" और "बीज ग्राम योजना" है। इतनी योजनाओं

[डा. विजयलक्ष्मी साधौ]

के बावजूद भी किसान की माली हालत बेहद कमजोर है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खेती...**(व्यवधान)**... मैंने आपको टोका नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझे बोलने दिया जाए। खेती लाभ का धंधा बने, किसानों को उनकी लागत के अनुरूप फसल की कीमत मिले, इसके लिए यूपीए सरकार ने किसानों की पैदावार के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की है। दलहन, तिलहन की फसलों के समर्थन मूल्य में पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। चने और मसूर के समर्थन मूल्य में चार सौ रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। पिछले साल दलहन की फसलों का मूल्य करीब 2800 रुपए था, जो बढ़कर अब 3200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इतना सब होने के बाद भी आज किसान की हालत जितनी तेजी से ठीक होनी चाहिए थी, उतनी तेजी से ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि कहीं न कहीं डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों, खाद, बीज और मार्केटिंग की परेशानियों से किसान घिरा हुआ है। मौसम के मिजाज के कारण किसानों की चिंता बढ़ रही है। आजकल मौसम का मिजाज ऐसा हो गया कि एक खेत में पानी गिरता है, उसी के पड़ोस में दूसरे खेत में पानी नहीं गिरता है। किसान जितनी मेहनत करता है, इसकी वजह से किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह निवेदन है कि पाले व ओले की वृष्टि से किसानों की फसलों का जो नुकसान होता है, उस नुकसान के आकलन का जो जरिया है, वह बहुत पुराना है और उसके अंतर्गत किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। पहले किसान की प्रति एकड़ फसल कुछ और होती थी। आज किसान अपनी कड़ी मेहनत से जो प्रति एकड़ फसल उगाता है वह पहले ही अपेक्षा करीब-करीब कई गुना ज्यादा फसल लेता है। मेरा यह निवेदन है कि जो फसल की नुकसानी का आकलन होता है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि अगर किसान की फसल बर्बाद होती है तो इससे उसको लाभ मिल सके।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 2013 की सरकारी एजेंसियों के पास करीब 662 लाख टन खाद्यान्न एकत्रित हुआ है, जिसमें करीब 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल है। देश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए और हर गरीब को सस्ता और पर्याप्त राशन मिले, इसके लिए यूपीए सरकार ने "खाद्य सुरक्षा बिल" तैयार किया है, जिसे पारित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुनकरों के पैकेज के लिए आकर्षित करना चाहूंगी। हथकर्घा हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के बाद हथकर्घा देश का दूसरा सबसे बड़ा असंगठित आर्थिक क्षेत्र है।

पूरे देश के अंदर इस क्षेत्र में करीब 48 लाख करघे हैं, जिनमें करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इनमें से 32 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/जनजाति और माइनॉरिटी

के हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें करीब-करीब 60 प्रतिशत महिलाएं लगी हुई हैं। देश के कुल कपड़ा उत्पादन का करीब एक-चौथाई इसी क्षेत्र में होता है, साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देश भर में भी रोजगार मिला हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि हथकरघा क्षेत्र के सामने कई समस्याएं भी आती हैं, जिनमें वे अभी भी, कहीं-कहीं पुरानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना डिजाइन बनाते हैं, इसलिए इनके नये डिजाइनों, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान की दिशा में ध्यान देने की भी आज आवश्यकता है। इसके साथ ही इसकी भी जरूरत है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बुनकरों को समय पर समुचित ऋण मिले। इसके साथ ही उनको जिस रॉ मैटीरियल की जरूरत होती है, जैसे यार्न, डाई, रसायन जैसी सामग्री, जो कि उन्हें बाहर से बहुत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है, उसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन बुनकरों को ये सुविधाएं, जैसे कि रॉ मैटीरियल आदि हैं, मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही साथ, उसका जो तैयार उत्पाद है, उसको बिचौलियों से बचाना है, क्योंकि गांव के अंदर वह जो सामान बनता है, शहरों में आते-आते उस सामान की लागत कई गुणा बढ़ जाती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा इंतजाम करने की आवश्यकता है कि तैयार उत्पादों पर मुकम्मल बाज़ार हो।

उपसभाध्यक्ष जी, यूपीए सरकार ने इन बुनकरों को आर्थिक सहायता भी दी है। करीब 10 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ देने की योजना है ताकि वे कर्ज़ लेकर अपनी रोजी-रोटी ठीक से चला सकें। सरकार की कोशिश है कि बुनकर क्षेत्र का तेजी से और सही दिशा में विकास हो। इस बाबत पिछले दिनों आदरणीय राहुल जी के प्रस्ताव पर बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों के कर्ज़ माफ़ किए गए थे। बुनकरों को 3 साल की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिसमें सस्ती दरों पर धागों के लिए मार्ज़िन मनी के लिए 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का कर्ज़ मिल सकेगा। बुनकरों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी बुनकर क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई जाएगी। सरकार ने अभी तक जो संस्थागत (सोसायटीज) हैं, उन बुनकरों के लिए कर्ज़ माफ़ी की योजना बनाई है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सोसायटीज के साथ-साथ बहत से इन्डिविजुअल बुनकर भी इसमें लगे हुए हैं, इसलिए सरकार उनके लिए भी इन्डिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कर्ज़ माफ़ी की योजना बनाए ताकि उनको भी लाभ मिल सके।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी 2005-06 से 2012-13 तक करीब 43,500 से अधिक नए निर्माण उन्नयन का कार्य स्वास्थ्य विभाग ने किया है, जिसमें 70,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मी नियोजित किए गए हैं।

जननी सुरक्षा योजना के तहत करीब 1.1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। देश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में इन दिनों काफी कमी आई है। पिछले 5 वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 46 प्रतिशत, पोस्ट ग्रेजुएट में 70 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और 200 से अधिक नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी दी गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन कि उन्होंने एमबीबीएस की सीटों पर 46 प्रतिशत वृद्धि, पी.जी.

[डा. विजयलक्ष्मी साधौ]

की सीटों में 70 प्रतिशत वृद्धि और 200 नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी तो दी है, जो कि इस देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ इनसे निकलने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज़ इसी देश में अपनी सेवाएं दें और खास कर के रिमोट एरिया में अपनी सेवाएं दें, सरकार को इस तरह के कानून बनाने और इस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यदि आज भी हम रिमोट एरिया छोड़ दें, लेकिन जो ब्लॉक हैडक्वार्टर है, तहसील हैडक्वार्टर है, जो मीडियम दर के स्तर पर हैं, वहां पर जितनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, हम आज भी उतनी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि यह कारगर सिद्ध हो। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम सीटें बढ़ा रहे हैं, हम कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन इनसे निकले हुए विद्यार्थी उसी देश को सर्विस दें, उसी एरिया को सर्विस दें, इस बात को सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है।

मैं एक और बात कहना चाहूंगी। स्मृति जी यहां से चली गई हैं, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर हमें विकास की बात करनी है, तो दलगत राजनीति से उठ कर बात करनी है। अगर कोई चीज अच्छी है, तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। यहां उन्होंने बीजेपी राज्यों की बात की कि हमारे बीजेपी के राज्य उजाला करेंगे। मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, जहां से मैं आती हूं, तो माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 8 साल के अंदर 11 हजार किसानों ने खुदकुशी की। अगर हम 8 साल का रिकॉर्ड न लें, अगर हम लोग मात्र 2011 का ही रिकॉर्ड लें, तो यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह विधान सभा में माननीय मंत्री जी का दिया गया जबाव है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2011 में प्रति दिन औसतन 3 किसानों ने आत्महत्या की है। ये उजाला दिखा रहे हैं।...**(व्यवधान)**... ये उजाला दिखा रहे हैं। 86 दिन के अंदर 700 बलात्कार के केसेज़ और उनमें भी...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Let her conclude. When your turn comes, you can speak. ...*(Interruptions)*... Dr. Sadho, kindly come to the point.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : 700 बलात्कार के केसेज़ मात्र 86 दिन के अंदर...**(व्यवधान)**... यह अखबार नहीं, विधान सभा में दिया गया जबाव है।...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने बड़े ध्यान से सुना...**(व्यवधान)**...

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... Kindly listen to me.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : हमने बड़े ध्यान से सुना, आप भी सुनने का माद्दा रखिए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा का रिकॉर्ड है।...**(व्यवधान)**... यह विधान सभा में जबाव दिया गया है।...**(व्यवधान)**...

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : सर, क्या ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रही हैं?...**(व्यवधान)**...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... Kindly listen to me.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Dr. Sadho, please wait. She is on a point of order. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर को संबोधित कर रही हूं।...**(व्यवधान)**... मैं विधान सभा का रिकॉर्ड बता रही हूं। मंत्री ने यह जबाव दिया है।...**(व्यवधान)**... मैंने सुना, आप भी सुनने का माद्दा रखिए।...**(व्यवधान)**... हमने सुना, आप भी सुनें।...**(व्यवधान)**... हमने सुना, आप भी सुनें।...**(व्यवधान)**... यह डॉक्युमेंटरी रिकॉर्ड है।...**(व्यवधान)**... हमने सुना, आप भी सुनें।...**(व्यवधान)**...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Anything that is spoken in the House should be substantiated. ...*(Interruptions)*... Can she substantiate what she is talking about? Sir, you know that any statement made on the floor of the House should be substantiated. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश की भी सुन लें।...**(व्यवधान)**...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, I am on a larger question.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, यह रिकॉर्ड की बात है, मैं रिकॉर्ड की बात कर रही हूं।...**(व्यवधान)**...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: If, on the President's Address, you permit State issues to be raised like this, ...*(Interruptions)*... Recently, there was a protest on the U.P. issue. ...*(Interruptions)*... When a free-for-all is given, then, a lot can be raised by this side as well. This is a debate on the President's Address. ...*(Interruptions)*... I would request you that any reference made about State subjects should be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I will look into the record and do it. Now, Dr. Sadho, please conclude. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, मैंने उनकी बात सुनी है, उनको भी मेरी बात सुननी होगी।...**(व्यवधान)**... यह हवा में की गई बात नहीं है, यह विधान सभा का रिकॉर्ड है।...**(व्यवधान)**... सर, मुझे बोलने दिया जाए।...**(व्यवधान)**... सर, मुझे बोलने दिया जाए।...**(व्यवधान)**... सर, उन्होंने महाराष्ट्र की बात की।...**(व्यवधान)**... उन्होंने महाराष्ट्र की बात की।...**(व्यवधान)**... मैं भी मध्य प्रदेश की बात करूंगी।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please continue and conclude it quickly. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, 86 दिन में 700 बलात्कार, सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा नाबालिग बेटियां शिकार बनीं। सर, नवम्बर, 2012 से 25 जनवरी, 2013 तक बलात्कार और सामूहिक

[डा. विजयलक्ष्मी साधौ]

बलात्कार की घटनाएं हुईं...**(व्यवधान)**... यह राज्य के गृह मंत्री का जबाव है।...**(व्यवधान)**... 708 घटनाएं हुईं।...**(व्यवधान)**... यह हाउस के अन्दर दिया हुआ जबाव है।

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, it should not go on record. You kindly give a ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Already, the Deputy Leader of the Opposition has made a point. I will look into the record. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : यह गृह मंत्री जी का जबाव है।...**(व्यवधान)**... यह गृह मंत्री का दिया हुआ जबाव है।...**(व्यवधान)**...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I have no problem if this is not stopped. But then the rest of the speakers from my party will speak about the Congress (I)-ruled States only, and nobody can stop them. ...*(Interruptions)*... They will only speak about the rule of the Congress (I) Governments in the States. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : आप महाराष्ट्र की बात करेंगे और मध्य प्रदेश की नहीं सुनेंगे ! ...**(व्यवधान)**... यहां महाराष्ट्र की बात होगी और मध्य प्रदेश की बात नहीं होगी ! ...**(व्यवधान)**... आप महाराष्ट्र की बात करेंगे और हम मध्य प्रदेश की बात न करें !...**(व्यवधान)**... सुनने का माद्दा रखिए।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down. Dr. Sadho, you please come to the President's Address. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, मैं अपनी बात कहूंगी।...**(व्यवधान)**...

श्रीमती माया सिंह : सर, मैं विजयलक्ष्मी जी से कहना चाहती हूं कि वे दिल्ली के आंकड़े बताएं।...**(व्यवधान)**... आप दिल्ली के बारे में बोलिए।...**(व्यवधान)**...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं।...**(व्यवधान)**... राज्य के गृह मंत्री ने यह जानकारी दी।...**(व्यवधान)**...

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : दिल्ली में कोई भी चीज़ गलत होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्ट कन्डेम करते हैं...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down. Kindly come to the point and conclude. Your time is already over. Please...*(Interruptions)*...

श्री परवेज़ हाशमी : दिल्ली के लिए हमारे प्राइम मिनिस्ट कन्डेम करते हैं...**(व्यवधान)**... आपमें तो सुनने की...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly come to the point and conclude. Your time is already over. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, अपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मो. नदीमुल हक (पश्चिमी बंगाल) :

ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में,
वक्त की शाख को हिलाना होगा।
कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा करने से,
अपने हिस्से का चिराग़ खुद जलाना होगा।

वाइस चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुशतरका इजलास से सदर-ए-जमहूरिया, मोहतरम प्रणब मुखर्जी का ख़िताब जामे था, जहां उन्होंने यूपीए हुकूमत के कारनामों का अहाता और कई सारी स्कीमों और प्रोजेक्टों को अहैया किया। हमारा मक़सद सदारती खुतबे की नुक्ताचीनी नहीं है, मुश्किल यह है कि आपको तो जो लिस्ट पकड़ा दी जाती है, उसे पढ़ देना पड़ता है। हम सोच रहे थे कि हुकूमत इस बार कुछ ऐसे वादे और इरादे के साथ सामने आती, जिन्हें हकीक़त का आइना दिखाया जा सके, मगर यहां भी वही फिक्शन है, वही ख़याली पुलाव, जिन्हें पिछले बार के सदर के खुतबे में उठाया गया था, लेकिन अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। सदारती खुतबे की मुकम्मल तौर पर सताइश और सराहना मुमकिन नहीं और हम इस ऐवान की तवज्जो चन्द हक़ायक की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल में यकसा तौर पर अहम और क़ाबिले तवज्जो हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि सदारती खुतबे में अच्छी-अच्छी बातें की गईं और अच्छे-अच्छे ख्वाब बुने गए। लेकिन मैं यह सवाल करता हूं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है? जनाब सदर ने यूपीए हुकूमत की अनगिनत स्कीमों और मनसूबों को अपने ख़िताब में गिनवाया है। गरीबी हटाना है और गरीबों की सतह गरीबी से उठाना है, मगर यह सबको मालूम है कि इन स्कीमों के तहत मुख़तस रक़म का शायद 20 फीसदी हिस्सा भी हक़दार तक नहीं पहुंचता। अपने खुतबे में मुअज़्ज़िज़ सदर ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तारीफ की है। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस मामले में हिन्दुस्तान की कारगुज़ारी काफी अच्छी हुई है, लेकिन फिर क्या वजह है कि गरीब किसान, जो मां, माटी और मानुष से जुड़ा हुआ है, वह आज भी भूखा सोता है।

वाइस चेयरमैन साहब, सदारती खुतबे में फ़ख्र के साथ इंदराज किया गया है कि हमारे मुल्क में मिल्क प्रोडक्शन दुनिया के अंदर अव्वल नम्बर पर है, जहां 2011-12 में 128 मिलियन मीट्रिक टन दूध की पैदावार हुई है। लेकिन इसी हिन्दुस्तान में गरीब के बच्चे मालन्युट्रिशियन का शिकार हो रहे हैं। कम खुराक की वजह से मां अपने बच्चों को दूध पिलाने से क़ासिर है, लिहाज़ा भूखी मां के बच्चे भी भूखे सोते हैं। हिन्दुस्तान के तरक्कियाती एजेंडे में अक्लियतों और खुसूसन मुसलमानों की सलामती, आजादी और मसावी मौके यानी equal opportunity के मसले अब भी नुमाया हैं। अक्लियतों की माशी, समाजी और तालीमी पसमांदगी मुख़तलिफ़ सतहों पर बहस का मौजू बन चुकी हैं और मुल्क के सेकुलर सियासी जमातों की जानिब से इसे

4.00 P.M.

[श्री मो. नदीमुल हक]

तस्लीम भी कर लिया गया है। मगर जब तक इन मसाइल को मुन्सिफाना तौर पर हल नहीं किया जाता, तब तक हुकूमत के वादों का शुमार ज़ुबानी जमाख़र्ची में होगा।

सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन पर मुख़्तलिफ़ तामीरी और मस्बत प्रोग्राम के ऐलानात किए गए, मगर कमोबेश वो महज़ दग़ाई वादे साबित हुए हैं और मुल्क़ की अक्लियतों की हालत दिन-ब-दिन बद से बदतर हो रही है। हम यहां जरूरी समझते हैं कि गिनवा दें कि मग़रिबी बंगाल, जहां अक्लियतों की आबादी लगभग तीस फीसदी है, में पिछले 20 महीनों में क्या-क्या इकदामात उठाए गए हैं। ममता हुकूमत के इक्तिदार में आने के एक हफ्ते के अंदर उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने का ऐलान किया गया, जिसे पिछले साल रियासती असेम्बली में "The Official Languages Act" में तरमीम करके बाज़ाबता क़ानूनी शक्ल दी गई। रियासती बजट में अक्लियती फंड को बढ़ा कर दुगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है।

राजरहाट में 5 एकड़ जमीन पर मुशतमिल रियासत के तीसरे हज हाउस की तामीर जल्द शुरू होने वाली है। हम सब लोग वाक़िफ हैं कि वक्फ जायदाद पूरे मुल्क में घपले और कब्ज़े के नरग़े में है। ममता हुकूमत ने इस ज़मरे में न सिर्फ सीआईडी बल्कि सीबीआई इन्क्वायरी का भी हुक्म दे दिया है।

आलिया युनिवर्सिटी को अक़लियती किरदार के साथ-साथ 20 एकड़ ज़मीन और 200 करोड़ रुपए का कॉरप्स अदा किया गया है। मग़रीबी बंगाल के 10 हजार मदरसों को अकलियती किरदार देने का एलान किया गया है, जिसकी वजह से अब वहां स्टाफ की बहाली में एससी और एसटी की बंदिश नहीं रही। 'वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन', जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूं, कि कारकर्दगी पूरे मुल्क में अव्वल नम्बर पर है। ओबीसी के तहत रिजर्वेशन को बढ़ा कर 17 फीसदी कर दिया गया है और साथ-साथ रियासत की 85 फीसदी मुस्लिम आबादी का इंदराज इसी लिस्ट में भी हुआ है। लिहाज़ा, अगर देखा जाए तो हक़ीक़त में मुसलमानों के लिए बंगाल में 10 फीसद से ज्यादा रिजर्वेशन है। हमारी हुकूमत ने रियासत के सारे कब्रिस्तानों की दीवार की तामीर और मरम्मत के काम की जिम्मेदारी भी कुबूल की है, जो पिछली सीपीएम हुकूमत के 34 साला दौर-ए-इक्तिदार में नहीं हुआ। ममता हुकूमत ने ये सारे कारनामे सिर्फ 20 महीनों में अंजाम दिए हैं। ऐसे में हम मग़रीबी बंगाल के लोगों की जानिब से हमारी दीदी ममता बनर्जी पर यह शेर नज़र करते हैं कि

बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम,
सौ बार ले चुका है तू इम्तिहां हमारा।

जब से यूपीए सरकार इक्तेदार में आई है, पिछले साल यानी 2012 में दंगों का रिकॉर्ड ही टूट गया है। पूरे मूल्क में फिरक़ापरस्त ताक़तों ने सर उठाया है। जब दंगे होते हैं, तो आग भड़कती है और शोले लपकते हैं। वह कोई हिन्दू या मुसलमान या सिख या ईसाई थोड़ी ही देखते हैं! खून किसी का भी हो, मौत तो एक हिन्दुस्तानी की होती है। वह हिन्दुस्तानी, जो कभी फख

से गाता होगा- 'हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।' इसलिए, यह लाजिमी बन जाता है कि मुल्क इस लानत से छुटकारा पाने के लिए मुल्तकिल हल तलाश करे। मुल्क भर में अलग-अलग ब्लास्ट्स के शुबहे में अक़लियतों के नौजवानों को, जो इस मुल्क के मुस्तक़बिल हैं, जुर्म-बेगुनाही के लिए जेलों में ठूंस दिया जाता है। पकड़ कर तो पुलिस ले जाती है, लेकिन जब छोड़ने-छुड़ाने की बात आती है, तो मेम्बरान-ए-पार्लियामेंट के डेलिगेशन को वज़ीरेआजम से दर्ख्वास्त करनी पड़ती है। जब तक ये नौजवान अपनी बेगुनाही साबित कर पाते हैं, तब तक उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुज़र चुका होता है और ये अब सोशल मिसफिट बनकर रह जाते हैं।

ऐसे सदारती खिताब का किस तरह स्वागत किया जाए? आपने मेजें थपथपाई हैं - हमारे जख्मों पर। वाइस चेयरमैन साहब, सदारती खुतबे में स्लो ग्रोथ रेट पर तशवीश जाहिर की गई और कहा गया कि अन्दरुनी और बेरुनी वजुहात के बिना पर हमारी इकॉनमी को झटका लगा है। मुझे हैरत होती है कि जहां रोज नए-नए घपले और घोटाले सामने आ रहे हैं, वहां हुकूमत का यह रोना है। अगर सिर्फ काले धन की रक़म मुल्क की तरक्की में खर्च होती, तो हम यह रोना नहीं रोते। न खेल का मैदान छूटा न हवाओं की लहरें, अब तो हवा में चकराने वाले हेलिकॉप्टर का भी चक्कर सामने आया है। वह दिन दूर नहीं कि हमें कहना पड़ेगा- 'सारे जहां से महंगा, हिन्दोस्तां हमारा।' लिहाज़ा, मैं हुकूमत से डिमांड करता हूं कि वह 'इकनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ करॅप्शन' पर एक पेपर जारी करे। हमें पता तो चले कि बदउनवानी हमारी जड़ें कहां-कहां खोखली कर रही हैं।

यूपीए हुकूमत को क्या कहें, आप तो अपने साथियों को भी साथ लेकर नहीं चल सकते। जब भी हुकूमत पर आफत आती है, तो सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Your time is over.

श्री मो. नदीमुल हक : शायद इस एदारे का नाम 'सेंटर बचाओ इंस्टीट्यूट' होता, तो बेहतर होता, लेकिन इसका असर अगर किसी पर नहीं चलता है, तो वह मग़रीबी बंगाल की वज़ीरेआला ममता बनर्जी हैं। यूपीए ने मुल्क के लाखों छोटे कारोबारियों के पेट पर मारने के लिए एफडीआई की लात उठाई है। देश की जनता के साथ हम विश्वासघात नहीं कर सके, लिहाज़ा हमने इक्तिदार ठुकरा दिया और यूपीए मरकज़ में माइनॉरिटी में आ गए। इन सारे उमूर पर सदारती खुतबे की खामोशी चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि सच्चाई कड़वी होती है। देश की जनता सब देख रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसान के साथ नहीं है, अगर गरीब के साथ नहीं है, अगर मजदूर के साथ नहीं है, अगर मिडिल क्लास के साथ नहीं है, अगर अक़लियतों के साथ नहीं है, तो यूपीए का हाथ आखिर है किसके साथ?...(**व्यवधान**)...

सर, अब मैं बस इतना ही और कहूंगा कि

मैं आ गया हूं, मगर खाली हाथ आया हूं।
हमारे ख्वाब थे ऐसे कि साथ न ला सके,
चले चलो कि वह मंजिल अभी नहीं आई।

खुदा हाफिज़, जय हिन्द।

جناب محمد ندیم الحق (مغربی بنگال) :

خواہشوں سے نہیں گرتے پھول جھولی میں
وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا
کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے
اپنے حصے کا چراغ خود جلانا ہوگا

وائس چئیرمین صاحب، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ، محترم پرنب مکھرجی کا خطاب جامع تھا، جہاں انہوں نے یوپی۔اے۔ حکومت کے کارناموں کا احاطہ اور کئی ساری اسکیموں اور پروجیکٹوں کا احیأ کیا۔ ہمارا مقصد صدارتی خطبہ کی نکتہ چینی نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ آپ کو تو جو لسٹ پکڑا دی جاتی ہے، اسے پڑھ دینا پڑتا ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ حکومت اس بار کچھ ایسے وعدے اور ارادے کے ساتھ سامنے آتی، جنہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا جاسکے، مگر یہاں بھی وہی فکشن ہے، وہی خیالی پلاؤ، جنہیں پچھلے بار کے صدر کے خطبہ میں اٹھایا گیا تھا، لیکن ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنایا جاسکا۔ صدارتی خطبہ کی مکمل طور پر ستائش اور سراہنا ممکن نہیں اور ہم اس ایوان کی توجہ چند حقائق کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، جو میرے خیال میں یکساں طور پر اہم اور قابل توجہ ہیں۔

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

اس میں کوئی شک نہیں کہ صدارتی خطبے میں اچھی اچھی باتیں کی گئیں اور اچھے اچھے خواب بنے گئے۔ لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جناب صدر نے یو۔پی۔اے حکومت کی ان۔گنت اسکیموں اور منصوبوں کو اپنے خطاب میں گنوایا ہے۔ غریبی ہٹانا ہے اور غریبوں کو سطح غریبی سے اٹھانا ہے، مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ ان اسکیموں کے تحت مختص رقم کا شاید بیس فیصد حصہ بھی حقدار تک نہیں پہنچتا۔ اپنے خطبے میں معزز صدر نے ایگریکلچرل پروڈکشن کی تعریف کی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معاملے میں ہندستان کی کارگزاری کافی اچھی ہوئی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ غریب کسان، جو ماں، ماٹی اور مانش سے جڑا ہوا ہے، وہ آج بھی بھوکا سوتا ہے۔

وائس چئیرمین صاحب، صدارتی خطبے میں فخر کے ساتھ اندراج کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ملک پروڈکشن دنیا کے اندر اول نمبر پر ہے، جہاں 2011-12 میں 128 ملین ٹن دودھ کی پیداوار ہوئی ہے۔ لیکن اسی ہندوستان میں غریب کے بچے مال-نیوٹریشن کا شکا ہورہے ہیں۔ کم خوراک کی وجہ سے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے قاصر ہے، لہذا بھوکی ماں کے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں۔ ہندوستان کے ترقیاتی ایجنڈے میں اقلیتوں اور خصوصا مسلمانوں کی سلامتی، آزادی اور مساوی مواقع یعنی equal opportunity کے مسئلے اب

بھی نمایا ہیں۔ اقلیتوں کی معاشی، سماجی اور تعلیمی پسماندگی مختلف سطحوں پر بحث کا موضوع بن چکی ہے اور ملک کے سیکولر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسے تسلیم بھی کرلیا گیا ہے۔ مگر جب تک ان مسائل کو منصفانہ طور پر حل نہیں کیا جاتا، تب تک حکومت کے وعدوں کا شمار زبانی جمع خرچی میں ہوگا۔

سچر کمیٹی کے ریکمنڈیشن پر مختلف تعمیری اور مثبت پروگرام کے اعلانات کئے گئے، مگر کم وبیش وہ محض دغائی وعدے ثابت ہوئے ہیں اور ملک کی اقلیتوں کی حالت دن بہ دن بد سے بدتر ہورہی ہے۔ ہم یہاں ضروری سمجھتے ہیں کہ گنوادیں کہ مغربی بنگال، جہاں اقلیتوں کی آبادی لگ بھگ تیس فیصدی ہے، میں پچھلے بیس مہینوں میں کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ممتا حکومت کے اقتدار میں آنے کے ایک ہفتے کے اندر اردو کو سرکاری زبان بنانے کا اعلان کیا گیا، جسے پچھلے سال ریاستی اسمبلی میں "The Official Language Act" میں ترمیم کرکے باضابطہ قانونی شکل دی گئی۔ ریاستی بجٹ میں اقلیتی فنڈ کو بڑھاکر دوگنے سے بھی زیادہ کردیا گیا ہے۔

راجرہاٹ میں 5 ایکڑ زمین پر مشتمل ریاست کے تیسرے حج ہاؤس کی تعمیر جلد شروع ہونے والی ہے۔ ہم سب لوگ واقف ہیں کہ وقف جائیداد پورے ملک میں

گھپلے اور قبضے کے نرغے میں ہیں۔ ممتا حکومت نے اس زمرے میں نہ صرف سی۔آئی۔ڈی۔ بلکہ سی۔بی۔آئی۔ انکوائری کا بھی حکم دے دیا ہے۔

آلیہ یونیورسٹی کو اقلیتی کردار کے ساتھہ ساتھہ 20 ایکڑ زمین اور 200 کروڑ روپے کا کارپس عطا کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے 10 ہزار مدرسوں کو اقلیتی کردار دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہاں اسٹاف کی بحالی میں ایس۔سی۔ اور ایس۔ٹی۔ کی بندش نہیں رہی۔ 'ویسٹ بنگال مائنارٹی ڈیولپمینٹ اینڈ فائننس کارپوریشن'، جس سے میں خود جڑا ہوا ہوں، کی کارکردگی پورے ملک میں اوّل نمبر پر ہے۔ او۔بی۔سی۔ کے تحت رزرویشن کو بڑھا کر 17 فیصدی کر دیا گیا ہے اور ساتھہ ساتھہ ریاست کی 85 فیصدی مسلم آبادی کا اندراج اسی لسٹ میں بھی ہوا ہے۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں مسلمانوں کے لئے بنگال میں 10 فیصد سے زیادہ رزرویشن ہے۔ ہماری حکومت نے ریاست کے سارے قبرستانوں کی دیوار کی تعمیر اور مرمّت کے کام کی ذمّہ داری بھی قبول کی ہے، جو پچھلی سی۔پی۔ایم۔ حکومت کے 34 سالہ دور اقتدار میں نہیں ہوا۔ ممتا حکومت نے یہ سارے کارنامے صرف 20 مہینوں میں انجام دئے ہیں۔ ایسے میں

ہم مغربی بنگال کے لوگوں کی جانب سے ہماری دیدی ممتا بنرجی پر یہ شعر نذر کرتے ہیں کہ...

باطل سے دبنے والے اے اسماں نہیں ہم

سو بار لے چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔

جب سے یو۔پی۔اے۔ سرکار اقتدار میں آئی ہے، پچھلے سال یعنی 2012 میں دنگوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ پورے ملک میں فرقہ پرست طاقتوں نے سر اٹھایا ہے۔ جب دنگے ہوتے ہیں، تو آگ بھڑکتی ہے اور شولے لپکتے ہیں۔ وہ کوئی ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی تھوڑی ہی دیکھتے ہیں۔ خون کسی کا بھی ہو، موت تو ایک ہندوستانی کی ہوتی ہے۔ وہ ہندوستانی، جو کبھی فخر سے گاتا ہوگا، "ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا"۔ اس لئے، یہ لازمی بن جاتا ہے کہ ملک اس لعنت سے چھٹکارہ پانے کے لئے مستقل حل تلاش کرے۔ ملک بھر میں الگ الگ بلاسٹس کے شبہ میں اقلیتوں کے نوجوانوں کو، جو اس ملک کے مستقبل ہیں، جرم بے-گناہی کے لئے جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ پکڑ کر تو پولیس لے جاتی ہے، لیکن جب چھوڑنے چھڑانے کی بات آتی ہے، تو ممبران پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن کو وزیر اعظم سے درخواست کرنی پڑتی ہے۔ جب تک یہ نوجوان اپنی

بے۔گناہی ثابت کر پاتے ہیں، تب تک ان کی زندگی کا ایک بڑا حصّہ گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اب social misfit بن کر رہ جاتے ہیں۔

ایسے صدارتی خطاب کا کس طرح سواگت کیا جائے؟ آپ نے میزیں تھپتھپائی ہیں، ہمارے زخموں پر۔ وائس چیئرمین صاحب، صدارتی خطبے میں 'سلو گروتھ ریٹ' پر تشویش ظاہر کی گئی اور کہا گیا کہ اندرونی اور بیرونی وجوہات کی بناء پر ہماری اکانومی کو جھٹکا لگا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جہاں روز نئے نئے گھپلے اور گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں، وہاں حکومت کا یہ رونا ہے۔ اگر صرف کالے دھن کی رقم ملک کی ترقی میں خرچ ہوتی، تو ہم یہ رونا نہیں روتے۔ نہ کھیل کا میدان چھوٹا، نہ ہواؤں کی لہریں۔ اب تو ہوا میں چکرانے والے ہیلی کاپٹر کا بھی چکر سامنے آیا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں کہنا پڑے گا "سارے جہاں سے مہنگا، ہندوستاں ہمارا"۔ لہٰذا، میں حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ 'اکانومک امپیکٹ آف کرپشن' پر ایک پیپر جاری کرے۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ بدعنوانی ہماری جڑیں کہاں کہاں کھوکھلی کر رہی ہیں۔

یو۔پی۔اے۔ حکومت کو کیا کہیں، آپ تو اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ جب بھی حکومت پر آفت آتی ہے، تو سی۔بی۔آئی۔ کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Your time is over.

†**جناب محمد ندیم الحق:** شاید اس ادارے کا نام 'سینٹر بچاؤ انسٹی ٹیوٹ' ہوتا، تو بہتر ہوتا، لیکن اس کا اثر اگر کسی پر نہیں چلتا ہے، تو وہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی ہیں۔ یو۔پی۔اے۔ نے ملک کے لاکھوں چھوٹے کاروباریوں کے پیٹ پر مارنے کے لئے ایف۔ڈی۔آئی۔ کی لات اٹھائی ہے۔ دیش کی جنتا کے ساتھ ہم وشواس گھات نہیں کر سکے، لہذا ہم نے اقتدار ٹھکرا دیا اور یو۔پی۔اے۔ مرکز میں مائنارٹی میں آ گئے۔ ان سارے امور پر صدارتی خطبے کی خاموشی چلّا چلّا کر کہہ رہی ہے کہ سچائی کڑوی ہوتی ہے۔ دیش کی جنتا سب دیکھہ رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسان کے ساتھہ نہیں ہے، اگر غریب کے ساتھہ نہیں ہے، اگر مزدور کے ساتھہ نہیں ہے، اگر مڈل کلاس کے ساتھہ نہیں ہے، اگر اقلیتوں کے ساتھہ نہیں ہے، تو یو۔پی۔اے۔ کا ہاتھہ آخر ہے کس کے ساتھہ؟...(مداخلت)... سر، اب میں بس اتنا ہی اور کہوں گا کہ...

میں آ گیا ہوں، مگر خالی ہاتھہ آیا ہوں،
ہمارے خواب تھے ایسے کہ ساتھہ نا لا سکے،
چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔

خدا حافظ، جے ہند۔

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri K.C. Tyagi, not present.

PROF. M.S. SWAMINATHAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to speak. I rise to support the Motion moved by Shrimati Renuka Chowdhury. While dong so, I want to draw the attention of the House, through you, to three important issues. The first is the food security. I need hardly remind this House that 2013 represents the 70th anniversary of the Bengal Famine in 1943 when, according to estimates, 3 million children, women and men died of hunger. Since that Bengal Famine days, this year, the Parliament has under its

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

consideration the Food Security Bill which makes access to food a legal right. It is not a political patronage, but it is a right. I think, this is a very significant historic occasion when we have this great transition in our agricultural history from one of ship-to-mouth to one of providing a legal right to food, with home grown food. The international prices are very volatile. You can't really implement a Bill of this kind with imported food. It has to be homegrown food. It is in this direction that the President rightly mentioned that our farmers produced, last year, 260 MT of foodgrains, 251 MT of fruits and vegetables and 128 MT of milk. In fact, if you look at these figures, it comes almost to half-a-tonne of fruits and vegetables and foodgrains per individual in this country.

In spite of it, we have extensive malnutrition which is well known, which has been mentioned many times. We have also economic problems faced by farmers and that is why I want to suggest that in the future Economic Surveys—one of the important commitments made in the new National Policy for Farmers placed in this House by the Union Minister for Agriculture and Food in Novemer, 2007 the very first goal is to improve the economic viability of farming by substantially increasing the net income of farmers and to ensure that agricultural progress is measured by advances made in this income. In other words, the progress made in the net income of farmers should be a measure of progress in agriculture. I think, the Economic Survey should bring it out Purely giving progress in million tonnes, at the same time reporting farmers' suicides, farmers' distress, 45 per cent of women and children being malnourished and so on. This is not compatible.

The reason why the economics of farming is getting adverse has been mentioned by several Members. I hardly need to mention this. But, there were two major suggestions made by the National Commission on Farmers. The first recommendation is already met by the Finance Minister—farm loans at 4 per cent including crop loans at 4 per cent interest. This time, the Finance Minister—I thank him—has also mentioned that private sector scheduled commercial banks will also provide the loan at 4 per cent interest. The total credit has been increased to Rs.7 lakh crores. That is a very important step.

The second step we suggested was that the price must be somewhat more than remunerative because in the case of others, we have the Sixth Pay Commission, the Seventh Pay Commission, and so on. The farmers' economic condition is very

[Prof. M.S. Swaminathan]

bad. In fact, if the Economic Survey fulfils the first requirement of the National Policy for Farmers, namely, that we measure progress in farming by the increase in the net income of the farmer, if you see, it will be in the negative. This is why we recommended a minimum support price of C2 plus 50 per cent, 50 per cent margin over the cost of production. I am sure, just as our recommendation for 4 per cent interest has been met—earlier it was 7 per cent, now it has come down to 4 per cent—this too would be met. We want to fulfill the obligations of the Food Security Bill. There is no way except making farming economically viable. If we do not make it viable, there will be nobody in farming.

Sir, the second point about the Food Security Bill is the importance of attracting youth in farming. The President, in his Address, has rightly emphasized, 'that the youth constitute our greatest national asset', these are his words, and majority of youth are in villages. It is well known now; all surveys have shown that they are not interested in farming any more because farming is neither intellectually stimulating nor economically rewarding. It is very uncertain; droughts, floods and so on. Therefore, how do we make farming economically attractive and intellectually stimulating? I would suggest one thing; I won't go into details because of lack of time. We have started a Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana. In the same way, I think, we should start a 'Yuvak Kisan Sashaktikaran Pariyojana, and the components can be worked out. But, I think, it is important to look at the special needs of young farmers to have intellectual satisfaction as well as economic satisfaction.

The third aspect of the Food Security Bill, if you want to fulfil the obligations of the Food Security Bill, over a period of time, is that there has to be a pan-political commitment to the food security of the nation. The pan-political commitment can come only through this. We have suggested a National Food Security Authority, chaired by the Prime Minister, with leaders of all the main parties in Parliament as well as certain Chief Ministers from deficit States and surplus States. Unless there is a political oversight and a political commitment on a continuing basis, on a pan-political basis, again, we will find, after a couple of years, the fulfilment of the obligations for the Food Security Bill will be somewhat difficult.

May I also mention two other aspects before I close? I referred to the importance of procurement, procurement at a reasonable price.I am very happy that the Address

of the President says that the Direct Benefit Transfer System will not be a substitute for public services, and will be complementary to the Public Distribution System. I applaud the Direct Benefit Transfer System in many areas, but not in the case of foodgrains cash. Not cash but foodgrains must be provided. The reason is, not only foodgrains will ensure the objectives of the Food Security Bill but will also ensure that there is a continuing interest among farmers to produce more. If public procurement goes down at a minimum support price, production will go down. You can take it from me; procurement and production are very strongly and closely related. The wheat and rice story is only because of our procurement over a period of time at a minimum support price. Therefore, I would suggest that we should not relax because once you start giving cash instead of grains, there will be relaxation of efforts to build up our storages, to procure, the whole machinery of the PDS, and so on. We should strengthen the PDS system and ensure that. The provision has been made in the Bill that the woman is the head of the household from the point of view of entitlement; it is a very important one. But we should ensure that the Direct Benefit Transfer System, as far as the food grains are concerned, must be only in the form of foodgrains.

Finally, Mr. Vice-Chairman, Sir, I was in Maharashtra, last week, in the drought-prone areas. I think, droughts, floods; these calamities, extreme calamities, are going to be much more frequent, it looks as though. Although every year our delegation goes to the Climate Conference, last year, it was at Doha, but none of those Conferences have led to a strong political commitment on the part of the industrialized countries. There is no political will to cut down their emissions and, therefore, the poor nations, the poor in all nations will be the sufferers of climate change because they have the least coping capacity. I find, the Prime Minister has eight national missions on Management of Climate Change, but one very important mission which is missing is the mission to look after the coastal areas, the problems of sea-level rise. In the coastal areas where nearly 30 per cent of our population live within 30 to 40 kilometres from the shore line, sea-level rise is one of the consequences. I would suggest that we should now go into greater details, developing a drought code for the drought-prone areas as a set of proactive measures, not reactive measures; not post-mortem, but proactive measures, particularly for water security, and also, the coastal areas where the fishing communities live. There is a great danger that once you have a sea-level rise, there will be a very large number of climate refugees

[Prof. M.S. Swaminathan]

who will have to be accommodated in other parts of the country. So, may I, Mr. Vice-Chairman, thank you for giving me the time? But let me again emphasize that these important initiatives, like the National Food Security Bill, which is a historic one, the nation should rejoice at our ability today to make a legal commitment to provide food, at the same time, our commitment to ensure that the youth of this country have an opportunity for a satisfying life; much of it has to come from agriculture.

We should retain and attract youth in farming. You will find that farming promotes job-led economic growth; most of the industry today is jobless economic growth. Therefore, farming has to be one of our major sources of employment. The Economic Survey emphasizes this. Finally, the climate change impact on all parts of the country, drought-prone areas, flood-prone areas and particularly for coastal communities requires much greater attention. Thank you very much.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you and to my Floor Leader for having given me an opportunity to participate in the Motion of Thanks to the Presidential Address.

Sir, it is the maiden Address of the hon. President, Shri Pranab Mukherjee, and as a new Member, it is also my first opportunity to go through the total 22 pages of 114 points of the Address with anxiety to know about the future dream, aspirations and prospects of the country. I know the hon. President of India, Shri Pranab Mukherjee, the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, and the Finance Minister of India, Shri P. Chidambaram are social, economical scientists of India. So, people of India were awaiting for a good Budget which will create a remarkable place in the world economy. I am sorry to say that my total aspiration has gone in vain. It is a matter of regret, I observed, that sufficient care has been taken to divert the public opinion by the Council of Ministers while approving the text Address from the serious concerns of common people like rise in food prices, multiple hike in the prices of diesel and petrol, LPG, fertilizer, etc. which enable high inflation. Sir, when the balance of payment position is under stress and decline in investment is a worry of the country, it has been addressed about Direct Benefit Transfer system as an important initiative by the Government without aiming at its proper implementation.

I remember one Sloka in Sanskrit by Chanakya, the great diplomat that "Udyamena hi Sidhyanty Karjayani na Manorathaie Nahi Suptashya Singheshya Prabisanty Mukha Marugaha."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE) in the Chair.

Sir, about 40 million people, over 75 per cent of our children, are affected by water-borne diseases every year. Medical expenditure on water-borne diseases is estimated to be Rs. 2,400 crores annually in the country. I urge upon the Government to take necessary steps to provide drinking water facilities to each primary school, secondary school, college and each Anganwadi centre throughout the country. The Planning Commission should look into it. I had visited Bhabha Atomic Research Centre in a Parliamentary Committee where I saw desalination of water purification technologies prepared by our scientists. We should adopt it.

Sir, diseases like cancer, kidney failure, heart problem, neuro problem, etc., are forcing middle class people to go to the BPL category every day in the country. We should address it. Sir, when the Motion of Thanks was moved by Shrimati Renukaji, on behalf of the Government, I hoped that being a woman she would tell us regarding Women Reservation Bill.

But it was not mentioned. It has not been addressed in point 37 and 38 of the President's Address. Though the General Elections are knocking at the door, yet she did not mention it. In my beloved State, Odisha, our late leader Biju Patnaik, for the first time, made 33 per cent reservation for women. Now, my Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has made 50 per cent reservation for women in the Panchayats and the Municipal Corporation. The Government of Odisha is giving five thousand rupees to pregnant mothers under *Mamata Yojana*. There is Mission Shakti programme to empower women. It has reached at a remarkable point.

Sir, care has been taken to divert the public opinion about the Government's failure to pass the Women Reservation Bill. At present, I observe that the Government has been put in the dock by the people for corruption and scams after scams. Even former Ministers and corporates have been put in the jails on corruption charges. The then Finance Minister observed in the White Paper on Black Money that the Government's failure to contain corruption in the system affects the poor

[Shri Rabinarayan Mohapatra]

disproportionately. At the same time, it has been stated in point 90 of the Address that the Government is committed to bringing reforms for greater transparency, probity, integrity and accountability. But the corruption is still rampant. A deal has been done to purchase VVIP helicopters from an Italian company, Augustawestland, for Rs. 3,546 crores. Out of this, Rs. 347 crores are alleged to have been paid as kickbacks. Corruption was also reported in the Commonwealth Games, 2G allotment, Adarsh Housing Society, etc. The Government has not been able to keep its promise of bringing back black money which has illegally or legally been deposited in foreign banks. The CBI Director, Shri A.P. Singh, speaking in the inauguration of the Global Programme on Anti-Corruption and Asset Recovery, said, "It is estimated that about 500 billion dollars of illegal money, belonging to India, is deposited in tax havens abroad." A large amount of Indian money is also reported to be deposited in Swiss banks. Further, as reported in The Hindu newspaper, a CD, containing names of 700 clients who have accounts in the Geneva branch of the HSBC, has been given by the Government of French to the Indian Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Your time is over. Conclude please.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA: Okay, Sir, I am concluding.

It is a matter of regret that the Address does not mention regarding bringing back black money to India, though India is facing economic slowdown. And Rs. 93,000 crores have been cut down on expenditure.

The mandate of the Constitution of India is unitary in spirit and federal in nature. Being a new Member, I observe that Ministers, while speaking on the floor of the House, are shifting their responsibilities to the States. 'Unity in diversity' is our motto. We should have anxieties to know the genesis of the problems of the country. The root cause should be identified and redressed by the Parliament, as it is the supreme body of the Constitution of India.

Sir, my State Odisha is a unique State on the east-coast of India, with its wild life reserve, lovely virgin beaches, vast mineral treasures, immense industrial potentialities, archaeological monuments and a land of rich and diverse artistic

achievements. My leader, Shri Naveen Patnaik, has been driving forward the vehicle of development for the last three consecutive terms.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA: The last decade has been a decade of change for Odisha, with formidable growth in several sectors. We have to face the challenges of the time.

It is a matter of regret that the President's Address does not mention about the Government's failure to review the Centre-State relations, as per the demands of the State. Also, there is no mention about stopping the step-motherly attitude of the Central Government towards the State of Odisha on the following matters. I am quoting a few matters, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA: Yes, Sir; I am concluding. It is a very important matter. The, Government of Odisha has asked several times the Central Government to enhance the Minimum Support Price for paddy, but it has not been enhanced. Last time, in the Railway Budget, Odisha had got Rs.723 crores, but it was reduced by Rs. 280 crores. In respect of Khurda-Bolangir railway project which is the lifeline for tribals, out of 289 kilometers, only 34 kilometers has been constructed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Mohapatra, please conclude.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA: Sir, I am concluding. I urge upon the Government to implement the idea of 'Panchayat Industry' of late leader Shri Biju Patnaik, basing upon agriculture and small-scale cottage industries throughout India to strengthen the economy and to eradicate poverty in rural India.

In view of the above matters, Renukaji, I am unable to set my mind to support the Motion of Thanks on the President's Address. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Now, Shri Ahmad Saeed Malihabadi. Malihabadiji, your allotted time is five minutes.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिमी बंगाल) : सर, आपने मुझे समय दिया, उसका बहुत शुक्रिया। हमारे सदरे मोहतरम श्री प्रणब मुखर्जी ने जो एड्रेस यहां हमारे ज्वायंट सेशन में दिया है, हम उसका खैरमकदम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, इसलिए कि यह उनका पहला खुतबा था, जिसको हमने बहुत तवज्जोह के साथ सुना। उन्होंने अपने इस खुतबे में हुकूमत के तमाम, ज्यादातर कामों का अहाता किया है, जो हो चुके हैं या जिनके बारे में करने का इरादा है। उसी के साथ उन्होंने अपने खुतबे में अकल्लीयतों के बारे में भी जिक्र किया है और यह बताया है कि यूपीए हुकूमत अकल्लीयतों के जो तलबा हैं, स्टुडेंट्स हैं, लड़के और लड़कियां, उनकी तालीमे-वज़ीफे के वास्ते एक बड़ी रक़म खर्च कर रही है। उनके हिसाब से अब तक 55 लाख स्टुडेंट्स को यह ग्रांट मिल चुकी है, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए जो रुपये स्टेट्स के अंदर, रियासतों को जा रहे हैं, वहां से एक बड़ी रक़म करोडों-करोड़ रुपए के हिसाब से वापिस आ रही है। इसमें पिछले साल भी यानी 2011-12 के हिसाब में भी 600 करोड़ रुपये रियासतों से वापिस आये थे, जो अकल्लीयतों के फ़ंड के वास्ते दिये गये थे। तो जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वह उनको नहीं पहुंच रहा है। उसी के साथ सदर साहब ने अपने खुतबे में फरमाया है कि माइनोरिटीज के लिए सितंबर, 2012 तक बैंकों से 1,72,000 करोड़ रुपये कर्ज की शक्ल में क्रेडिट में दिये गये हैं। अब यह पता नहीं है कि यह अकल्लीयतों के किस सेक्शन को पहुंचे हैं? हम यह देखते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान गिरते-गिरते तालीम और अपने इक्तिसादी हालत के लिहाज़ से दलित के लेवल पर आ गए हैं। उनकी इस हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। जो गरीबी थी, जो इफ़लास था, भुखमरी थी, जहालत, गरीबी और बीमारी थी, वह उसी तरह चल रही है। हम लोग यह समझते हैं कि जब तक मुसलमानों को भी जॉब में और तालीम में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उनको ऊपर नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए कि जो 65-66 साल का बेकलॉग लग गया है, जो यह बेकवर्डनेस पैदा हुई है उसको इस तरह की लीपापोती से पूरा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम यह उम्मीद करते थे कि सदर साहब के खुतबे में मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए भी कुछ जिक्र होगा, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है।

UPA हुकूमत के 12 सालों में मुसलमानों के लिए ऐसा कहा गया है कि उन्हें 4.5 परसेंट रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। बाद में पता चला कि यह रिज़र्वेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि सभी minorities के लिए है। अब 4.5 परसेंट रिज़र्वेशन अगर सभी minorities के लिए होगा, तो उसमें मुसलमानों को क्या हिस्सा मिलेगा? रंगनाथ मिश्र कमीशन ने 10 परसेंट रिज़र्वेशन की सिफारिश की थी, लेकिन केवल 4.5 परसेंट रिज़र्वेशन दिया गया, वह भी सारी minorities में divide कर दिया गया। यह तो एक तरह से खैरात देने की बात हो गई है। इससे तो कोई भला होने वाला नहीं है।

मैं एक और बात का ज़िक्र करना चाहता हूं और वह बहुत जरूरी है कि अक़ल्लीयतों और मुसलमानों के बारे में अगर हम सोच रहे हैं कि हम उन्हें ऊपर उठाएं, उन्हें तरक्की दें, तो वह तरक्की होना तो दूर की बात है, आज हालत यह है कि हमारी जेलों के अंदर जो majority है, वह मुसलमानों की है। कैदी बरसों से जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और इन कैदियों के representations, इनकी, नुमाइंदगी खुद सदर साहब के सामने रखी गई थी। ऐसा हुआ है कि 14-14 सालों तक एक-एक मुलज़िम को अंदर रखा गया है और फिर वह अदालत से बेक़सूर बरी कर दिया गया है। आज यह हालत हो रही है। तो उनको रिज़र्वेशन भी नहीं देंगे, उनकी तालीम भी नहीं होगी, उनका कल्याण भी नहीं होगा और उन्हें जेलों में सड़ाया जाएगा। अगर यह मैसेज जाएगा, तो देश की तरक्की कैसे हो सकती है?

हम यह उम्मीद कर रहे थे कि सदर साहब के खुतबे में इन बातों का भी कुछ ज़िक्र होगा, ताकि अक़ल्लीयतों के अंदर जो बेचैनी फैली हुई है, वह कुछ कम हो सके। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। लोग 65-66 सालों से इंतज़ार कर रहे थे और अब हालत यह हो गई है कि उनके अंदर sense of insecurity पैदा हो गई है।

इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि मुल्क की हिफाज़त होनी चाहिए और आतंकवाद बंद होना चाहिए, लेकिन हर आदमी इस बात को मानता है कि यह जो terrorism है, इसका न कोई धर्म है और न इसे किसी community के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर किसी community के मुताल्लिक इसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब उसका बाकायदा contradiction भी करते हैं और उस पर इज़हारे-अफसोस भी करते हैं। हम खुश हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्हें करना भी चाहिए था। उनका पहला बयान गलत था और उन्होंने अपने बयान को सही किया, तो ठीक किया है, लेकिन मुसलमानों के बारे में देश भर में जो message जा रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसका कोई न कोई हल होना चाहिए। अगर यह नहीं होगा, तो हम जो कुछ भी उनके development के लिए, उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, वह होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी यह दरख्वास्त है कि सदर साहब ने जो कुछ फरमाया है, वह तो अपनी जगह पर है और हम उनका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, लेकिन यह policy matter है...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Malihabadi Saheb, your time is over. Please conclude.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी : हम लोग यह दरख्वास्त करते हैं कि इन मामलात पर गौर किया जाए और अक़ल्लीयतों के फलाहो-बहबूद के कामों को संजीदगी के साथ लिया जाए तथा जो उनकी शिकायतें हैं, वे दूर की जाएं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

جناب احمد سعید ملیح آبادی (مغربی بنگال): سر، آپ نے مجھے سمے دیا، اس کا بہت شکریہ۔ ہمارے صدر محترم، شری پرنب مکھرجی نے جو ایڈریس یہاں ہمارے جوائنٹ سیشن میں دیا ہے، ہم اس کا خیرمقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ یہ ان کا پہلا خطبہ تھا، جس کو ہم نے بہت توجہ کے ساتھہ سنا۔ انہوں نے اپنے اس خطبے میں حکومت کے تمام، زیادہ تر کاموں کا احاطہ کیا ہے، جو ہو چکے ہیں یا جن کے بارے میں کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی کے ساتھہ انہوں نے اپنے خطبے میں اقلیتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یو۔پی۔اے۔ حکومت، اقلیتوں کے جو طلباء ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان کے تعلیمی وظیفے کے واسطے ایک بڑی رقم خرچ کر رہی ہے۔ ان کے حساب سے اب تک 55 لاکھہ اسٹوڈینٹس کو یہ گرانٹ مل چکی ہے، لیکن ہم یہ دیکھہ رہے ہیں کہ مائنارٹیز کے لئے جو روپے اسٹیٹس کے اندر، ریاستوں کو جا رہے ہیں، وہاں سے ایک بڑی رقم کروڑوں-کروڑ روپے کے حساب سے واپس آ رہی ہے۔ اس میں پچھلے سال بھی یعنی 12-2011 کے حساب میں بھی 600 کروڑ روپے ریاستوں سے واپس ائے تھے، جو اقلیتوں کے فنڈ کے واسطے دئے گئے تھے۔ تو جو فائدہ پہنچنا چاہئے، وہ ان کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اسی کے ساتھہ صدر صاحب نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ مائنارٹیز کے لئے ستمبر، 2012 تک بینکوں سے 1،72،000 کروڑ روپے قرض کی شکل میں کریڈٹ میں دئے گئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اقلیتوں کے کس سیکشن کو پہنچے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان گرتے گرتے تعلیمی اور اور اپنے اقتصادی حالت کے لحاظ سے دلت کے لیول پر آ گئے ہیں۔ ان کی اس

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

حالت میں کوئی بھی سدھار نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو غریبی تھی، جو افلاس تھا، بھکمری تھی، جہالت، غریبی اور بیماری تھی، وہ اسی طرح چل رہی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کو بھی جاب میں اور تعلیم میں ریزرویشن نہیں دیا جائے گا، ان کے اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اس لئے کہ جو 66-65 سال کا بیک-لاگ لگ گیا ہے، جو یہ بیک-ورڈ نیس پیدا ہوئی ہے اس کو اس طرح کی لیپاپوتی سے پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ امید کرتے تھے کہ صدر صاحب کے خطبے میں مسلمانوں کے ریزرویشن کے لئے بھی کچھ ذکر ہوگا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یو پی اے حکومت کے بارہ سالوں میں مسلمانوں کے لئے ایسا کہا گیا کہ انہیں 4.5 پرسینٹ ریزرویشن دیا جارہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ریزرویشن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے، بلکہ سبھی مائنارٹیز کے لئے ہے۔ اب 4.5 پرسینٹ ریزرویشن اگر سبھی مائنارٹیز کے لئے ہوگا، تو اس میں مسلمانوں کو کیا حصہ ملے گا؟ رنگ ناتھ مشرا کمیشن نے دس پرسینٹ ریزرویشن کی سفارش کی تھی، لیکن صرف 4.5 ریزرویشن دیا گیا، وہ بھی ساری مائنارٹیز میں تقسیم کردیا گیا۔ یہ تو ایک طرح سے خیرات دینے کی بات ہوگئی ہے۔ اس سے تو کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔

میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے کہ اقلیتوں اور مسلمانوں کے بارے میں اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انہیں اوپر اٹھائیں، انہیں ترقی دیں، تو وہ ترقی ہونا تو دور کی بات ہے، آج حالت یہ ہے کہ ہماری جیلوں کے اندر جو میجارٹی ہے، وہ مسلمانوں کی ہے، قیدی برسوں سے جیلوں کے اندر سڑرہے ہیں اور ان قیدیوں کےrepresentations ، ان کی نمائندگی خود صدر

صاحب کے سامنے رکھی گئی تھی۔ ایسا ہوا ہے کہ 14-14 سالوں تک ایک ایک ملزم کو اندر رکھا گیا ہے اور پھر وہ عدالت سے بے قصور بری کردیا گیا ہے۔ آج یہ حالت ہورہی ہے۔ تو ان کو ریزرویشن بھی نہیں دیں گے، ان کی تعلیم بھی نہیں ہوگی، ان کا کلیان بھی نہیں ہوگا اور انہیں جیلوں میں سڑایا جائے گے۔ اگر یہ میسیج جائے گا، تو دیش کی ترقی کیسے ہوسکتی ہے؟

ہم یہ امید کررہے تھے کہ صدر صاحب کے خطبے میں ان باتوں کا بھی کچھ ذکر ہوگا، تاکہ اقلیتوں کے اندر جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، وہ کچھ کم ہوسکے۔ اب پانی سر سے اوپر جاچکا ہے۔ لوگ 66-65 سالوں سے انتظار کررہے تھے اور اب حالت یہ ہوگئی ہے کہ ان کے اندر sence of insecurity پیدا ہوگئی ہے۔

اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ملک کی حفاظت ہونی چاہئے اور آتنک واد بند ہونا چاہئے، لیکن ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا نہ کوئی دھرم ہے اور نہ اسے کسی کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ اگر کسی کمیونٹی کے متعلق اسے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر ہمارے ہوم منسٹر صاحب اس کا باقاعدہ contradiction بھی کرتے ہیں اور اس پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، انہیں کرنا بھی چاہئے تھا۔ ان کا پہلا بیان غلط تھا اور انہوں نے اپنے بیان کو صحیح کیا، تو ٹھیک کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں دیش بھر جو میسیج جارہا ہے، جس طرح سے گرفتاریاں ہورہی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہئے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، تو ہم جو کچھ بھی ان کی ترقی کے لئے، ان کی بھلائی کے لئے سوچ رہے ہیں، وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لئے میری یہ درخواست ہے کہ صدر صاحب نے جو کچھ فرمایا،

وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرنے جارہے ہیں، لیکن یہ policy matterہے...مداخلت....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Malihabadi Saheb, your time is over. Please conclude.

جناب احمد سعید ملیح آبادی : ہم لوگ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان معاملات پر غور کیا جائے اور اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے کاموں کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اور جو ان کی شکایتیں ہیں، وہ دور کی جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

''ختم شد''

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Next is, Mr. Palvai Govardhan Reddy. It is your maiden speech. But, still, try to finish in 15-20 minutes' time. I think, you have to speak in Telugu.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, generally, there is no limit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): I know. But there is an allotment like that. That is a request. That is a request only.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for permitting me to make my maiden speech. But, before I start my speech, I sincerely and wholeheartedly express my deep sense of gratitude to my leader, Shrimati Sonia Gandhiji, Chairperson, UPA, the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji and the Vice-President of my Party, Shri Rahul Gandhiji, who have reposed a great faith in me by nominating me to this august House.

At the outset, I express my thanks to hon. President for his Address to both Houses of Parliament. The hon. President has rightly said that an aspirational India is emerging, an India that is demanding more opportunities, greater choices, better infrastructure and enhanced safety and security, particularly to women and children.

It is precisely the goal of the UPA Government, which has been striving relentlessly to do everything possible to achieve the above objects with inclusiveness. It has

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

[Shri Palvai Govardhan Reddy]

achieved a substantial portion of the goals set but still, a lot more is to be achieved in order to make *Bharat* a world power.

Sir, the mover of the Motion and others form the Treasury Benches have spoken at length about the various programmes and policies of the UPA Government. I am not touching them, but I wish to bring some important points relating to my State to the notice of the Government for its consideration.

Sir, I shall first deal with irrigation projects in Andhra Pradesh. Water is one of the most important gifts of nature to mankind and so, we must use it prudently and optimally. It is precisely with this objective that various Governments take up various projects and schemes to preserve water for irrigation, drinking, industry and various other uses. Every Government must make every possible effort, with rational thinking, before constructing dams, barrages, etc. Sir, Godavari is called *Dakshin Ganga*. The State Government had, in 2004, decided to construct a dam over this river at Polavaram, without looking into the positive and negative aspects of it. This project had been under consideration for over 70 years, but ultimately, our four CWC Chairmen, as also other experts, said that there was no foundation there and therefore, it should not be constructed. The upstream States of Odisha and Chhattisgarh had objected to the project, saying that hundreds of tribal villages would be submerged with the Polavaram Dam. It was precisely due to this reason that the final environmental clearance was not given by the Ministry of Environment, and it had directed to stop the project on 8th February, 2011. Now, there is no way that Odisha and Chhattisgarh would give their approval to go ahead with the construction of the Polavaram Dam with the present design. We had bitter experience with Odisha in the Vamsadhara, Stage-II and Jhanjavathi projects, which have been languishing for the last 25 years, even after spending hundreds of crores of rupees. So, there is a need to look at alternative designs so that the State could reap the benefits and irrigate 7.2 lakh acres. But, actually, out of these, 3.5 lakh acres are being cultivated under various projects. And, unnecessarily, Government has been putting off this project, the production of 960 megawatts of hydro-power and additional use of 45 TMC of Krishna waters in Telangana and Rayalaseema. That is also false. It is with the objective of reaping the above benefits that an expert like Shri T. Hanumantha Rao, former Engineer-in-Chief of the Government of Andhra Pradesh and Consultant with the United Nations, has prepared an alternative design, without sacrificing any

of the benefits that would accrue due to the dam design. This design does not change the design of any canal which is now under construction. The original aim was to store 75 TMC water in one dam, but the alternative design would store the same amount of water at three places with low barrages. For the people of Andhra Pradesh, the alternative design would not only save agricultural areas of about two lakh acres of tribal lands from submersion and two lakh tribals from being vacated, but would also facilitate gravity-flow irrigation for the same area through the proposed barrages. This would benefit the backward tribal areas of Telangana immensely.

It also provides navigation of sea-going vessels upto 3000 tonnes capacity of ships as opposed to a few tonnes capacity of launches and boats through a tunnel designed to the alternative design.

*Fazal Ali Commission recommended that separate Telangana State should be created, and all the projects which are at different levels of execution should be suspended. But unfortunately, Government of Andhra Pradesh did not implement those suggestions and consequently we lost Krishna waters. Later, Nagarjuna Sagar Dam was constructed with a view to supply 132 TMCs of water equally through left and right canals, so that there can be uniform cultivation.

Ultimately, what is happening? Only 6 lakh acres developed in Telangana and 18 lakh acres developed in Andhra area. Therefore, I feel that this Andhra Pradesh Government is not doing anything for irrigation in Telangana area. Therefore, people of Telangana are agitating that in Andhra Pradesh...

That's why people of Telangana feel that they cannot develop as long as they are part of Andhra Pradesh. For last 50 years we are waiting for Government's decision to develop Telangana. Telangana is located between Krishna and Godavari rivers. Telangana has 57% catchment area, even then the waters of Krishna and Godavari are not being supplied to Telangana. The ongoing projects are causing huge damage to Telangana region. As per Bachavat Tribunal's judgement, there should be a barrage at Polavaram and a major dam near Itchampalli. But there are no further projects built. Apart from Sri Ram Sagar project, Telangana region do not have any major irrigation project.

The intention behind constructing Polavaram Dam is to benefit Andhra region and deprive Telangana region from the waters of Godavari. Polavaram Dam would

---

*English version of the original speech made in Telugu.

[Shri Palvai Govardhan Reddy]

result in flooding of thousands of acres, which would disturb our environment. Two lakh tribals would be displaced. We have an act that when there is mass displacement of tribals, Government of India's permission is mandatory. But, the officers misled the Government and got the required permissions. Two ministers reversed those environmental clearances and finally Government of India ordered to stop that project. Even then the Government of Andhra Pradesh is going ahead with the construction of the project. They are not considering construction of barrages which would be more beneficial. Shri Hanumantha Rao, a technical expert and an advisor suggested that 11 barrages should be constructed over river Godavari. By doing so, vessels of 3000 tonne capacity can reach Shri Ram Sagar project. The State Government did not consider any of these suggestions. I approached CWC officials on two occasions and explained to them elaborately about this project. They said that this issue should be considered by the State Government. In that case, why we have CWC? It is like a post office?

The CWC has to play its own role. If there is any alternative proposal, they have to suggest it to the State Government to implement it. Now, there is no permission for Polavaram dam, but still, the Government is going ahead with tendering. Every year, they call tenders two times and then cancel them. Original cost was Rs. 6,000 crores for Polavaram dam. Now, it has gone upto Rs. 36,000 crores. Therefore, the dam is unnecessary. Only barrages have to be constructed. With only Rs. 12,500 crores, the barrages will be completed. Not only that, Sir, actually, there is no irrigation facility. Krishna delta is there; Godavari delta is there and there are so many projects. But, Telangana is suffering from lack of projects. Therefore, people have now agitated in a bigger way. They feel that Telangana is the only answer because without Telangana, in Andhra Pradesh, we cannot achieve much because we are minority in Andhra Pradesh. Therefore, they will not care for us even in Legislative Assembly or outside. That is why, Andhra politicians and even officials are doing injustice to Telangana people and our officers are also not treated properly. Therefore, there was a big agitation for Telangana in 1956. When Fazal Ali Commission came, these people represented their views. Later on, in 1969, there was a big agitation. In that agitation, 370 people died. After that,...

The agitation was continued further and it is there for last 50 years. And people of Telangana would agiate for another 50 years to achieve separate Telangana State.

The people of Telangana do not want to live in Andhra Pradesh and they want Telangana at any cost. The Government of India should understand the aspirations of Telangana and should create separate Telangana State at the earliest.

Sir, I have to mention one thing here. When you have maximum possible flood flow of 50 lakh TMC of water, there is every possibility of breach of Polavaram with original design. This has been substantiated by IIT, Roorkie as well.

This report was not submitted to CWC and CWC did not study the project thoroughly. By going ahead with this project, it would result in damage to the Godavari dam. That's why I request the Government of India to look into this issue.

The Government of India should take initiative because it may be a State subject, but...

We should see to what extent it is useful. People of Telangana are into serious agitation, the Government should take note of this. The States Reorganization Commission went into this matter in great detail and concluded in Para 386 of its Report, and, I quote: "After taking all these factors into consideration, we have come to the conclusion that it will be in the interests of Andhra as well as Telangana, if for the present, the Telangana area is to be constituted into a separate State, which may be known as the Hyderabad State with provision for its unification with Andhra after the general elections likely to be held in or about 1961, if by a two-thirds majority, the legislature of the residual Hyderabad State expresses itself in favour of such unification."

Thus, the SRC recommended the State Assembly to decide about the merger after general elections. Regarding safeguards, assurances and guarantees to Telangana from the Andhra leaders,which the Andhra leaders proposed in case of merger of Telangana, the SRC said categorically: "We have carefully gone into the details of the arrangements, which may be made on these lines. It seems to us, however, that neither guarantees on the lines of Sri Bagh Pact nor Constitutional devices will prove workable or meet the requirements of Telangana. Anything short of supervision by the Central Government over the measures intended to meet the special needs of Telangana will be found ineffective and we are not disposed to suggest any such arrangement in regard to Telangana.

The way in which they made promises and assurances, none of them were fulfilled.

[Shri Palvai Govardhan Reddy]

In such a scenario. I do not understand how people of Telangana would live with people of Andhra region.

In 1969, there was a major agitation for de-merger, which brought the region to a stop. I am a witness to that as I had participated in the agitation and went to jail along with Dr. M. Chenna Reddy and other politicians. Police firing resulted in an estimated 379 young persons being killed. It got so bad that they Army was called in. In the 1971 General Elections, the Telangana Praja Samithi (TPS) won 11 out of 14 Telangana Parliamentary seats.

Even after clear mandate given by people of Telangana, it is unfortunate that Government of India did not respond.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Reddy, you have already taken twenty minutes.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, this is my maiden speech. The House is aware of the history behind the demand for a separate State of Telangana. It is sufficient to refer to the Gentlemen's Agreement of 1956 and the amendment of Article 371(1) of the Constitution, the Six Point Formula of 1973, and, the introduction of Article 371D in the Constitution. All these failed to protect interests of Telangana. Therefore, now, at least, the Government of India assured in 2009 that Telangana process would start. That was on the birthday of late Shrimati Indira ji also. Therefore, the promise of the Government of India should be honoured.

As announced in the President's Address to both Houses in June, 2004, the process of consultation was started. In 2005, before the Pranab Mukherjee Committee, the following eminent national leaders including former Prime Ministers...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude now.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Former Prime Ministers supported the cause of statehood for Telengana in writing. They are Shri Chandrasekhar, Shri V.P. Singh, Shri H.D. Deve Gowda and Shri I.K. Gujaral, all former Prime Ministers, and Shri Sharad Pawar, Shri Lalu Yadav, Behen Km. Mayawati and Shri Prakash Singh Badal. Therefore, all political parties in the country are agreeing to create

Telengana. Rich industrialists, contractors and builders have grabbed the entire land in Hyderabad and around Hyderabad. They are influencing the Government of India not to form the Telengana State. I will say no more. The hon. Home Minister is the key person, trying to untangle the Telengana statehood issue. I know that he has put in his best efforts. I know his heart is in the right place. This decision was arrived at through a democratic process and inter-party consultations. No one expects perfect unanimity – no political decision is without opposition from vested interests.

I expect him and the Government of India to implement the historic decision of December 9, 2009. The credit for the final decision goes to my leader, Shrimati Sonia Gandhi, on whose birthday the announcement was made about Telengana State. I have total confidence that my leader, Madam Sonia Gandhi, will ensure that this decision will be implemented quickly.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: One minute, Sir. I have only one request to make. When leaders of all political parties are supporting creation of Telangana State, the Government of India should consider this demand. With these words I conclude. Thank you. Jai hind.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Bhagat Singh Koshyari.

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड) : उपसभापति जी धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद में जो अभिभाषण दिया गया है, मैं उनके प्रति पूरे आदर के भाव, पूरे सम्मान के भाव के बाद भी उनसे अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभिभाषण को सुनने के बाद यदि आप उसको गहराई से पढ़ें तो भाषण में राष्ट्रपति जी ने बार-बार मेरी सरकार कहा है, पर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रपति जी की सरकार का नहीं, बल्कि मनमोहन जी की सरकार का बयान है। मैं यह आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, जाने-माने व्यक्ति हैं, राजनेता हैं और मुझे लग रहा था कि वे इस बार राष्ट्रपति का जो अभिभाषण पढ़ेंगे, उससे निश्चित रूप से कुछ ऐसी दिशा देंगे, कुछ ऐसी इग्नाइटिंग, इन्सपाइरिंग चीजें बोलेंगे, जिसके माध्यम से पूरे देश को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि राष्ट्रपति जी, जैसा कि उधर से हमारे एक माननीय वक्ता उनको कांग्रेस के, यूपीए के राष्ट्रपति बोल रहे थे, तो मैं कह दूं कि राष्ट्रपति केवल यूपीए या कांग्रेस के राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वे पूरे राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं और कम-से-कम वर्तमान

5.00 P.M.

[श्री भगत सिंह कोश्यारी]

महामहिम से तो मैं कह ही सकता हूं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसके माध्यम से मुझे कुछ लग रहा था कि वे हमारे सामने इस प्रकार की अच्छी बात या मार्गदर्शन रखेंगे। मुझे ऐसा लगा, चाहे तो आप उनके पहले से लेकर 114 पैराग्राफ तक पढ़ लीजिए, इनमें शायद केवल दूसरे पैराग्राफ में, जहां पर उन्होंने युवकों को थोड़ा महत्व दिया है, युवा शक्ति को महत्व दिया है, उसको छोड़ दें, उसके अलावा यदि आप कहीं देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि महामहिम हमसे कुछ कहने जा रहे हैं...। हमसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। वे हमसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वे हमसे कोई शब्द बोलें और उस पर सारा राष्ट्र न्योछावर हो जाए, क्योंकि वे राष्ट्रपति हैं। अगर उनकी बात पर सारा राष्ट्र न्योछावर न हो, तो वे राष्ट्रपति किसलिए हैं? इसलिए कुल मिला कर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं-न-कहीं मनमोहन सिंह जी का भाषण पढ़ दिया।

जहां तक युवाओं की बात है, अच्छी बात है, उन्होंने युवाओं के लिए उद्‌बोधक बात कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं का अर्थ यह नहीं होता है। जिनके बाल-बच्चे हैं, वे जानते होंगे कि हमारे यहां बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको कंधे पर रखते हैं और कहते हैं कि बच्चा, देख, मुन्ना, बेटा, तू कितना बड़ा हो गया है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन युवाओं की ओर संकेत है, जिनको कुछ लोग कंधों पर रख कर कह रहे हैं कि देखो भाई, अब तू कितना बड़ा हो गया, दो साल पहले तू इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा।

अब मैं राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण को पढ़ रहा हूं, जो गणतंत्र दिवस पर उनका भाषण था। मुझे लग रहा था कि वास्तव में देश का राष्ट्रपति बोल रहा है। मैं पूरा अंश नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसका एक अंश पढ़ रहा हूं। "क्या सामर्थ्यवान लालच में पड़ कर अपना धर्म भूल चुके हैं? क्या सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर भ्रष्टाचार हावी हो गया है?" उनका और भी भाषण है, मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता। मैंने ये दो बातें इसलिए कही कि वास्तव में राष्ट्रपति जी ने जैसा अभिभाषण गणतंत्र दिवसपर दिया था, आज आखिर जब वे संसद में सदस्यों के सामने बोल रहे थे, सेंट्रल हॉल में बोल रहे थे, तो मैं सोचता हूं कि उनका जो सेंट्रल, फोकस प्वायंट होना चाहिए था, that should have been corruption, that should have been नैतिकता, ethics. लेकिन ऐसा लगता है कि जो बना-बनाया भाषण आया, उस भाषण में राष्ट्रपति जी आज जो समाज की आवश्यकता है, जो हमारी जरूरत है, उस सबको भूल गए हैं।

मैं अंत में इस बिन्दु पर जाऊंगा, पर मैं आपसे प्रारंभ में एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं सब बिन्दुओं पर इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारी सहयोगी सदस्या,

स्मृति जी हमारी ओर से बोल चुके हैं और माननीय सदस्यों ने सारी बातों के ऊपर, गरीबी से लेकर आदिवासी तक, सभी बातों के ऊपर बातें रखी हैं। मैं उन पर ध्यान न देते हुए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति इस देश के सर्वोच्च सेनापति भी हैं। वे केवल राष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्र की सेना के सर्वोच्च सेनापति हैं। मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो सीमान्त है, वह सीमान्त कितना त्रस्त है। मैं सोचता हूं कि हमारे वित्त राज्य मंत्री, मीणा जी यहां पर हैं, तो वे ध्यान देंगे कि हमको उधर कितना ध्यान देना है। यहां पर सौभाग्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी भी बैठे हैं। हमारी स्थिति क्या है? मैं बुमला, अरुणाचल प्रदेश की अन्तिम सीमा से लेकर इधर जम्मू-कश्मीर के चुशूल तक गया हूं। उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मैंने देखा है कि आज वहां कितनी कठिनाई है। हमारे सैनिकों को कितना कठिन लगता है। मैं, मेरे साथी राजीव जी और दो-तीन साथी वहां दौरे पर गए थे। वहां के सैनिक कितने खुश हुए, वहां के लोग कितने खुश हुए, वे चिपक पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे यहां आप लोग आ गए। मैं यह अपेक्षा करता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं ऐसी योजना बनाई गई है कि हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसदगण उस दूरस्थ क्षेत्र में जाएं और हम सैनिकों का उत्साह बढ़ाएं? सैनिकों का उत्साह बढ़ाना तो छोड़ो, अगर एक सैनिक की गर्दन कट जाती है, हमारा पड़ोसी छीन कर ले जाता है, तो हम उस पर उफ नहीं करते हैं। ऐसी उपेक्षा! जो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, वह राष्ट्र समृद्ध भी नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्र समृद्ध भी होगा और अगर वह सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्र कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके उत्तर में बोलें, तो वे हमें आश्वासन दें। वास्तव में आज मुझे जब सीमा पर जाना पड़ता है, परिवहन मंत्री जी, समझ लीजिए, तो मुझे 5-5 दिन पैदल चल कर जाना पड़ता है। अब वे सुन ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं? माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी, अगर आप थोड़ा सुन लेंगे, तो अच्छा रहेगा। अगर मंत्रीगण ही नहीं सुनेंगे, तो यह ठीक नहीं है। मैं यहां पर इसलिए यह बात कह रहा हूं, नहीं तो मैं कहता भी नहीं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, समय कम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आखिर आज 5-5 दिन पैदल चल कर वहां जाना पड़ता है। Can you go to Barahoti? क्या आपने कभी यह नाम सुना है? हम लोग वहां 5 दिन पैदल चल कर गए हैं। सीमा पर, आप चाहे अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, अगर दो-तीन सड़कों को छोड़ दीजिए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप सिक्किम चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप जम्मू-कश्मीर चले जाइए, हमको पैदल जाना पड़ता है। दस-दस दिन तक पैदल चल कर हम उस सीमा तक पहुंचते हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि क्या उस सीमा तक हम कभी सड़क पहुंचा पाएंगे? पहुंचा पाएंगे तो किस गति से पहुंचा पाएंगे? आज चीन ने उनके हर एक दर्रे तक अपनी सड़क बना ली है। चीन हमारी सीमा तक रेलवे लाइन लेकर आ रहा है और उसने वहां हवाई अड्डे भी बना दिए हैं।

[श्री भगत सिंह कोश्यारी]

मान्यवर, मैं जब चसूल में था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि 1962 से पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में यहां विमान से उतरे थे। आज वह क्षेत्र इस प्रकार से ध्वस्त और अस्त-व्यस्त है कि आप उसको संभाल नहीं सकते। हमारी यात्रा के दौरान मुझे मालूम हुआ कि आपने कोशिश भी की और उसको थोड़ा ठीक भी कर दिया, लेकिन जब हमारी सरकार ने उसे ठीक करने की कोशिश की तो पड़ोसी चीन कहता है कि अगर आप यहां बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारी क्या स्थिति है कि पड़ोसी चीन की वजह से, जो दुनिया में हमारा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहलाता था, उस हवाई अड्डे पर हमारा विमान नहीं उतर सकता है। क्यों नहीं उतर सकता? क्यों हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसे वहां उतारें? इस तरह तो हमारी सीमाएं असुरक्षित होंगी, क्योंकि चाइना की ओर से पूरी रेलवे लाइन आ चुकी है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी एक संसदीय समिति ने सैनिकों के सभी अध्यक्षों और प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों को बुला कर कहा कि सीमा पर रेल जानी चाहिए। उन लोगों ने पांच रेलवे लाइनों के लिए रिकमेंड किया है, योजना आयोग ने भी इसके लिए रिकमेंड किया है, लेकिन उनका कहना है कि रेल मंत्रालय कहता है कि आखिर ये रेलवे लाइनें बनेंगी कैसे? माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, अगर हमारे अंदर ज़रा भी राष्ट्र भक्ति होती तो ऐसा न कहा जाता। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ऊधमपुर से लेकर काजीगुंडा, श्रीनगर और बारामूला तक इस योजना को राष्ट्रीय योजना बनाया। That was declared as national project. सारा का सारा खर्च वित्त मंत्रालय से गया। आखिर आज हमारी इन रेलवे लाइनों को क्यों नहीं देखा जा रहा? अरुणाचल में रेल जानी है, इसके लिए उन्होंने संस्तुति भी की है, सिक्किम में रेल जानी है, उत्तराखंड में रेल जानी है, इसके लिए कौन काम करेगा? अगर हम सीमाओं पर रेल का जाल नहीं बिछाएंगे, सड़कों का जाल नहीं बिछाएंगे, वहां अपने एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम किसी भी हालत में कभी भी अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकेंगे।

उपसभापति जी, मेरा आपसे एक और निवेदन है। हमारी कमेटी के द्वारा "One Rank One Pension" की बात की गई। राष्ट्रपति जी ने भी उसका उल्लेख किया है। 13 लाख भूतपूर्व सैनिक इससे प्रभावित थे। हमारी समिति के रिकमेंडेशन के बाद यह कार्य हुआ। पहले उनको जो सहायता दी गई, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। राष्ट्रपति जी ने इसकी बहुत तारीफ की है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह दिन अब जल्दी आना चाहिए जब सैनिकों को "One Rank One Pension" का हक दिया जाए। यह उनके 13 लाख भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड है, जो जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। वे हमारे देश के रक्षक हैं। अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह देश कैसे सुरक्षित रहेगा।

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बंगलादेश का वर्णन है, साथ ही दूसरे अन्य पड़ोसी देशों का वर्णन भी है। इस बार हमारे राष्ट्रपति जी पहली बार बंगलादेश गए। इस बात के लिए सबसे अधिक खुश होने वाला व्यक्ति शायद मैं ही था, क्योंकि हरेक राष्ट्रपति यह सोचता है कि पहले मैं इंग्लैंड जाऊं, अमरीका जाऊं या कहीं और जाऊं। उन्होंने पहली बार अच्छी कोशिश की और वे पड़ोसी देश बंगलादेश में गए। यह उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि बंगलादेशी भी हमारे ही ब्लड ग्रुप के हैं। हम सब एक ही हैं, हमारी एक ही भाषा है...**(व्यवधान)**... यह दूसरी बात है कि वह ससुराल गए, यह बहुत अच्छी बात है, यह बात मुझे भी मालूम है। असली बात यह है कि वह बंगलादेश गए। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके सारे अभिभाषण में नेपाल का वर्णन कहीं भी नहीं आया। क्या हम नेपाल को इतना उपेक्षित मान कर चलते हैं? नेपाल इस समय एक टर्मोइल से गुजर रहा है, संकट के दौर से गुजर रहा है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्या हम सब लोग, जो नेपाल के लोग हैं...**(व्यवधान)**... देखिए सर, या तो मैं बोलूंगा या मंत्री जी बोलें। I will stop speaking. या तो आप उन्हीं को बुलवा लीजिए, वे ही बोलें...**(व्यवधान)**... ऐसे मैं नहीं बोल सकता...**(व्यवधान)**... Sir, if the Minister does not want to hear my speech, then why is he sitting here? He should listen to me.

श्री उपसभापति : आप बोलिए, बोलिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन यह है कि नेपाल की समस्या का भी समाधान होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वहां इंटरफेयर करिए, लेकिन नेपाल को क्या आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, उन लोगों का किस प्रकार सहयोग करना चाहिए, यह आपको अवश्य देखना चाहिए। आखिर नेपाल और हम एक ही ब्लडग्रुप के लोग हैं, हम सब एक ही हैं, उनका और हमारा रिश्ता बराबर है।

मेरा निवेदन यह है कि नेपाल के बारे में हमारी चिन्ता क्यों नहीं होती है? नेपाल में जल्द-से-जल्द अच्छा शासन आए, वहां सुशासन आए, इस पर हम सब लोग क्यों नहीं उस दृष्टि से प्रयास करते हैं? मेरा आपसे अनुरोध यह है कि अगर हम लोगों ने नेपाल को इस प्रकार से असुरक्षित रखा, अगर नेपाल पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें प्राइऑरिटी के साथ नेपाल के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं बार-बार नेपाल जाता हूं और वहां के प्रधानमंत्री और वहां के लोगों से मिलता हूं। इसके साथ-साथ मैं वहां के विरोधी दल के नेताओं से भी मिलता हूं। वे सब यह कहते हैं कि चाहे हमारी पार्टी के लोग भारत विरोधी नारे लगाते होंगे, परन्तु हम आशा करते हैं, तो केवल और केवल भारत से आशा करते हैं। जोशी जी, एक तरफ जहां वे भारत से आशा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेपाल की ओर से उनकी सीमा तक जहां हमारी सड़क नहीं पहुंची है, वहां चाइना ने उनकी सड़क बना दी है। आखिर ऐसा कैसे होगा? जब हम उस ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे महत्व नहीं देंगे, तो हमारा काम कैसे होगा? इसलिए,

[श्री भगत सिंह कोश्यारी]

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हम कम-से-कम इस दृष्टि से कोशिश करें कि हम सब लोग नेपाल की ओर भी कुछ ध्यान दें, जो कि हमारा पड़ोसी है, जो आज संकट के दौर से गुजर रहा है और जहां आज संक्रमण काल चल रहा है। आज हमसे उसकी मित्रता है, लेकिन यदि नेपाल हमारे हाथ से खिसक गया, तो मेरे ख्याल से देश के लिए यह एक बहुत बड़ी कठिनाई की बात होगी।

मान्यवर, यहां इस बात की बड़ी चर्चा की गई कि हमने खाद्यान्न में काफी उन्नति कर ली और पूरे अभिभाषण में एक ही जगह पर लिखा है कि अगर हम गर्व कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर पर कर सकते हैं। मैं केवल आप ही से निवेदन नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम लोग भी यहां बैठे हैं और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने इस बात की रिपोर्ट पढ़ी है कि एक अध्ययन के मुताबिक इस देश में 56 हजार करोड़ रुपये का अनाज केवल भंडारण के अभाव में प्रतिवर्ष बर्बाद होता है। आखिर क्या हम सब यहां इसकी चिन्ता नहीं कर सकते, क्या हम इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? इस देश के अन्दर किसान जो अन्न पैदा कर रहा है, जिस एक-एक दाने के लिए गरीब आदमी ललच रहा है, क्या उस अन्न को हम बर्बाद हो जाने देंगे? अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि हम इतने लाख टन अनाज विदेश भेजेंगे। आप उसे विदेश भेजिए, हमें उसमें कोई कष्ट नहीं है। अगर ऐसी आवश्यकता है और उससे हमारा लाभ होता है, तो उसे भेजिए, मैं इसमें कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि उस अनाज का हम भंडारण नहीं कर सकते, इसलिए उसे विदेश भेज देंगे और अपनी महिलाओं के लिए संरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे, इसलिए विदेश भेज देंगे, यह कोई तर्क नहीं होता है। इसके लिए एक तर्क होना चाहिए था, एक दृष्टि होनी चाहिए थी। आखिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एनडीए सरकार ने कहा कि हम गांव-गांव तक सड़क पहुंचाएंगे। कैसे सड़क पहुंची? यह अलग बात है कि जोशी साहब उतनी स्पीड से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यह पहुंचनी चाहिए। मैं यह बात निन्दा के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है, वह काफी नहीं है। मैं आज जहां कहीं भी जाता हूं, चाहे वह चेन्नई हो, कोलकाता हो, वहां लोग हमको कहते हैं कि अच्छा, आप तो खंडूरी जी के यहां से हैं न? उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। यह सुन कर मुझे अच्छा लगता है कि आखिर उस कालखंड में बहुत अच्छा काम हुआ। मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी कुछ स्पीड पकड़ें। मैं उनकी निन्दा नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके आप उसी प्रकार से काम कीजिए, लेकिन इस सरकार में क्या होगा? इस सरकार ने तो सुरक्षा के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का बजट कम कर दिया, उसने शिक्षा में कम कर दिया, स्वास्थ्य में कम कर दिया और सड़क-परिवहन में भी कम कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 में इस सरकार को ही कम कर देना चाहिए, तो शायद बजट बढ़ेगा। आज क्या ऐसी स्थिति आ गयी है कि बजट में इतना अंतर हो गया? कल हमारे विशेषज्ञ लोग

बोल रहे थे कि आपने 2012-13 के बजट में इसको 90-95 हजार करोड़ कम कर दिया और आपने कहा कि हां, हम तो बहुत अच्छा सरप्लस ला रहे हैं। क्या ऐसे काम चलेगा? मेरा आपसे निवेदन है कि आज हमें एक साथ मिल कर यह सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें। यह केवल मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि स्वयं से भी कह रहा हूं, हमारे यहां के जो लोग हैं, उनसे भी कह रहा हूं कि आज हमको कहीं न कहीं यह बात सोचनी होगी। आखिर आज हमारे मन में यह बात क्यों नहीं आती है कि राष्ट्र पहले है? आखिर यह भाव कौन जगाएगा? उस गुलामी के कालखंड में जब एक विवेकानन्द शिकागो में जाकर धर्मध्वजा फहरा सकते हैं, एक महात्मा गांधी फकीर बन कर सारे देश को अपने साथ ले सकते हैं, तो आज हममें से कोई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम देश को एक साथ लेकर चलें? मुझे कल बड़ा अजीब लगा जब मैंने किसी अखबार में यह पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम तो वफा करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं आप वफा करना चाहते हैं, जफा करना चाहते हैं या सफा करना चाहते हैं?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी बोले, तो वास्तव में इस देश को कैसे साथ लाया जा सकता है, कैसे सारे देश को एक साथ लेकर चला जा सकता है, कैसे हम देश के अंदर फिर से चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, इस संबंध में बोले। अगर हमने प्रखर राष्ट्र भक्ति नहीं की, तो जिस प्रकार 16 दिसंबर की दिल्ली की दर्दनाक घटना है, जिसका कि आज अमेरिका में संज्ञान लिया जा रहा है, इस तरह की घटना को नहीं रोका जा सकता है। रात-दिन दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में नैतिकता का पाठ होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में यह क्यों नहीं आया कि हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए? जब आप अपने युवकों को बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह के दो लड़के सामने-सामने चुनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला, जब आप बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह के दो लड़के शहीद हो गए, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण में, नांदेड़ में जाकर अपना बलिदान दे दिया, जब आप ऐसे उदाहरण रखेंगे, लक्ष्मीबाई का उदाहरण रखेंगे, सरदार पटेल का उदाहरण रखेंगे, सुभाष चन्द्र बोस का उदाहरण रखेंगे, तब ऐसा होगा। हमको तो ऐसा लगता है कि हम तो अपने गांधी जी को भी भूल गए। लगता है कि लोग गांधी जी को नहीं, बल्कि कोई और गांधी को याद करने लगे हैं। उस गांधी जी को याद कीजिए, जो "रघुपति राघव राजा राम" बोलता था। उसने "रघुपति राघव राजा राम" के मंत्र से सारे देश को एक कर लिया था। आखिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं, जब कि हम सब के अंदर एक ऐसी इच्छा हो, मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को चुनौती दे दी। जब विपक्ष आपको चुनौती दे, तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सत्ता में होकर चुनौती देने लगे, तो इसका एक महत्व है? जो ताकतवर है, वह तो वैसे ही चुनौती दे देगा, परन्तु अगर विपक्ष चुनौती दे, तो बात समझ में आती है। आपको तो कहना चाहिए था कि हम एक हैं, हम एक दिशा में चलेंगे,

[श्री भगत सिंह कोश्यारी]

एक साथ मिल कर सब लोग चलेंगे। मैं कभी एक-आध बार टीवी के सामने बैठता हूं, उसमें एक बड़ा विज्ञापन आता है कि जो तेरा है, वह मेरा है, जो मेरा है, वह तेरा है। एक विज्ञापन "जो तेरा है, वह मेरा है, जो मेरा है, वह तेरा है" देकर कोई कंपनी सारे देश में अपना सामान बिकवा सकता है, अगर यही भाव हमारे प्रधानमंत्री जी लाते कि जो तेरा है, वह मेरा है, जो मेरा है, वह तेरा है, तो मैं समझता हूं कि यह देश कहां का कहां पहुंच जाता, लेकिन आज हमारे अंदर यह भाव है ही नहीं, इसलिए मैं विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अब समय आ गया है कि हम इधर-उधर भटकने, एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने, अपना गुणगान करने के बजाए अपने अंदर यह भाव लाएं। यह सारे दुनिया को नहीं लगना चाहिए कि हम भटक रहे हैं, हम दिशाहीन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा होना चाहिए, जिसके माध्यम से भविष्य में हम लोग एक नई दिशा में चलें, वरना तो यह कहना पड़ेगा,

"तू इधर-उधर की बात न कर,
यह बता कि कारवां क्यों लुट गया।"

सब लोग यही पूछेंगे कि कारवां क्यों लुट गया? मेरा अनुरोध है कि कारवां को लुटने मत दीजिए, इस देश को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं फिर से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर असहमति व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Resolution on the Vote of Thanks to hon. President of the country, who delivered the message about the State of affairs of the Union the other day. Mr. Deputy Chairman, Sir, I am conscious of the time. I will try to stick to it. The point at issue is, I have heard friends from both sides of the House passionately espousing one cause or the other with great feeling and passion and I admire some of the issues that have been raised. But the point that has not been discussed, that we are all responsible during 2011 and 2012 as Members of this august House for the number of working days we lost by not allowing the House to function. I think we are as much responsible for the sad State of the economy as we point the fingers towards other people. We don't realise how serious the global economy is and how closely we are tied with it and how many opportunities we have lost because we were trying to score points off each other.

The hon. President was very mild and polite, as indeed that Office requires him to be, that he didnot point out that, as a nation, we are failing ourselves, nor

did he blame-somebody or the other or some party or the other. I am afraid, the chalenges of 2013-14, the year ahead of us, are far grimmer than what we have experineced during last year. I rise to urge this House that we co-operate and we pass the Bills, we make progress as Indians rather than score political points and trying to do oneupmanship over ourselves.

I think, the challenge of equitable economic growth remains unfulfilled. We are not sesitive to the seriousness of the condition of the people who do not have a voice in this House represent a threat to our nation, because those who have been deprived for hundreds of years will refuse to remain deprived because we are inactive and we are not ready to push this country to the limits of its achievable economy.

Sir, some hon. Member raised that what this country is paying for a series of issues of corruption which crop up everyday. And, I am not talking about the headlines that we discuss in this House. But, in every walk of life, it is shameful that every common Indian has to face issues of corruption to get any job done in this country. This country is paying and each one of us is paying a heavy price for corruption which has entered the vitals of our society. And, it is not a matter that will go away easily or readily. That is going to blow holes in our ambition, in our future and unless we collectively rise and raise our voice instead of accusing each other that we need to do something about it, we will suffer, our children will suffer and our grandchildren will suffer. It is a responsibility that we all must seriously consider.

The second issue which has now come up to the surface — it was never absent; it was hidden — is the lock of safety of women and malnourishment of children. The safety of women in this country or the lack of it is one of the most shameful chapters in our history which, fortunately, has come out in the public domain. But, are we going to do something about it? Is our police force going to change? Are our Judges going to be more conscious and speedier? Is there going to be law reforms? Are we going to spend more funds towards increasing the number of courts? I don't know the answer to that. The hon. President has raised these and several other issues. But, I did not see us responding to what has happened in the past. There is very little we can do about it. But, what is it that we are going to do in the coming months, in the coming year, because we will never be pardoned by history if we continue to score points on each other and remain mute spectators, rather than act as leaders to change the fortunes of this country.

[Dr. Ashok S. Ganguly]

Our economic climate will continue to be challenging. We have to rise above it. Our farmers have demonstrated how they can do it. Our industrial leaders will have to show it. Our political leaders will have to lead.

Mr. Chairman, I know that we are running out of time. I don't want you to point it out to me. I am very conscious of the fact. I am very grateful for the opportunity and I convey my respects to all the Members of the House for permitting me to speak. But, I cannot sit down without expressing my sadness that I don't see the light at the end of the tunnel. I am, normally, an optimistic person. I will continue to be optimistic. But, I want that optimism to infect all of us, rather than myself alone.

I thank you Mr. Deputy Chairman once again.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Gangulyji, I must thank you. You always meticulously adhere to the time and make your points within that time. Thank you. This is the example to be followed by others also.

Now, Shri Biswajit Daimary. You follow the good example of Gangulyji.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो भी बातें कही हैं, उसका वहां अच्छी तरह reflection रिप्लाई हुआ है। यह हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मुझे इसके ऊपर विस्तार से कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहां कुछ छोटी-छोटी समस्याओं को आपके जरिए दृष्टि में लाना चाहता हूं, स्पेशली नॉर्थ-ईस्ट की समस्याओं को लेकर। यहां पर जिनती भी बातें कही गई हैं, उनसे नॉर्थ-ईस्ट की समस्या हल नहीं होने वाली हैं। नॉर्थ-ईस्ट की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार की एक स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए। आज आप सब लोग जानते हैं, मैं हाऊस में बतलाना चाहता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट के लोग बहुत सालों से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर, अपना मुद्दा उठाते रहे हैं और इसके लिए संग्राम भी हो रहा है। यह संग्राम आज भयानक रूप भी ले रहा है। आज नॉर्थ-ईस्ट का जो सारा जनसमुदाय है, वे लोग हाथ में हथियार लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके कारण नॉर्थ-ईस्ट में आज सारे आम लोग शांति से जी नहीं पा रहे हैं। समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था जब तक भारत सरकार की तरफ से नहीं होगी, तब तक नॉर्थ-ईस्ट में शांति नहीं होगी। यह नॉर्थ-ईस्ट के बहुत समुदायों के साथ बात हो रही है, जो कि उग्रवादी भी हैं। जैसे, नागालैंड की जो समस्या है, NSCN (1-M) के साथ सालों से बात हो रही है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या का हल करने

के लिए सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसका हल निकालना चाहिए। आज असम में उल्फा के साथ बात चल रही है। लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ बात करते रहने से नहीं होगा। उल्फा के साथ जो समस्या है या जो मुद्दा उठाया गया है, इस पर बात करके समस्या का हल निकालने की जरूरत है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFB के साथ भी बात हो रही है। लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेघालय में ANVC जो गारो का उग्रवादी संगठन है, उन लोगों के साथ भी बात हो रही है। वहां के लोग गारोलैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। वहां की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो डिस्कशन हो रहा है, इसको जल्दी समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। आज वहां की जो हालत है, उसे आप महसूस नहीं कर सकते हैं। सारे उग्रवादी संगठन सीजफायर करते हुए वहां डेजिनेटेड कैम्प में बैठे हुए हैं। वे लोग के डेजिनेटेड कैम्प के बाहर खुलेआम आर्म्स लेकर घूमते हैं और वहां की पब्लिक को उनके बीच में ही रहकर अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। सीजफायर होते हुए जो लोग डेजिनेटेड कैम्प में हैं, वे लोग कभी-कभी एक्सटोर्शन के काम में लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और भारत सरकार को इस समस्या का जितना जल्दी हो सके, समाधान करना चाहिए। 2003 में बोडो लिबरेशन टाइगर के साथ एक समझौता हुआ था और इसमें असम के जो karbi anglong और एन.सी. हिल्स में रहने वाले जो बोरो लोग हैं, उन लोगों को पहाड़िया जनजाति की मर्यादा देने की बात थी। आज दस साल गुजर गए लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया है। मैंने सदन में इस बारे में प्रश्न भी उठाया था, जिसके जबाव में बतलाया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शैड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से क्लीयरेंस आनी है, एक कमेटी आई है, जिसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन सालों के बाद नेशनल कमीशन फॉर शैड्यूल्ड ट्राइब्स में यह मुद्दा अभी भी पड़ा हुआ है। आज भी इसके जबाव में Ministry of Tribal Affairs न यही बताया कि मुझे पता नहीं। क्या सरकार या उसका कोई ऑफिसर सालों साल ऐसे मामलों की फाइल अपनी टेबल पर रखे रखता है और इसके हल के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी कदम बढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता? आज इसी कारण असम में फिर से बंद हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, वहां ट्रेनें रोकी जा रही हैं। कहीं-कहीं इसको लेकर हंगामा हो रहा है। वहां पुलिस फायरिंग चल रही है। तो इन सारी चीजों का इसके साथ एक संबंध है।

मैं चाहता हूं कि सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके, इस समस्या का समाधान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सर, नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं बहुत छोटी-छोटी हैं, अगर भारत सरकार चाहे तो बहुत कम दिनों में इनका समाधान कर सकती है। इसके लिए समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी उग्रवादी संगठन को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी ऑर्गनाइजेशन को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मंत्रालय की ओर से कोई अधिकारी जाकर उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्था करेगा, तो वहां कोई आंदोलन नहीं होगा और किसी उग्रवादी की बात को

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

वहां कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ सरकार की ओर से वहां कुछ व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। भारत सरकार को किसी संगठन या उग्रवादी के बोलने से ही वहां कुछ करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को खुद ही वहां के लोगों को खुश करने की चिंता करनी चाहिए और इस तरह की पॉलिसी बनाकर काम करना चाहिए। महोदय, वहां पर छोटी-छोटी बातों को लेकर कई तरह का विचार चलता है, इस कारण नॉर्थ-ईस्ट के लोग भारत की mainstream से दूर जा रहे हैं। इन्हीं छोटी-छोटी बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बन जाता है। वहां एक समय में बंगला देश में आने वाले migrants को रोकना एक मुद्दा था, जब इस समस्या का कोई हल नहीं निकला, तो वहां के लोगों ने बंदूक लेकर उल्फा ऑर्गनाइजेशन का गठन किया और 30 साल से असम में यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। महोदय, बोडोलैंड का मुद्दा सिर्फ गुवाहाटी में ट्राइबल्स के लिए हॉस्टल बनाने की डिमांड को लेकर था, लेकिन वह न देने के कारण separate State के नाम पर लोग अस्त्र उठाकर हंगामा करा रहे हैं और आज भी यह समस्या बनी हुई है। ऐसी समस्याओं के समाधान की जरूरत है।

महोदय, इसका भी कारण है। वहां शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर आप वहां के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उन्हें हर समय इसी तरह से जीने को मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिए, अगर हम सेंट्रल की ओर से कोई इंडस्ट्री खोलते हैं, कोई ऑफिस वहां खोलते हैं, तो वहां साथ में सेंट्रल स्कूल बना देते हैं, लेकिन वहां के भारतीय लोगों के लिए हम न कभी सेंट्रल स्कूल खोलने या कोई दूसरा स्कूल खोलने के बारे में चिंता करते हैं जिस कारण वहां के लोग पढ़ाई में पीछे रह गए हैं। महोदय, मैं आपके जरिए इस हाउस में एक बात बताना चाहूंगा। कोकराझार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। आज तीन साल हो गए हैं, लेकिन बोडो लैंड के इस कॉलेज में सिर्फ एक ही बोडो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इसका कारण है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो entrance examination या स्टेट लेवल पर जो entrance examination होता है, उसमें वहां के छात्र मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उनके गांव के स्कूल में पढ़ाई की जो व्यवस्था है, टीचर्स की जो क्वालिटी है, लोगों के घर के जो हालात हैं, उनका जो परिवेश है, वह बहुत बुरा है, इस कारण उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। वे मेरिट में ऊपर नहीं आ पाते हैं। दूसरे, वहां की local language की पढ़ाई के कारण वे लोग अंग्रेजी में जबाव नहीं दे पाते हैं, उस competition में भाग नहीं ले पाते हैं और दिल्ली में भी रहकर वे लोग compete नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग specially इन बातों की चिंता नहीं करेंगे तो उन लोगों का स्तर कभी भी ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। महोदय, वहां की सारी बातें sensitive हैं।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा। महोदय, भारत सरकार के मंत्रिमंडल में नॉर्थ-ईस्ट का एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। वहां के लोगों का विचार है कि नॉर्थ-ईस्ट के आदमी को इंडिया, की constitutional post पर क्यों बिठाएगा? क्या नॉर्थ-ईस्ट के लोगों में ऐसी योग्यता

नहीं है, जोकि कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन ले सके? हम उसे independent charge दे सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का दर्जा नहीं दे सकते। आज देश के बारे में अगर कोई decision कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है, तो उसमें भाग लेने के लिए, सुनने के लिए या नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बताने के लिए कोई नहीं है। अगर आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को कैबिनेट मिनिस्टर के हिसाब से उसे एडवांस कॉपी मिलती, तो नॉर्थ-ईस्ट का व्यक्ति बोल सकता था कि इसमें यह समस्या भी highlighted कर दीजिए ताकि एक मैसेज नॉर्थ-ईस्ट के लोगों में जाए। वहां यह समस्या भी है, यह हमारी feeling है। कोई कह सकता है कि भारतीय मंत्री देगा, नहीं देगा, उससे असम का क्या संबंध है? मैं कहता हूं कि संबंध है और इसे लेकर भी वहां के लोग सोचते हैं और अपने को negligent feel करते हैं। महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार इन छोटी-छोटी बातों पर विचार करेगी और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएगी। इसके साथ ही मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति : श्री प्यारीमोहन महापात्र — absent. श्री राजीव शुक्ल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल) : उपसभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि हमारे अन्य सदस्य बोलने के लिए तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन कल नेता विपक्ष के भाषण से मुझे कहीं न कहीं आशा की किरण दिखाई दी और वह आशा की किरण दिखाई दी संसदीय लोकतंत्र में कुछ मुद्दों पर आम सहमति की। चूंकि ताली दोनों तरफ से बजती है, इसलिए कुछ चीजों पर मेरा मानना है कि अगर विपक्ष की तरफ से भी कुछ सुझाव आएं तो हमें उन्हें जोश-गरमी से स्वीकार करना चाहिए। माननीय राम गोपाल जी ने कई बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं।

महोदय, सिर्फ यही मान लेना कि अगर हमारी आलोचना होती है तो वह हमारे ऊपर तोहमत है और इसलिए हम आलोचना पर आक्रोश व्यक्त करें और नाराज हों, ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसको हम उस ढंग से लें कि एक अच्छा सुझाव है और रचनात्मक सुझाव है तो दोनों तरफ से बहुत काम हो सकते हैं। मैं दोनों तरफ बैठ कर देख चुका हूं। उधर का धर्म होता है कि आलोचना करना वरना उसे विपक्ष नहीं कहा सकता और इधर का धर्म होता है आलोचना सुनना वरना सत्तारूढ़ दल में होने का कोई मतलब नहीं होता और बीच के लोगों का धर्म होता है मुद्दों के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना। इस ढंग से संसदीय लोकतंत्र, संसदीय परंपरा चलती है।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : बीच का क्या मतलब होता है? जैसा आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष और बीच वाले, तो यह बीच क्या होता है?

श्री राजीव शुक्ल : बीच का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, अग्रवाल साहब की बात में काफी वजन है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल : देखिए, कुछ ऐसे दल होते हैं, जो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर सरकार को समर्थन देते हैं, वे बीच की तरफ होते हैं। स्वयं नेता विपक्ष ने कहा कि एक सिनिसिज़म का माहौल है। सिनिसिज़म का माहौल कहां से पैदा होता है? हम जब कहीं अपने निर्णयों को लेते वक्त चूक जाते हैं, अपनी बात को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते। मुझे याद है जब डा. मनमोहन सिंह जी उधर बैठते थे, प्रणब मुखर्जी जी वहां बैठते थे जहां रवि शंकर जी बैठे हैं, हम लोग पीछे बैठते थे, तो उस वक्त जो आर्थिक सुधार के मुद्दे आते थे, उनको ये दोनों समर्थन करते थे। आर्थिक सुधार के मुद्दों पर कभी संसद में इस तरह की बात नहीं होती थी कि हाउस सात-सात दिन नहीं चल रहा है। कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सब में सहमति हो जाती थी। उस दिन नेता विपक्ष का जो भाषण था, उसके आधार पर मैं इस बात से आशान्वित हूं कि कुछ मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आर्थिक विकास की दर नीचे गिर रही है और यह सही भी है। आज विश्व स्तर पर जो माहौल है, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं चाहे देश के अंदर हों या बाहर हों, उसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ रहा है और यह हमारे लिए चिंता की बात है। मैं योजना आयोग में बैठ कर देखता हूं, 80 बिलियन डॉलर का करंट एकाउंट में डेफिसिट है। तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वह घटता चला जा रहा है और 55 बिलियन डॉलर तो सिर्फ सोना खरीदने में चला गया। लोग सोना बहुत खरीद रहे हैं। अब वह सोना महिलाओं के इस्तेमाल के लिए खरीद हो रहा है या लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यह देखने की बात है। वित्त मंत्रालय को इस बात पर तेजी से गौर करना चाहिए कि इतना सोना क्यों खरीदा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े व्यापारी सोने की ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से यह इम्पोर्ट हो रहा है? तेल के अलावा सोना खरीदने में फॉरेन एक्सचेंज का बहुत जबर्दस्त हिस्सा जा रहा है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस आर्थिक विकास की दर को हम सब मिल कर कैसे आगे ले जा सकते हैं? इसमें सभी राज्य सरकारें भी शामिल हैं, हम भी हैं और आप भी हैं। सत्ता में कौन कब तक रहता है, कोई नहीं जानता। सबको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है, तो समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वहीं से फिर वक्तव्य की टोन बदलने लगती है। इसलिए इस स्थिति में, जैसा नेता विपक्ष ने कहा और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है, अगर मिलजुल कर तमाम ऐसे बिल जो इकनॉमिक सुधार के, आर्थिक सुधार के हैं, उनमें सहयोग करें और उनमें अगर सुझाव आते हैं तो उनको शामिल करें और जहां हमारे प्रावधान ठीक नहीं हैं वे बदलें और जो विपक्ष के सही सुझाव हैं उनको मानें, इस तरह से आम सहमति से कई बिल

निकल सकते हैं। मेरा विपक्ष से आग्रह है कि इस काम में मदद करे। इस तरह से हम बहुत कुछ एचीव कर सकते हैं।

अभी साल-डेढ़ साल ही तो हुआ है, जब ओबामा ने आकर कहा था कि यह देश प्रसिद्ध हो चुका है, India has emerged, इतना ज़बर्दस्त भाषण उन्होंने दिया था। अब एक साल में ही क्या हो गया कि आर्थिक विकास की दर यहां पहुंच गई, आप सब लोग कहने लगे कि एकदम से हालत खराब हो गई है। इसकी क्या वजह है? पिछले एक-डेढ़ साल में अंतर्राष्ट्रीय माहौल में फर्क पड़ा है और ईमानदारी से कहें तो हमारे यहां भी कुछ ऐसी चीजें हुईं, जिनकी वजह से माहौल बदला। चाहे वह 2G का judgment हो, चाहे CAG को लेकर कई प्रकरण उठे हों। केन्द्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और देश की बदनामी, इन दोनों चीजों में एक बड़ी पतली रेखा है। आरोप लग गए, ठीक है, कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ देश की कितनी बदनामी हो जाती है! बाद में पता चलता है कि आरोप साबित नहीं हो पाया, लेकिन तब तक देश को लगता है कि यह भ्रष्ट देश है। हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा है। हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें और आपको मिलकर एक फैसला लेना पड़ेगा, चाहे आप सत्ता में हों, चाहे हम सत्ता में हों, कि CAG का हमें क्या करना है? CAG की रिपोर्ट, Public Accounts Committee में जाती है, उसी आधार पर होना चाहिए, या CAG की रिपोर्ट गीता-पुराण है, इसे पहले दिन से ही मान लेना चाहिए? इसमें भी सर्वसम्मति से सारी विधान सभाएं निर्णय ले लें और संसद भी तय कर ले कि CAG की रिपोर्ट का क्या होना चाहिए? क्या वह पहले दिन से ही scandal है या PAC के through आने के बाद उसको scandal मानना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उसके observations सही हैं? इस पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि राज्यों के खिलाफ भी आता है। फिर वहां की राज्य सरकारें यह कहती हैं, चाहे वे कांग्रेस की राज्य सरकारें हों या दूसरी राज्य सरकारें हों, कि नहीं, हम CAG की रिपोर्ट तब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारी सार्वजनिक वित्तीय समिति अपना निर्णय नहीं देती है। तो एक खेल के दो मापदंड नहीं हो सकते हैं, एक गेम के दो रूल्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह तय कर लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या सहमति बननी चाहिए, क्या यह पहले दिन से ही scandal है? अगर सभी लोग तैयार हैं, तो पहले दिन से ही इसे scandal मान लेते हैं। अगर सभी लोग कहते हैं कि नहीं, यह PAC के through आना चाहिए और सही है या गलत, इसका पता लगाने के बाद मानना चाहिए, तो केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों तक, सभी पर वह लागू होना चाहिए। वरना यह भी पूरे विश्व में cynicism पैदा करता है, माहौल खराब करता है। आप यह जान लीजिए कि इंडिया की खबर विदेशों में खूब छपती है। यहां अगर पत्ता भी हिलता है, तो वह खबर विदेश में छपती है और अब यह वह भारत नहीं है, जिसकी coverage नहीं होती है। जो यहां छपता है, मैं बाहर विदेश में था, मैं देख रहा था कि दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था, पूरे विश्व में उसकी ज़बर्दस्त publicity हुई थी और बाहर के अखबारों से ऐसा लग रहा था कि India is a rape country. तो publicity हर चीज की होती है। आज यह नहीं है कि बाहर वाले हमें

[श्री राजीव शुक्ल]

नहीं देख रहे हैं, सभी लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें मुद्दों को चुनते वक्त देखना चाहिए।

दूसरी चीज़ यह है कि किसी भी मुद्दे को हम आपके खिलाफ उठाएं, आपकी राज्य सरकारों के खिलाफ उठाएं, आप हमारे खिलाफ उठाएं, लेकिन हमें उनके तथ्यों को भी देखना चाहिए, वरना यह जो माहौल है, इसमें सबसे पहले किसी राजनीतिक आदमी को दोषी ठहराने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। सिस्टम में बैठकर जो गड़बड़ी करते हैं, वे protected रहते हैं, वे मज़े में रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति है, सबसे पहले लोग उसी का सिर पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उसकी आलोचना करके, जब तक वह हट नहीं जाता, तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। जहां राजनीतिक व्यक्ति हट गया, फिर सबको उस आरोप से कोई मतलब नहीं है, सब चुप हो जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 20-25 सालों से ऐसा हो रहा है कि जहां राजनीतिक व्यक्ति शहीद हो गया, उसका इस्तीफा हो गया, इसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। आखिर हम राजनीतिक व्यक्तियों की गरिमा कब तक और कितनी बनाएंगे और इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए।

माननीय नेता विपक्ष ने low cost manufacturing की बात कही थी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा idea है और निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। अगर हम इंडिया को low cost manufacturing hub बनाते हैं, तो इससे हमें रोज़गार बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और इसके साथ-साथ हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वही theory, वही concept है, लेकिन इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। यह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, यह स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। चाहे बिजली का मसला हो, चाहे credit tax का मसला हो, क्योंकि आज एक आदमी इंडिस्ट्री लगाता है, तो 10 agencies उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सबको बैठकर, मिल-जुलकर तय करनी पड़ेंगी और यह संसदीय लोकतंत्र में ही संभव है हम मिल-जुलकर इस चीज़ को करें, तभी काम बन पाता है। जैसे Food Security Bill की बात है। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस बारे में अच्छा काम किया है, तो हमें उनके model को देखना चाहिए कि आखिर वह क्या है, कैसे हम उसको national model में incorporate कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि छत्तीसगढ़ में दूसरे दल की सरकार है, इसलिए हम उस पर ऐतराज़ करें, हम यह माहौल नहीं चाहते।

आपके ideas भी हम लें और हमारे ideas आप अपनी राज्य सरकारों में लें, ऐसे मिल-जुलकर ही काम हो सकता है।

महोदय, राम गोपाल जी ने गंगा-यमुना की बात की। यह सच है कि आज हमारी नादियों की हालत इतनी खराब है कि देखा ही नहीं जाता है। आप गंगा और यमुना, दो महान नदियों के पास खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनसे बहुत बदबू आती है। दूसरी नदियों का भी

ज़िक्र हुआ, नर्मदा का सब लोग ज़िक्र कर रहे हैं, क्या हो गया है? आज बैंकॉक की कई बिलियन डॉलर की कमाई, जो उसके अंदर नदी बहती है, सिर्फ उससे होती है, river tourism से होती है। इसी तरह हम अपनी नदियों को बढ़िया बना सकते हैं और इतना अच्छा बना सकते हैं कि उससे tourism के द्वारा बहुत बड़ी कमाई हो सकती है, लेकिन नदियां भी तो सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में नहीं हैं। पूरे देश में सारी फैक्टरियों का मलबा नदियों में गिरता है और इतनी राज्य सरकारें यहां से वहां तक हैं। तो सबको मिलकर यह करना पड़ेगा। आप यह जान लीजिए कि यह देश का ऐसा ट्रक है, जिसके विकास में हम सब पहिए हैं। एक पहिए के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। जब सब पहिए मिलकर काम करेंगे, तभी यह ट्रक, बस या vehicle आगे बढ़ने वाला है। अगर कुछ चीज़ों पर आम सहमति हो जाए, हम लोग मिलकर उस काम को आगे बढ़ा सकें, तो मुझे लगता है कि विकास की रफ्तार भी बढ़ सकती है और हम देश को काफी आगे ले जा सकते हैं।

महोदय, कुछ प्वाइंट्स ऐसे हैं, जिनको मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार का ज़िक्र किया, मैंने उसके बारे में बताया। लोकपाल में भी जैसे Select Committee की रिपोर्ट थी, तो Select Committee की रिपोर्ट सरकार के पास आई है। कैबिनेट उसको देखकर अपना निर्णय देगी, लेकिन इस पर भी मेरा यह कहना है कि हम जल्दबाज़ी न करें और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कानून ऐसा न बनाया जाए, दबाव में हम कोई कानून ऐसा न बना जाएं कि जिसमें किसी की भी अपनी जो आज़ादी है, privacy है, उसका हनन हो। चाहे जो भी कानून हो, एक कानून की मैं बात नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वह अपनी बात कह सके कि यह आरोप सही है या गलत है। इसलिए चिट्ठी सही लिखी या गलत लिखी, अगर उसको अपने को बचाने का एक बार भी मौका नहीं मिलेगा, तो फिर ट्रकों complaints आएंगी और सब refer होती रहेंगी। इसलिए कहीं न कहीं एक firsthand screening की बहुत जरूरत है। यह filter लगना ही चाहिए। बिना इस filter के, क्योंकि आप चुनाव लड़ते हो और आपका विरोधी आपके खिलाफ चुनाव लड़ता है। जब वह हार जाता है, तो उसका दिन भर यही काम होगा कि आपके खिलाफ complaint भेजे। लिख दिया कि आपने बीस मकान खरीदे हैं, आपका इस फैक्टरी में शेयर है, यहां से आपने पैसे ले लिए, आपके बेटे ने यह कर लिया, बेटी ने वह कर लिया, अब अगर वह सीधे जांच के लिए चला गया, तो आप इस्तीफा दें, इसलिए कहीं न कहीं एक filtering होनी चाहिए।

इसके अलावा दूसरे जो कानून बनने हैं, उनमें भी यह होना चाहिए कि हम दबाव में, pressure में, जल्दी-जल्दी में कोई ऐसा कानून न बना जाएं, क्योंकि जो कानून बनता है, वह सौ साल के लिए बनता है। उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, इसलिए ये बातें समझना राजनीतिक सर्वानुमति से ही संभव है।

महोदय, जी.एस.टी. और एन.सी.टी.सी. का मसला है, दोनों में कुछ मुद्दों पर विवाद हैं। अच्छी बात है कि सरकार और राजनीतिक दलों में कुछ बातचीत हो रही है और अगर इनमें

[श्री राजीव शुक्ल]

से सर्वानुमति निकल सके, कुछ प्रावधान जिन पर राज्यों को आपत्ति है, वे हट जाएं और केंद्र जिनको चाहती है, उनको रखे, अगर ये दोनों सुलझ जाएं, तो राष्ट्र के लिए आतंकवाद को रोकने में और दूसरे आर्थिक विकास की दर बढ़ाने में निश्चित रूप से बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

महोदय, इसके अलावा जैसे "आधार" कार्ड है, उस पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। "आधार" कार्ड एक पहचान कार्ड है, जिसका फायदा हर राज्य सरकार ले सकती है। यह पहचान का एक बहुत बड़ा काम है, अगर यह एक बार हो गया, तो इससे कम-से-कम "रामलाल" "रामलाल" हैं और "श्यामलाल" "श्यामलाल" हैं, यह तो पूरे देश में तय हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा काम है और अगर सबके सहयोग से यह हो सके, तो उसका बहुत बड़ा फायदा सबको मिल सकता है, क्योंकि हर योजना के लिए पैसा केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकारें भी देती हैं। मैं तो यह मानता हूं कि जो राज्य सरकारें हैं, वहां केंद्र सरकार जो पैसा देती है, यह सचमुच निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए। हर मुख्य मंत्री यह कोशिश करता है कि लोगों की मदद के लिए पैसा पहुंचे। हर प्रधानमंत्री कोशिश करता है कि पैसा पहुंचे, लेकिन actual तक नहीं पहुंचता है। गालियां हम सब लोग खाते हैं, जो मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री, होते हैं, उनको लोग हटा भी देते हैं, लेकिन वे दिन भर system को defend करते हैं, चाहे पार्लियामेंट में question-answer हों, चाहे Assembly में question-answer हों, क्योंकि उनकी सरकार होती है, इसलिए वे दिन भर उन्हीं को defend करते रहते हैं कि नहीं, गलत नहीं हुआ है, जबकि निचले स्तर तक वह चीज़ पहुंच नहीं पाती है। अगर पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिले और पूरे देश की तस्वीर बदल जाए। Rural development के लिए जितना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पिछले साठ सालों में दिया है, अगर वह सचमुच खर्च होता, तो भारत के गांव सोने के होते। अमेरिका, इंग्लैंड के गांव ऐसे नहीं होते, अगर actual में वह खर्च हो गया होता। तो यह सब हमें मिलकर करना पड़ेगा और इसके लिए न हम कहीं आपके खिलाफ हैं, न आप हमारे खिलाफ हैं। जब तक हम आपस में टकराते रहते हैं और हर चीज़ की आलोचना और आरोप-प्रत्यारोप करते रहते हैं...

सिस्टम के लोग उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप लड़ेंगे तो अल्टीमेटली हमें डिफेंड करेंगे और जिसकी सरकार होगी, हमारा पक्ष लेगी क्योंकि उसके कार्यकाल में हुआ। हम चुनाव के लिए प्वाइंट स्कोर कर लेते हैं कि मैंने इनके खिलाफ बोलकर यह माहौल बन दिया और इनको हरा दिया, लेकिन अल्टीमेटली वह नुकसान पूरे देश का, समाज का और हम सबका होता है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि इस माहौल में, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण आया है, इस संसदीय लोकतंत्र में अगर कुछ मुद्दों पर राजनैतिक सर्वानुमति हो सके तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा फायदा देश को मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to make an announcement.